

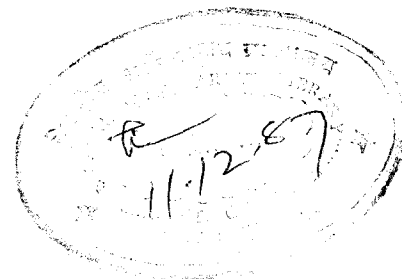


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 402]
No. 402]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 1987/श्रावण 15, 1909
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 1987/SRAVANA 15, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

गृह मंत्रालय
(राष्ट्रीय सुरक्षक अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1987

सा. का. नि. 688 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षक
अधिनियम, 1986 (1986 का 47) की धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

राष्ट्रीय सुरक्षक नियम, 1987

अध्याय I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना :

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सुरक्षक नियम, 1987 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (3) ये नियम, उन सभी व्यक्तियों को जो अधिनियम के अधीन हैं
लागू होंगे।

परन्तु इसके अध्याय IV के उपबन्ध ऐसे व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे
जो राष्ट्रीय सुरक्षक में प्रतिनियुक्ति पर हैं ;

परन्तु और कि इसके अध्याय IX और X के उपबन्ध समरी सुरक्षक
न्यायालय द्वारा विचारण को, जहाँ तक वे समरी सुरक्षक न्यायालय से
संबंधित अध्याय XI में अन्तर्विष्ट किन्हीं उपबन्धों से असंगत हैं, लागू नहीं
होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा
अपेक्षित न हो—

- (क) “अधिनियम” से राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 (1986
का 47) अभिप्रेत है ;
- (ख) “परिशिष्ट” से इन नियमों से उपाबद्ध परिशिष्ट अभिप्रेत है ;
- (ग) “न्यायालय” से सुरक्षक न्यायालय अभिप्रेत है ;
- (घ) “टुकड़ी” के अन्तर्गत सुरक्षक के किसी ग्रुप या यूनिट का कोई
ऐसा भाग है जिससे मुख्यालय से दूर इपुटी पर जाने की अपेक्षा
की गई है या आदेश दिया गया है ;
- (ङ) “समुचित सुरक्षक प्राधिकारी” से जब इसका प्रयोग किसी
शक्ति, कार्य, कार्य या विषय के संबंध में किया जाए, ऐसा

सुरक्षक प्राधिकारी अभिप्रेत है जो अधिनियम के अधीन बनाए गए इन नियमों में अनुसरण में उस शक्ति का प्रयोग करता है या कार्य का पालन करता है या उस विषय से संबद्ध है ;

(घ) "धारा" में अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(छ) उन अन्य सभी शब्दों और पदों के जो नियमों में प्रयुक्त हैं और जो परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ;

3. रिपोर्ट और आवेदन :—ऐसी कोई रिपोर्ट या आवेदन जो इन नियमों द्वारा किसी बरिष्ठ प्राधिकारी को किया जाना अपेक्षित है या जो अन्यथा किसी बरिष्ठ प्राधिकारी को किया जाना है, निम्नित रूप में और उचित प्रणाली से किया जाएगा ।

4. परिशिष्टों के प्रारूप : (1) परिशिष्टों में उपबर्णित प्रश्न, ऐसे परिवर्तनों के साथ, जो प्रत्येक मामले में परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हों, उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं, और यदि उनका प्रयोग किया जाता है तो वह पर्याप्त होंगे, किन्तु इन प्रश्नों से से विचलन केवल विचलन के कारण किसी आरोप, वारंट, आवेदन, कार्य-वाही या इन नियमों में गुप्तगत किसी अन्य दस्तावेज को, अधिधिमाम्य नहीं होगा ;

(2) ऐसे किसी प्रश्न का कोई लोप, केवल ऐसे लोप किए जाने के कारण ही, किसी कार्य या बात को अधिधिमाम्य नहीं बनाएगा ।

(3) टिप्पणों में दिए गए निवेशों और प्रश्न में दिए गए अनुदेशों का ऐसे सभी मामलों में, जिससे के संबंधित हैं, सम्यक् रूप से अनुपालन किया जाएगा, किन्तु टिप्पणों या अनुदेशों में दिए गए ऐसे किसी निदेश के अनुपालन में कोई लोप, केवल ऐसे लोप के कारण, किसी कार्य या बात को अधिधिमाम्य नहीं बनाएगा ।

5. सुरक्षक के किसी पदवारक में निहित शक्ति का प्रयोग किया जाना—सुरक्षक में कोई पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के प्रति या समक्ष किसी कार्य या बात को करने के लिए दी गई किसी शक्ति या अधिकारिता का, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, प्रयोग किसी अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो तत्समय सुरक्षक के नियमों और व्यवहारों के अनुसार उस पद के दायों का पालन कर रहा हो ।

6. मामले जिनके लिए उपबन्ध नहीं किया गया हो—किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिसके लिए इन नियमों में विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया हो, सक्षम प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी बात या ऐसी कार्यवाही करे जो वह मामले की परिस्थिति के अनुसार करना उचित समझे ।

अध्याय II

भर्ती किया जाना

7. अभावता (1) वह व्यक्ति, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है या जिस का पति/पत्नी जीवित है, किसी ऐसे दशा में, जब ऐसे पति/पत्नी के जीवित रहने के दौरान ऐसा विवाह किया जान शून्य हो, विवाह करता है, सुरक्षक में नियुक्ति या नियोजन का पात्र नहीं होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है अपने पहले पति/पत्नी के जीवित रहने के दौरान, दूसरा विवाह करता है, अपने आपकी सेवा में रखे जाने के लिए अपात्र बनाएगा और अनुपयुक्तता के आधार पर उसे सेवा से पदच्युत किया जा सकता है, हटाया जा सकता है या निवृत्त किया जा सकता है ;

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाय है कि ऐसा आदेश करने के लिए पर्याप्त आधार है, किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

8. अन्य वेतनीय की अभावता—कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, केन्द्रीय सरकार की निम्नित रूप में संज्ञापित सम्पत्ति के सिवाय, सुरक्षक में नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा

परन्तु इस नियम में अन्विष्ट कोई बात नेपाय या भूतान के किसी प्राय को सुरक्षक में नियुक्ति या नियोजन में वर्जित नहीं करेगी ।

9. अधिकारियों की नियुक्ति :—केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी व्यक्तियों को, जिन्हें वह अधिकारी के रूप में उपयुक्त समझती है, सुरक्षक में निम्न-निम्नित रीति में नियुक्त कर सकेगी और उनकी सेवा की शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निम्नित बनाए गए नियमों में उपबर्णित हों :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा ;

(ख) अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा बलों, संघ के सशस्त्र बलों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग या स्वशासी निकायों से प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) प्रोन्नति द्वारा जैसा समय-समय पर विहित किया जाए ।

10. परीक्षा : (1) सुरक्षक में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी दो वर्ष के लिए परीक्षाधीन होगा और केन्द्रीय सरकार ऐसे कारणों से जो अधिलिखित किए जाएं परीक्षा की अवधि को ऐसी अवधि या अवधियों के लिए, जो दो वर्ष से अधिक की नहीं हो बढ़ा सकेगी ;

(2) केन्द्रीय सरकार, परीक्षावधि के दौरान कोई कारण बताए बिना, किसी अधिकारी की सेवा को समाप्त कर सकेगी ।

11. सहायक कमांडर, रेंजर और योधक व्यवसायी की नियुक्ति—

(1) महानिरीक्षक द्वारा सहायक कमांडर ग्रेड 1, के पदों पर उप-महानिरीक्षक, द्वारा, सहायक कमांडर ग्रेड 2 और 3 के पदों पर नियुक्तियों और रेंजर और योधक व्यवसायियों की नियुक्ति किसी रूप कमांडर या सुरक्षक के किसी अन्य ऐसे अधिकार द्वारा की जा सकेगी जिन्हें कमणः महानिरीक्षक द्वारा निम्नलिखित रीति में भर्ती अधिकारों के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा और उनकी सेवा की शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा ;

(ख) रक्षा बलों या संघ के किसी सशस्त्र बल, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग या स्वशासी निकायों से प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) प्रोन्नति द्वारा, जैसा समय-समय पर विहित किया जाए ;

(2) सहायक कमांडर, रेंजर या किसी योधक व्यवसायी के रूप में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेगा । उपनियम (1) में विहित प्राधिकारी, परीक्षा की अवधि के दौरान, कोई कारण बताए बिना, उनकी सेवाओं को समाप्त कर सकेगा ।

12. रेंजर और योधक व्यवसायियों की नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्ति का ठंग—सुरक्षक में रेंजर या योधक व्यवसायी के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति के भर्ती अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने पर, भर्ती अधिकारी, उस पद की, जिस पर उसकी नियुक्ति की जाती है, सेवा की शर्तें, उसकी उपस्थिति में रहेगा या पढ़ाएगा और उसके समक्ष स्पष्ट करेगा या स्पष्ट कराएगा और उससे नियुक्ति के प्रकार में अस्पष्ट-विष्ट ऐसे प्रश्न करेगा जो महानिरीक्षक द्वारा विहित किए जाएं और उसको इस बात की चेतावनी देने के पश्चात् कि यदि वह ऐसे किसी प्रश्न का मिथ्या उत्तर देगा तो वह अधिनियम के अधीन वर्जनीय होगा, ऐसे प्रत्येक प्रश्न के उसके उत्तर को अधिलिखित करेगा या अधिलिखित कराएगा ।

(2) यदि, उपनियम (1) के उपबन्धों का और ऐसे अन्य निषेधों का जो इस निमित्त महानिदेशक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं, अनुपालन करने के पश्चात् भर्ती आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि नियुक्त किए जाने के लिए इच्छुक व्यक्ति, उन प्रश्नों को पूर्णतः समझता है जो उससे पूछे गए हैं और सेवा की शर्तों के लिए सहमत होता है और यदि उक्त आफिसर का समाधान हो जाता है कि कोई अज्ञान नहीं है तो वह नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और ऐसे व्यक्ति के उस पर हस्ताक्षर कराएगा और तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

(3) (क) उपनियम (2) के अधीन सुरक्षक के सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञा कराया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा विहित किया जाए।

(ख) यथासंभव, अनुप्रमाणित किए जाने वाले व्यक्ति के कमानों द्वारा शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञा कराया जाएगा या कमानों की अपरिहार्य अनुपस्थिति में, इस निमित्त कमानों द्वारा निश्चित रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञा कराया जाएगा।

(ग) शपथ तभी दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञा तभी कराया जाएगा जब अनुप्रमाणित किए जाने वाले व्यक्ति ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो।

अध्याय III

संगठन

16. सुरक्षक का गठन और नियंत्रण—

(1) सुरक्षक का समावेशन और अधीक्षण का प्रयोग करते हुए महानिदेशक की सहायता और महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप-महानिरीक्षक, ग्रुप कमानों और अन्य आफिसर करेंगे।

(2) समावेशन, अनुशासन, महायान और प्रशासन के उत्तरदायित्व का—

(क) अगर महानिदेशक की दशा में सभी ग्रुपों, यूनिटों, मुख्यालयों, स्थापनों पर और उनके अधीन रखे गए सुरक्षा कर्मियों और उस क्षेत्र के भीतर जो उसे समनुदिष्ट किए जाएं, विस्तार होगा;

(ख) महानिरीक्षक की दशा में, सभी ग्रुपों, यूनिटों, मुख्यालयों, स्थापनों पर और उनके अधीन रखे गए सुरक्षक कर्मियों और उस क्षेत्र के भीतर जो उसे समनुदिष्ट किए जाएं, विस्तार होगा;

(ग) उपमहानिरीक्षक की दशा में, उसके अधीन रखे गए सभी ग्रुपों अन्य कर्मियों और यूनिटों पर और उस क्षेत्र के भीतर जो उसे समनुदिष्ट किए जाएं, विस्तार होगा।

(घ) कमानों की दशा में, उसके अधीन रखे गए ग्रुप या यूनिटों पर और उस क्षेत्र के भीतर जो उसे समनुदिष्ट किए जाएं, विस्तार होगा।

(3) ऐसे ग्रुपों, यूनिटों और स्थापनों के कमान अनुशासन, प्रशासन और प्रशिक्षण, जिसे किसी उप-महानिरीक्षक या किसी महानिरीक्षक के अधीन नहीं रखा गया है, ऐसे आफिसरों द्वारा और ऐसी रीति से किया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा समय-समय पर अधिकृत किए जाएं।

(4) सुरक्षक का कोई सदस्य आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाइयों के संबंध में किसी भी इयटी का पालन करने, सुरक्षक के प्रशासन, अनुशासन और कल्याण तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों के जिनकी उसमें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार पालन करने के लिए कहा जाए, पालन करने के लिए बाधित होगा, इस निमित्त किसी बरिष्ठ आफिसर द्वारा दिया गया आदेश उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विधिपूर्ण कमान

14. कमान—(1) कमान के लिए नियुक्त किसी आफिसर को, उसके कमान के अधीन रखे गए सभी आफिसरों और प्राधिकारियों पर ज्येष्ठता को ध्यान में लाए बिना, कमान की शक्ति होगी।

(2)(क) किसी आकास्मिकता की दशा में यदि कोई आफिसर उस कमान का जिसके साथ वह नियुक्त किया गया है, किसी कारणवश प्रयोग करने में असमर्थ हो तो कमान का उत्तरदायित्व कमान के दूसरे व्यक्ति पर, यदि उसे इस प्रकार नियुक्त किया गया है, आ जाएगा।

(ख) यदि कमान के दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई है तो कमान का उत्तरदायित्व ऐसे व्यक्ति पर आ जाएगा जिसे कमान का प्रयोग करने में असमर्थ ठीक बरिष्ठ आफिसर द्वारा स्थानापन्न रूप से कमान के लिए नियुक्त किया जाए।

(ग) यदि इस प्रकार किसी आफिसर की नियुक्ति नहीं की गई है तो कमान का उत्तरदायित्व ज्येष्ठतम उपस्थित आफिसर पर आ जाएगा।

(घ) किसी अन्य आफिसर द्वारा कमान के प्रयोग की असमर्थता की ओर इ उपनियम के अनुसार किसी अन्य आफिसर द्वारा उसका भार ग्रहण किए जाने के बारे में रिपोर्टें ऐसे आफिसर द्वारा जिनसे कमान का भार ग्रहण किया है अपने उच्चतर आफिसर को शीघ्र की जाएगी।

(3) यदि विभिन्न यूनिटों के व्यक्ति—

(i) किसी ऐसे विनिर्दिष्ट कार्य के लिए जिम्मेदार नियोजित किए गए हैं, एक साथ कार्य कर रहे हैं तो कमान करने के लिए नियुक्त किया गया आफिसर या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम उपस्थित आफिसर ऐसे सभी व्यक्तियों की कमान करेगा;

(ii) अन्य सभी मामलों में प्रत्येक यूनिट का ज्येष्ठ अधिकारी अपनी यूनिट के व्यक्तियों का कमान करेगा।

(4) ऐसे व्यक्ति पर जो अधिनियम के अधीन हैं, अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग उस यूनिट के कमानों द्वारा किया जाएगा जिसका वह व्यक्ति है, या उस आफिसर द्वारा जिस पर उपनियम (2) के अनुसार कमान का भार आया है, किया जाएगा।

(5) जहां कोई ऐसा व्यक्ति टुकड़ी संबंधी इयटी कर रहा है, जिस प्रवर्तित शिक्षण कार्यक्रम पर उपस्थित होना भी है, यूनिट, सेंटर या स्थापन का कमानों जिन्हें गांव बड़ों की इयटी कर रहा है, किसी कमानों की सभी अनुशासनिक शक्तियां भी उसे प्राप्त होंगी।

(6) महानिदेशक, महानिरीक्षक और उपमहानिरीक्षक कर्मचारियों के एक या अधिक आफिसरों को विनिर्दिष्ट कर सकेंगे, जो, ऐसे व्यक्तियों की बाबत जो अपने अपने मुख्यालयों के हैं या अपने अपने मुख्यालयों में टुकड़ी इयटी कर रहे हैं, किसी कमान की अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(7) महानिदेशक, ऐसे आफिसरों को भी विनिर्दिष्ट कर सकेंगे जो ऐसे व्यक्तियों की बाबत जो अपने मुख्यालयों के हैं या उनमें टुकड़ी इयटी कर रहे हैं, कमान: महानिरीक्षक और उपमहानिरीक्षक की अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(8) कोई महानिरीक्षक, किसी ऐसे आफिसर को विनिर्दिष्ट कर सकेंगे जो, ऐसे व्यक्तियों की बाबत जो उनके मुख्यालय के हैं या उनमें टुकड़ी इयटी कर रहे हैं, किसी उपमहानिरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

स्पष्टीकरण—उपनियम (1) और (3) में, "आफिसर" शब्द के अन्तर्गत महायक कमानों और रजिस्टर प्रेड 1 भी होंगे।

अध्याय IV

सेवा की समाप्ति

15. केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्वयार के कारण आफिसरों की सेवा की समाप्ति—

(1) जब धारा 9 के अधीन, किसी आफिसर की सेवा, उसके अन्वयार के कारण समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है, तब उसकी उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति से ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने के लिए अवसर दिया जाएगा। परन्तु यह उपनियम निम्नलिखित को लागू नहीं होगा, अर्थात्—

(क) जहाँ सेवा, ऐसे आन्वयार के आधार पर समाप्त की जाती है, जिसके लिए दण्ड न्यायालय या किसी सुरक्षक न्यायालय द्वारा उसे दोषमिद किया गया है; या

(ख) जहाँ, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, आफिसर को हेतुक दर्शित करने के लिए अवसर दिया जाना समीचीन या युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है।

(2) जब केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक का किसी आफिसर के अन्वयार की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि किसी सुरक्षक न्यायालय द्वारा आफिसर का विचारण असमीचीन या अव्यवहार्य है, किन्तु उसकी यह राय है कि उक्त आफिसर का सेवा में और बने रहने दिया जाना आवश्यकनीय है, तब महानिदेशक, आफिसर को उन मामलों में जहाँ अधिकृतों का अन्वेषण किया गया है, अधिकृत की विनिर्दिष्टों और अन्वेषण की रिपोर्ट सहित (जिसके अन्तर्गत साक्षी का अभिलिखित कथन और दस्तावेजों की प्रतियाँ यदि कोई हों, जिनका उसके विरुद्ध उपयोग किया जाता आशयित है, भी हैं) ऐसी सूचना देगा और उसे अपना स्पष्टीकरण और प्रतिवाद लिखित में प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

परन्तु महानिदेशक ऐसी किसी रिपोर्ट या उसके भाग के प्रकटन को रोक सकेगा यदि, उसकी राय में, उक्त प्रकटन राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है।

(3) यदि महानिदेशक आफिसर के स्पष्टीकरण को असमाधानप्रद समझता है या जब केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाता है, तब मामले को आफिसर के प्रतिवाद सहित और उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट रीति से आफिसर की सेवा की समाप्ति के संबंध में महानिदेशक की सिफारिश के साथ केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) उपनियम (2) या उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय सरकार को मामले को प्रस्तुत करने समय महानिदेशक इस बात की अपनी सिफारिश करेगा कि क्या आफिसर की सेवा समाप्त की जानी चाहिए और यदि ऐसा हो तो क्या आफिसर को—

(क) सेवा से पदच्युत किया जाना चाहिए; या

(ख) सेवा से हटा दिया जाना चाहिए; या

(ग) सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए; या

(घ) त्यागपत्र देने के लिए कहा जाना चाहिए।

(5) केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, रिपोर्ट और आफिसर के प्रतिवाद पर यदि कोई हो, या दण्ड न्यायालय के निर्णय और महानिदेशक की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात्, आफिसर को सेवा में पेशन सहित या पेशन के बिना या पदच्युत कर सकेगा या सेवानिवृत्त या सेवा से उसका त्यागपत्र प्राप्त कर सकेगा, और उसके ऐसा करने से इंकार करने पर आफिसर को उसकी अनुज्ञेय पेशन या उपदान यदि कोई हो, सहित अनिवार्य सेवा निवृत्त या हटाया जा सकेगा।

16. अन्वयार से भिन्न आधारों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा आफिसरों की सेवा की समाप्ति—

(1) जब महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि किसी आफिसर को सेवा में बनाए रखे जाना अनुपयुक्त है तो, आफिसर को—

(क) ऐसी सूचना दी जाएगी;

(ख) उसके प्रतिकूल सभी विषयों की विनिर्दिष्टों दी जाएगी, और

(ग) किन्हीं ऐसे कारणों को प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाएगा जिन्हें वह सेवा में अपने को बनाए रखे जाने के लिए अपने पक्ष में सामने रखने के लिए इच्छा प्रकट करे—

परन्तु खण्ड (क), (ख) और (ग) लागू नहीं होंगे, यदि केन्द्रीय सरकार का, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, यह समाधान हो जाता है कि, उसके उपबन्धों का अनुपालन किया जाना समीचीन या युक्तियुक्त साध्य नहीं है।

परन्तु यह और कि, महानिदेशक आफिसर को, ऐसी कोई मामलों नहीं देगा जो उसके प्रतिकूल हों, यदि उसकी राय में ऐसा करना राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है।

(2) यदि महानिदेशक स्पष्टीकरण को असमाधानप्रद समझता है तो मामले को आदेश के लिए केन्द्रीय सरकार को, आफिसर के स्पष्टीकरण और महानिदेशक की सिफारिश के साथ, प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, रिपोर्ट, आफिसर के स्पष्टीकरण पर यदि कोई हो, और महानिदेशक की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् आफिसर को सेवानिवृत्त होने के लिए या त्यागपत्र देने के लिए वह कह सकेगी और उसके ऐसा करने से इंकार करने पर, आफिसर को उसकी अनुज्ञेय पेशन या उपदान सहित, यदि कोई हो, अनिवार्य सेवा निवृत्त किया जा सकेगा।

17. आफिसरों से भिन्न व्यक्तियों का अन्वयार के कारण पदच्युत किया जाना या हटाया जाना—

(1) जब किसी आफिसर से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति की जो अधिनियम के अधीन है, सेवा समाप्ति का प्रस्ताव किया जाता है तब उसको पदच्युत या हटाये जाने के लिए समक्ष प्राधिकारी द्वारा उसको ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति से हेतुक दर्शित करने के लिए अवसर दिया जाएगा।

परन्तु यह उपनियम निम्नलिखित को लागू नहीं होगा, अर्थात्—

(क) जहाँ सेवा ऐसे आन्वयार के आधार पर समाप्त की जाती है, जिसके लिए दण्ड न्यायालय या किसी सुरक्षक न्यायालय द्वारा उसे दोषमिद किया गया है; या

(ख) जहाँ महाम प्राधिकारी का ऐसे कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, यह समाधान हो जाता है कि संबंधित कामिक को हेतुक दर्शित करने के लिए अवसर दिया जाना समीचीन या युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है।

(2) जब संबंधित कामिक के अन्वयार के संबंध में रिपोर्टों पर विचार किए जाने के पश्चात् महाम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे किसी कामिक का विचारण असमीचीन और साध्य नहीं है, किन्तु यदि उसकी यह राय है कि उसकी सेवा में और बनाए रखना वाञ्छनीय नहीं है तो वह उसे उसके प्रतिकूल सभी रिपोर्टों सहित सूचित करेगा और उसमें लिखित में अपना स्पष्टीकरण और प्रतिवाद प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

परन्तु, महाम प्राधिकारी ऐसी किसी रिपोर्ट या उसके भाग के प्रकटन को रोक सकेगा यदि, उसकी राय में, उक्त प्रकटन लोक हित में नहीं है।

(3) सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, उसके स्पष्टीकरण, या दण्ड न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के पश्चात् उसको सेवा से, पेंशन सहित या उसके बिना, पदच्युत कर सकेगा या हटा सकेगा।

(4) इस नियम के अधीन पदच्युत किए जाने या हटाए जाने के सभी मामले, महानिदेशक को रिपोर्ट किए जाएंगे।

18. शारीरिक अनुपयुक्तता के आधार पर आफिसरों की सेवानिवृत्ति—

(1) जहां किसी उपमहानिरीक्षक से अन्यून पंक्ति का कोई आफिसर यह समझता है कि, सुरक्षक का कोई आफिसर अपनी शारीरिक अवस्था के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करने में अनुपयुक्त है, तो आफिसर को किसी चिकित्सीय बोर्ड के समक्ष लाया जाएगा।

(2) चिकित्सीय बोर्ड में ऐसे आफिसर होंगे और उसका ऐसी रीति से गठन किया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा समय समय पर अधिकथित किए जाएं।

(3) जहां चिकित्सीय बोर्ड, आफिसर का सेवा के लिए अनुपयुक्त होना समझता है, वहां केन्द्रीय सरकार, यदि वह चिकित्सीय बोर्ड के निष्कर्ष से सहमत होती है, तो उक्त आफिसर को चिकित्सीय बोर्ड के निष्कर्ष को संमूचित करेगी और तब, आफिसर ऐसी संसूचना के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार को उसके विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकेगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, आफिसर से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, इस प्रयोजन के लिए गठित किसी नए चिकित्सीय बोर्ड को मामले का पुनर्विलोकन किए जाने के लिए निर्देश करेगी और यदि नए चिकित्सीय बोर्ड का विनिश्चय उसके प्रतिकूल है तो उक्त आफिसर की सेवानिवृत्ति के लिए आदेश करेगी।

19. अनुपयुक्तता के आधार पर सहायक कमांडरों की सेवानिवृत्ति— जहां ग्रुप कमांडर से अन्यून पंक्ति के किसी कमांडर का यह समाधान हो जाता है कि किसी सहायक कमांडर, सुरक्षक में बनाए रखा जाना अनुपयुक्त है, वहां वह सक्षम प्राधिकारी को ऐसे किसी सहायक कमांडर की सेवा निवृत्ति के लिए सिफारिश कर सकेगा।

तब, सहायक कमांडर ग्रेड I की दशा में महानिरीक्षक, और सहायक कमांडर ग्रेड II और ग्रेड III की दशा में उपमहानिरीक्षक, किसी सहायक कमांडर को हेतुक दणित करने के लिए अवसर देने के पश्चात् (तब के सिवाय जब वह ऐसा अवसर दिया जाना असाध्य हो) ;

उक्त सहायक कमांडर को सुरक्षक से सेवानिवृत्ति कर सकेगा।

20. अनुपयुक्तता के आधार पर रैंजर और शोधक व्यवसायी की सेवानिवृत्ति :—

जहां ग्रुप कमांडर से अन्यून पंक्ति के किसी कमांडर का यह समाधान हो जाता है कि कोई रैंजर या कोई योधक व्यवसायी सुरक्षक में बनाए रखे जाने के लिए अनुपयुक्त है, वहां कमांडर, ऐसे किसी रैंजर या किसी योधक व्यवसायी को हेतुक दणित करने के लिए अवसर दिए जाने के पश्चात् (तब के सिवाय जब वह ऐसा अवसर दिया जाना असाध्य समझता हो), उक्त रैंजर या किसी योधक व्यवसायी को सुरक्षक से सेवा निवृत्त कर सकेगा।

21. शारीरिक अनुपयुक्तता के आधार पर सहायक कमांडर, रैंजर और योधक व्यवसायी की सेवा निवृत्ति—(1) जहां ग्रुप कमांडर से अन्यून पंक्ति के किसी कमांडर का यह समाधान हो जाता है कि, कोई सहायक कमांडर, रैंजर या कोई योधक व्यवसायी किसी शारीरिक निशक्तता के कारण अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ है तो, वह निदेश दे सकेगा कि यथास्थिति उक्त सहायक कमांडर, रैंजर या योधक व्यवसायी को किसी चिकित्सीय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए।

(2) चिकित्सीय बोर्ड का गठन ऐसी रीति से किया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा अवधारित की जाए।

(3) जहां उक्त सहायक कमांडर, रैंजर या योधक व्यवसायी का चिकित्सीय बोर्ड द्वारा सुरक्षक में और सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, वहां कमांडर चिकित्सीय बोर्ड की कार्यवाहियों को सहायक कमांडर ग्रेड I की दशा में, महानिरीक्षक के पास और सहायक कमांडर ग्रेड II और ग्रेड III की दशा में उपमहानिरीक्षक के पास भेजेगा। महानिरीक्षक या उपमहानिरीक्षक, या यथास्थिति रैंजर, या योधक व्यवसायी की दह दशा में कमांडर यदि वह चिकित्सीय बोर्ड के निष्कर्ष से सहमत होता है तो, संबंधित व्यक्ति को उसके बारे में सूचित करेगा जिससे कि वह चिकित्सीय बोर्ड के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसी संसूचना की प्राप्ति से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, अभ्यावेदन करने के लिए समर्थ हो सके।

(4) जहां और सेवा के लिए अनुपयुक्त घोषित व्यक्ति, उपनियम

(3) के अधीन कोई अभ्यावेदन करता है वहां उसे अगले वरिष्ठ अधिकारी के पास अग्रसर किया जाएगा जो मामले को किसी नए चिकित्सीय बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन के लिए निर्दिष्ट करेगा। बोर्ड का गठन ऐसी रीति से किया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा अवधारित की जाए।

वरिष्ठ अधिकारी नए चिकित्सीय बोर्ड के निष्कर्ष के ध्यान में रखते हुए, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

(5) जहां उपनियम (3) के अधीन चिकित्सीय बोर्ड के विनिश्चय के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन नहीं किया जाता है वहां महानिरीक्षक या उपमहानिरीक्षक या यथास्थिति कमांडर (यदि वह चिकित्सीय बोर्ड के निष्कर्ष से सहमत है) क्रमशः सहायक कमांडर ग्रेड I या सहायक-कमांडर ग्रेड II या सहायक कमांडर ग्रेड III या यथास्थिति रैंजर या योधक व्यवसायी की सेवानिवृत्ति के आदेश कर सकेगा।

22. त्यागपत्र (i) केन्द्रीय सरकार किसी मामले की विशेष परिस्थितियों के ध्यान में रखते हुए सुरक्षक के किसी आफिसर को सेवा निवृत्ति की आयु को पूरा करने से पूर्व या उतने वर्षों की सेवा पूरी करने के पूर्व जितनी नियमों के अधीन सेवानिवृत्ति के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक हों सुरक्षक से त्यागपत्र देने के लिए अनुज्ञा दे सकेगी :

परन्तु ऐसी अनुज्ञा देने समय केन्द्रीय सरकार,

(i) आफिसर से ऐसी रकम के जो उस आफिसर को दिए गए प्रशिक्षण की लागत हो प्रतिदाय की अपेक्षा कर सकेगी; या

(ii) यदि आफिसर पेंशन नियमों के अधीन पेंशन संबंधी फायदों के लिए पात्र है तो आफिसर की पेंशन या अन्य पेंशन संबंधी फायदों में से ऐसी कटौती के आदेश कर सकेगी जैसे कि सरकार उन परिस्थितियों में त्वायोचित और समुचित समझे।

(2) केन्द्रीय सरकार उपनियम (1) के अधीन उस तारीख से जिसे वह समीचीन समझे, त्यागपत्र स्वीकार कर सकेगी :

परन्तु यह ऐसे त्यागपत्र की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के पश्चात् की नहीं होगी।

(3) केन्द्रीय सरकार किसी आफिसर को त्यागपत्र देने की अनुज्ञा से इंकार कर सकेगी।

(क) यदि देश में आंतरिक उपद्रव या बाह्य आक्रमण के कारण आपात की उद्घोषणा की गई है ; या

(ख) यदि वह सुरक्षक के अनुशासन के हित में ऐसा किया जाना असमीचीन समझती है ; या

(ग) यदि किसी आफिसर ने विशेष रूप से किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सेवा करने के लिए वचनबद्ध किया है और ऐसी अवधि समाप्त नहीं हुई है।

(4) इस नियम के उपबन्ध सहायक कमांडर रैंजर और योधक व्यवसायियों को और उनके संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे सुरक्षक

के किसी भी आफिसर को या उसके संबंध में लागू होने हैं और उपनियम (1) और (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार में विभिन्न शक्तियों का प्रयोग सहायक कमांडर ग्रेड I की दशा में किसी महानिरीक्षक द्वारा सहायक कमांडर ग्रेड II और III की दशा में किसी उपमहानिरीक्षक द्वारा तथा रैंजर ग्रेड I रैंजर या किसी योद्धक कदमियों की दशा में किसी ग्रुप कमांडर द्वारा किया जाएगा।

23. बरिष्ठ आफिसर या प्राधिकारी द्वारा प्रयोज्य शक्तियाँ— इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी आफिसर को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग प्रथम उल्लिखित प्राधिकारी से कमान में बरिष्ठ आफिसर या प्राधिकारी द्वारा भी की जा सकेगी।

24. पदच्युति, हटाया जाना या सेवा निवृत्ति के आदेशों के विरुद्ध अपील।

(1) यदि, आफिसर से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति को जो अधिनियम के अधीन है, सेवा से पदच्युति किया गया है, हटाया गया है या समयपूर्व सेवानिवृत्ति किया गया है, तो उसे अपनी सेवा समाप्ति के बिना सेवा समाप्ति का आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी से उच्चतर किसी आफिसर को सेवा समाप्ति की जाने के तबसे दिन के भीतर अपील करने का अधिकार होगा।

(2) अधिकांशों की दशा में, अपनी केन्द्रीय सरकार को की जाणी और ऐसी अपील सेवा की समाप्ति के तबसे दिन के भीतर फाईल की जाणी।

(3) जहाँ अपील प्राधिकारी इस नियम के अधीन पदच्युति, हटाए जाने या सेवानिवृत्ति के आदेश को अपास्त करता है, वह ऐसा प्राधिकारी ऐसे आदेश पारित करेगा जो ऐसे व्यक्ति की, किसी पदच्युति, हटाया जाना या सेवा निवृत्ति अपास्त की गई है, इयूटी ने अनुपस्थित रहने की अवधि की बाबत आवश्यक हो।

25. पदच्युति, हटाए जाने, सेवान्मुक्त किए जाने, सेवा निवृत्ति की तारीख (1) पदच्युति हटाए जाने, पदत्याग या सेवा निवृत्ति की प्रमाणां तारीख —————

(क) वह तारीख होगी जो पदच्युति या हटाए जाने या सेवान्मुक्त किए जाने के आदेश में अथवा त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति मंजूर या स्वीकार करने वाले आदेश में उल्लिखित हो, या

(ख) यदि ऐसी कोई तारीख उल्लिखित नहीं की गई है तो वह तारीख होगी जिसको आदेश पर हस्ताक्षर किया गया था या वह तारीख जिसको संबंधित व्यक्ति को इयूटी में मुक्त किया गया था, इसमें जो भी बाद की तारीख हो, होगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन के किसी व्यक्ति की पदच्युति, हटाया जाना, सेवान्मुक्त किया जाना, पदत्याग या सेवा निवृत्ति भूतलक्षी नहीं होगी।

अध्याय—5

गिरफ्तारी और अन्वेषण

26. गिरफ्तारी के रूप (1) गिरफ्तारी या तो खुली गिरफ्तारी हो सकेगी या बंद गिरफ्तारी।

(2) गिरफ्तारी से, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, खुली गिरफ्तारी अभिप्रेत है।

(3) गिरफ्तारी अधिरोपित करने वाला आदेश गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप में संसूचित किया जा सकेगा।

27. गिरफ्तारी का आदेश करने वाला प्राधिकारी—(1) इस अधिनियम के अधीन के किसी व्यक्ति की अधिनियम के अधीन किसी

आरोप पर गिरफ्तारी उस पर कमान की शक्ति रखने वाले बरिष्ठ आफिसर के आदेश के अधीन और उसके अनुसार ही की जाणी अन्यथा नहीं।

(2) उपनियम (2) में किसी बात को होने हुए भी, कोई व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन है, किसी बरिष्ठ आफिसर द्वारा गिरफ्तार किया जा सकेगा :—

(क) यदि वह ऐसे बरिष्ठ आफिसर के विरुद्ध कोई अपराध करता है, या

(ख) यदि वह ऐसे बरिष्ठ आफिसर के सामने कोई अपराध करता है, या

(ग) यदि वह विच्छेदनीय रीति में आचरण करता है और उस, बरिष्ठ आफिसर ऐसे विच्छेदनीय आचरण को रोकने की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यकता समझता है।

(3) उपनियम (2) के अधीन गिरफ्तारी करने वाला बरिष्ठ अधिकारी यथासम्भव शीघ्र और किसी भी दशा में ऐसी गिरफ्तारी के चौबीस घंटे के भीतर उस ग्रुप या यूनिट के कमांडर को जिसका गिरफ्तार किया गया व्यक्ति सदस्य है, और एक के या उससे ऊपर की रैंक के किसी आफिसर की गिरफ्तारी की दशा में, उसके सीधे बरिष्ठ आफिसर को एक रिपोर्ट भेजेगा।

28. गिरफ्तारी अधिरोपित करने की रीति:—(अ) बंद गिरफ्तारी,

(1) (क) बंद गिरफ्तारी रैंजर ग्रेड या और योद्धक कदमियों की दशा में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को सूचित करके और यह आदेश देकर की जाणी कि उसे उगी या उससे बरिष्ठ रैंक के व्यक्तियों के अनुमंडल में परिरोध स्थल को ले जाया जाए;

(ख) जहाँ ऐसा कोई अनुमंडल उपलब्ध न हो वहाँ गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को क्वार्टर गार्ड या अन्य परिरोध स्थल पर अपने आप तुरंत रिपोर्ट करने का आदेश दिया जाएगा।

(2) (क) बंद गिरफ्तारी आफिसरों, और अवर आफिसरों, सहायक कमांडरों और रैंजर ग्रेड I की दशा में, ऐसे आफिसर, सहायक कमांडर रैंजर ग्रेड I को उगी या बरिष्ठ रैंक के किसी दूसरे व्यक्ति की अभिरक्षा में रखा कर की जाणी और जहाँ कहीं आवश्यक समझा जाए वहाँ ऐसा आफिसर सहायक कमांडर, रैंजर ग्रेड I किसी गार्ड के प्रभार के अधीन परिरोध किया जा सकेगा।

(ख) गिरफ्तार व्यक्ति कमांडर द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी बरिष्ठ आफिसर का अनुज्ञा के बिना अपना परिरोध स्थल नहीं छोड़ेगा।

(अ) खुली गिरफ्तारी 3 (क) खुली गिरफ्तारी गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को यह सूचित करके की जाणी कि वह खुली गिरफ्तारी के अधीन है और वह अपने आप को उन सीमाओं के भीतर परिरोध रखेगा जो ऐसी गिरफ्तारी करने वाले संबंधित बरिष्ठ आफिसर द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए।

(ख) कमांडर अपर खंड (क) में विनिर्दिष्ट सीमाओं में समय समय पर परिवर्तन कर सकेगा।

29. अन्वेषण के दौरान गिरफ्तारी में निमित्त (1) नियम 27 के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को किसी आफिसर के आदेश के अधीन गिरफ्तारी में निमित्त किया जा सकेगा :

परन्तु ऐसे व्यक्ति को दशा में जो किसी आफिसर द्वारा गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी का आदेश करने वाले आफिसर ने बरिष्ठ अधिकारी के आदेश के अधीन गिरफ्तारी से निमित्त किया जाएगा।

(2) नियम 30 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति को, उसके विरुद्ध नए साक्ष्य के आधार पर पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है अन्यथा नहीं।

30. पुनः गिरफ्तारी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना निर्भूति अन्वेषण पूरा होने तक या न्यायालय संयोजित किए जाने तक, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसके कमांडर द्वारा या उसके कमांडर से बरिष्ठ किसी आफिसर द्वारा पुनः गिरफ्तारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्मुक्त किया जा सकेगा।

31. गिरफ्तारी कब की जाएगी—(1) किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर निम्नलिखित का आरोप है :—

(1) धारा 15 या धारा 16 के खंड (क) या खंड (ख) या धारा 17 या धारा 20 या धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का ;

(2) मृत्यु या आजीवन कारावास में दंडनीय किसी सिविल अपराध का ;

(3) अधिनियम के अधीन किसी अन्य अपराध का :—

(क) यदि अनुशासन के हित में ऐसा अपेक्षित है, या

(ख) यदि संपूक्त व्यक्ति जान बूझ कर अनुशासन में क्षति पहुंचाना है, या

(ग) यदि संपूक्त व्यक्ति हिंसात्मक स्वभाव का है, या

(घ) यदि संपूक्त व्यक्ति की विचारण में बचने की दृष्टि से अनु-परिस्थिति संभाव्य है, या

(ङ) यदि संपूक्त व्यक्ति का साक्षियों के साथ हस्तक्षेप और साक्ष्य में गड़बड़ करना संभाव्य है, गिरफ्तार किया जाएगा।

(2) जहाँ किसी गिरफ्तार व्यक्ति में बीमारी के लक्षण हैं, वहाँ उसे चिकित्सीय सहायता की जाएगी।

32. मृत व्यक्ति की गिरफ्तारी की दशा में विशेष उपबन्ध

(1) जहाँ कोई मृत व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, वहाँ उसे यथा संभव श्रमण ही परिहृत किया जाएगा और ड्यूटी आफिसर या ड्यूटी सहायक कमांडर या गारड के भारमाधक ड्यूटी रेंजर हर दो घंटे बाद उसके पास एक बार जाएगा।

(2) किसी मृत व्यक्ति को उसके मामले के अन्वेषण के लिए किसी बरिष्ठ आफिसर के समक्ष तब तक नहीं ले जाया जाएगा जब तक वह स्वस्थचित नहीं हो जाता है।

33. उन व्यक्तियों की दशा में गिरफ्तारी जिनके विचारण के लिए आदेश दिए गए हैं (1) यदि, संयोजन आफिसर ने अव्यथा निवेश नहीं दिया है तो किसी व्यक्ति की न्यायालय द्वारा विचारण प्रारम्भ होने पर, उक्त व्यक्ति को उसके कमांडर के अधीन रखा जाएगा और विचारण के दौरान वह गिरफ्तार रहेगा।

(2) जहाँ किसी न्यायालय द्वारा कारावास में कम दण्डादेश पारित किया जाता है वहाँ गिरफ्तार व्यक्ति को उसके कमांडेंट द्वारा तब तक के लिए निर्मुक्त कर दिया जाएगा जब तक कि निकर्ण और दण्डादेश की पुष्टि नहीं हो जाती है।

परन्तु संयोजन प्राधिकारी कमांडर द्वारा उक्त नियम (1) या उक्त नियम (2) के अधीन पारित किए गए आदेश को विरुद्धित परिवर्तित या उपलब्ध कर सकेगा और जहाँ ऐसा कोई आदेश कमांडर द्वारा नहीं किया गया है, वहाँ संयोजन प्राधिकारी ऐसा आदेश, जो वह उचित समझे पारित कर सकेगा :

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे पदच्युत किए जाने का दंडादेश दिया गया है, उस दशा के विषय अब वह सक्रिय इण्टी पर है, किसी ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा।

34. बिलम्ब रिपोर्टें—(1) (क) धारा 57 के अधीन यथा अपेक्षित बिलम्ब के कारणों के संबंध में रिपोर्ट परिशिष्ट I में दिए गए प्रश्नों में होगी और यह कमांडेंट द्वारा उक्त उपमहानिरीक्षक को भेजी जाएगी जिसके अधीन अभियुक्त सेवा कर रहा है ;

(ख) आठवीं बिलम्ब रिपोर्ट और उसके पश्चात् वाली प्रत्येक रिपोर्ट की एक प्रति भी उक्त महानिरीक्षक को भेजी जाएगी जिसके अधीन अभियुक्त सेवा कर रहा है।

(2) जहाँ अभियुक्त को विचारण के लिए लाए बिना तीन मास से अधिक अवधि के लिए गिरफ्तार रखा गया है, वहाँ की गई कार्रवाई और बिलम्ब के कारणों के बारे में विशेष रिपोर्ट कमांडर द्वारा महानिदेशक को और उसकी एक एक प्रति संबंधित उपमहानिरीक्षक और महानिरीक्षक को भेजी जाएगी।

35. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार—(1) (क) गिरफ्तार करने वाला आफिसर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय उसके विरुद्ध आरोपों की लिखित विनिर्णियाँ देगा ;

(ख) खंड (क) में किसी बात के होने हुए भी, जहाँ अन्वेषण के दौरान अभियुक्त द्वारा किए गए अन्य अपराधों का पता चलता है, वहाँ उन अपराधों में ऐसे व्यक्ति को आरोपित करना विधिपूर्ण होगा।

(2) (क) ड्यूटी आफिसर या ड्यूटी सहायक कमांडर गिरफ्तार व्यक्ति को प्रतिदिन जाकर देखेगा और गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा किए गए निवेदन या अभ्यावेदन पर कमांडर से आदेश प्राप्त करेगा।

(ख) गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा किया गया निवेदन या अभ्यावेदन परिशिष्ट 2 में उपबर्णित प्ररूप में प्रविष्ट किया जाएगा।

अध्याय 6

मुख्य न्यायालय और दंड न्यायालय के बीच अधिकारिता का वृत्ताव --

36. मुख्य न्यायालय या दंड न्यायालय द्वारा मामलों का विचारण—(1) जहाँ कोई अपराध, दोनों दंड न्यायालय और मुख्य न्यायालय द्वारा, विचारणीय है, वहाँ धारा 77 में निर्दिष्ट आफिसर—

(1) (क) जहाँ अभियुक्त द्वारा अपराध, मुख्य के मदम्य के रूप में अपने कर्तव्य के पालन के दौरान किया जाता है, या

(ख) जहाँ अपराध सरकार या मुख्य या उक्त अधिनियम के अधीन के किसी व्यक्ति की संपत्ति के संबंध में किया जाता है, या

(ग) जहाँ अपराध, अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है

यह निदेश दे सकेगा कि अधिनियम के अधीन के किसी व्यक्ति का जिसके बारे में ऐसा अपराध किया जाता अभिकथित है, विचारण मुख्य न्यायालय द्वारा किया जाएगा, और

(ii) किसी अन्य मामले में, यह विनिश्चय कर सकेगा कि नया अनुशासन के हित में यह आवश्यक होगा कि अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति का, जिसके बारे में ऐसा अपराध किया जाता अभिकथित है, न्यायालय द्वारा विचारण का दावा किया जाए।

(2) सुरक्षक न्यायालय द्वारा किसी अपराधी के विचारण का दावा करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य में, धारा 77 में निहित कोई आफिसर निम्नलिखित में से गयी या किन्हीं बातों पर विचार कर सकेगा, अर्थात्:—

- (क) अपराधी सक्रिय ड्यूटी पर है या उसे सक्रिय ड्यूटी के लिए चेतावनी दी गई है और यह महसूस किया गया है कि वह ऐसी ड्यूटी से बचने का प्रयत्न कर रहा है;
- (ख) अपराधी एक नवयुवक व्यक्ति है जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है और अपराध गंभीर नहीं है और किसी दंड न्यायालय द्वारा अपराधी का विचारण उसके प्रशिक्षण को सार्वजनिक रूप से प्रभावित करेगा;
- (ग) अपराधी के बारे में मामले की प्रकृति को देखते हुए अधिनियम के अधीन नक्षेपत कार्रवाई की जा सकेगी।

37. ऐसे मामले जिनका विचारण सुरक्षक न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता—नियम 26 के उपनियम (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी अपराधी के बारे में मामान्यतः निम्नलिखित दशाओं में विचारण का दावा किसी सुरक्षक न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकेगा:

- (क) जहां अपराध उसके द्वारा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ किया गया है जो अधिनियम के अधीन का नहीं है और जिसकी पहचान जाना जाता है, या
- (ख) जहां अपराध उसके द्वारा है, जब वह छुट्टी पर हो या छुट्टी के बिना अनुपस्थिति के दौरान किया गया है।

अध्याय 7

अन्वेषण और संक्षिप्त निपटारा

38. अभिकथनों का विवरण—जहां यह अभिकथन किया गया है कि अधिनियमों के अधीन का किसी व्यक्ति ने उसके अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, वहां अभिकथन को रेंजर, ग्रेड 1 के और उससे नीचे की पंक्ति के व्यक्तियों की दशा में परिशिष्ट 3 में निर्दिष्ट प्रारूप में और आफिसरों और सहायक कमांडरों की दशा में परिशिष्ट 4 में निर्दिष्ट प्रारूप में लिखा जाएगा।

39. टीम कमांडर और स्वाइत कमांडर द्वारा सुनवाई—

- (क) आफिसर या सहायक कमांडर ने भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो अधिनियम के अधीन का है, मामले की सुनवाई प्रथमतः उसके टीम कमांडर या उसके स्वाइत कमांडर द्वारा की जाएगी।
- (ख) साक्षियों की सुनवाई, अभियुक्त की उपस्थिति में, जिसे उनकी प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार होगा, की जाएगी।
- (ग) अभियुक्त को अपनी रक्षा के लिए साक्षियों को बुलाने और कथन करने का अधिकार होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन अभियुक्त की सुनवाई के पश्चात् यथास्थिति, टीम कमांडर या स्वाइत कमांडर, ऐसा दंड दे सकेगा। जिसके लिए वह सक्षम है या जब आरोप साबित नहीं होता है तो उसे खारिज कर सकेगा अथवा मामले को कमांडर द्वारा निपटाए जाने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा।

परन्तु वह ऐसे मामले का निपटारा नहीं करेगा जिसे स्वयं कमांडर द्वारा निपटाए जाने के लिए आरक्षित रखा गया है या यदि अभियुक्त बंद गिरफ्तारी के अधीन है।

40. कमांडर द्वारा सुनवाई—(1) ग्रुप कमांडर या उससे ऊपर की पंक्ति का कमांडर नियम 39 के उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार सभी रैंकों के विरुद्ध आरोप की सुनवाई कर सकेगा, और

(i) वहां ऐसा कोई दंड दे सकेगा जिसके लिए किसी रेंजर ग्रेड 1 के या उससे नीचे की पंक्ति के अधिकारों की बाबत देने के लिए वह सक्षम है, या

(ii) आरोप को खारिज कर सकेगा; या

(iii) अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य का अभिलेख या साक्ष्य की साक्षात्पत्त तैयार करने के लिए मामले को प्रतिप्रेषित कर सकेगा;

या

v) रेंजर ग्रेड 1 के या उससे नीचे की पंक्ति के किसी अभियुक्त की दशा में, अभियुक्त को संक्षिप्त सुरक्षा न्यायालय द्वारा विचारण के लिए प्रतिप्रेषित कर सकेगा।

परन्तु—

(क) किसी आफिसर के मामले में, साक्षियों के साक्ष्य को यदि वह ऐसी मांग करे, तो लिखा जाएगा।

(ख) कमांडर आरोप को खारिज कर सकेगा, यदि उसकी राय में, आरोप साबित नहीं होता है या उसे खारिज कर सकेगा यदि वह समझता है कि अभियुक्त के पिछले चरित्र और उसके विरुद्ध आरोप की प्रकृति के कारण इस पर और आगे विचार करना उपयुक्त नहीं है। किसी आफिसर के मामले में, आरोप खारिज करने के कारणों को वह अभिलेखित करेगा।

(ग) जहां किसी आफिसर की बाबत कोई मामला अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ करने के लिए किसी वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा किसी कमांडर को निर्दिष्ट किया गया है,

वहां कमांडर ऐसे आरोप को ऐसे प्राधिकारी को निर्देश बिना खारिज नहीं करेगा।

(घ) मृत्यु से दंडनीय सभी अपराधों के मामलों में, साक्ष्य का अभिलेख तैयार किया जाएगा।

(2) जहां कमांडर की राय है कि किसी आफिसर या सहायक कमांडर के विरुद्ध आरोप गंभीर प्रकृति के हैं वहां वह उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार आरोप की सुनवाई किए बिना मामले में साक्ष्य के अभिलेख के लिए या साक्ष्य का सार-तैयार किए जाने के लिए सीधा आदेश दे सकेगा।

(3) जहां कमांडर की राय है कि किसी आफिसर या सहायक कमांडर के विरुद्ध आरोप खारिज किए जाने योग्य नहीं है और आरोप इतना गंभीर भी नहीं है कि उसका विचारण सुरक्षक न्यायालय द्वारा किया जाए वहां वह सहायक कमांडर की दशा में या तो स्वयं मामले का निपटारा कर सकेगा या धारा 54 के उपबंधों के अधीन निपटारे के लिए किसी समुचित प्राधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा। किसी आफिसर की दशा में वह मामले को धारा 53 के उपबंधों के अधीन संक्षिप्त निपटारे के लिए समुचित प्राधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा।

(4) जहां किसी ग्रुप या यूनिट या मुख्यालय के कमान आफिसर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जानी आवश्यक है वहां ऐसे आफिसर को यथास्थिति उस ग्रुप यूनिट या मुख्यालय के कमान से हटा दिया जाएगा या उस प्रयोजन के लिए इस प्रकार संबद्ध या तैनात किए जाने वाले आफिसर से वरिष्ठ आफिसर के कमान के अधीन ग्रुप यूनिट या मुख्यालय में उसे संबद्ध या तैनात किया जाएगा।

41. आफिसरों के विरुद्ध आरोपों के संक्षिप्त निपटारे की प्रक्रिया:

(1) जहां किसी आफिसर को, उसके विरुद्ध आरोप के संक्षिप्त निपटारे के लिए प्रतिप्रेषित किया जाता है वहां, उसको आरोप पत्र के साथ उसके विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्य का सार या अभिलेख की एक प्रति या साक्ष्य की संक्षिप्त यथासाध्य यदि तैयार किया गया हो और किसी भी दशा में कार्यवाही आरम्भ होने के चौबीस घंटे के भीतर किया जाएगा।

(2) धारा 53 के अधीन मामले की कार्यवाही करने वाला अधिकारी जब तक कि अभियुक्त ने साक्षियों की उपस्थिति में लिखित रूप में की अभियुक्ति की सम्मति नहीं दी हो। अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य की सुनवाई करेगा और उसे साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार होगा। अभियुक्त को किसी साक्षी को बुलाने और अपनी प्रतिरक्षा में कथन करने का अधिकार होगा।

(3) कार्यवाहियों की यथासाध्य परिशिष्ट XIV के प्ररूप के अनुसार अभिलिखित किया जाएगा और ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें दण्ड अधिनिर्णीत किया जाए, यथास्थिति, साक्ष्य के सार या अभिलेख या साक्ष्य की संक्षिप्ति के साथ कार्यवाही करने उच्चतर प्राधिकारी को जज महा-न्यायाधीश या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के माध्यम से भेजा जाएगा, जो यदि उसे अधिनिर्णीत किया गया दण्ड अवैध, अन्यायपूर्ण या अत्यधिक प्रतीत होता है तो दण्ड में परिवर्तन कर सकेगा या छूट दे सकेगा या कार्यवाही को अग्रस्त कर सकेगा या ऐसा अन्य निदेश दे सकेगा जो मामले की परिस्थिति में समुचित हो।

(4) यदि कोई सहायक कमांडर इस नियम के अधीन किए गए विनिश्चय से अपने आप को व्यथित समझता है तो वह अपने कमांडर के माध्यम से एक याचिका मामले के निपटारे के एक मास के भीतर दण्ड अधिनिर्णीत करने वाले प्राधिकारी से वरिष्ठ प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी ऐसा आदेश या निवेश पारित कर सकेगा जो मामले की परिस्थिति में समुचित हो।

42. सहायक कमांडरों के विरुद्ध आरोपों का संक्षिप्त निपटारा:

(1) जहाँ किसी सहायक कमांडर को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से आरोपित किया गया है वहाँ उसके विरुद्ध धारा 54 के अधीन सशक्त प्राधिकारी द्वारा नियम 41 में यथाउपबन्धित के अनुसार लगभग उसी रीति से कार्यवाही की जाएगी जो परिस्थितियाँ स्वीकार करें।

(2) कार्यवाहियों की यथासाध्य परिशिष्ट XIV के प्ररूप के अनुसार अभिलिखित किया जाएगा और ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें दण्ड अधिनिर्णीत किया जाए, यथास्थिति, साक्ष्य के सार या अभिलेख या साक्ष्य की संक्षिप्ति के साथ कार्यवाही करने उच्चतर प्राधिकारी को जज महा-न्यायाधीश या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के माध्यम से भेजा जाएगा, जो यदि उसे अधिनिर्णीत किया गया दण्ड अवैध, अन्यायपूर्ण या अत्यधिक प्रतीत होता है तो दण्ड में परिवर्तन कर सकेगा या छूट दे सकेगा या कार्यवाही को अग्रस्त कर सकेगा, या ऐसा अन्य निदेश दे सकेगा जो मामले की परिस्थिति में समुचित होगा।

(3) यदि कोई सहायक कमांडर इस नियम के अधीन किए गए विनिश्चय से अपने आप को व्यथित समझता है तो वह अपने कमांडर के माध्यम से एक याचिका मामले के निपटारे के एक मास के भीतर दण्ड अधिनिर्णीत करने वाले प्राधिकारी से वरिष्ठ प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी ऐसा आदेश या निवेश पारित कर सकेगा जो मामले की परिस्थिति में समुचित हो।

43. किसी दूसरी यूनिट के सम्बन्धता कमांडर किसी मामले में कार्यवाही नहीं करेगा—

(i) जिसमें वह अपराध, जिसका अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है, स्वयं कमांडर के विरुद्ध है, या

(ii) जहाँ कमांडर अभियुक्त के विरुद्ध मामले में स्वयं साक्षी है, या

(iii) जहाँ कमांडर मामले में व्यक्तिगत रूप से अग्रगण्य हितवद्ध है वहाँ अभियुक्त को समस्त प्राधिकारी के आदेश के अधीन मामले के निपटारे के लिए किसी दूसरे ग्रुप या यूनिट या मुख्यालय से सम्बन्धित किया जाएगा:

परन्तु कमांडर केवल इस कारण आरोप को सुनवाई करने से निरहित नहीं होगा कि अपराध संरक्षक को उस में से बैठ या संस्था की जिसका कमांडर सचिव या ग्यासी है संपत्ति के विरुद्ध किया जायेगा या कि अपराध ऐसे कमांडर के आदेशों की अवज्ञा का अपराध है।

44. वे आरोप जिन पर संक्षिप्त कार्यवाही नहीं की जानी है :—
धारा 15 या धारा 16 के खण्ड (क) और (ख) या धारा 17 या धारा 18 के खण्ड (क) या धारा 20 के खण्ड (क) या धारा 23 के खण्ड (क) या धारा 45 के अधीन (साधारण उपहति या चोरी से भिन्न) किसी अपराध के आरोप या इन अपराधों में से किसी के दुष्प्रेरण करने या दुष्प्रेरण करने के प्रयत्न के आरोप पर संक्षिप्त कार्यवाही नहीं की जाएगी।

45. साक्ष्य का अभिलेख :—(1) कमांडर या तो स्वयं साक्ष्य के अभिलेख तैयार कर सकेगा या वह किसी दूसरे अधिकारी को ऐसा करने के लिए लगा सकेगा।

(2) साक्षी अपना साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में देगे और अभियुक्त को उन सब साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार होगा जो उसके विरुद्ध साक्ष्य देते हैं।

(3) अभियुक्त के विरुद्ध सभी साक्षियों की परीक्षा कर लिए जाने के पश्चात् अभियुक्त को निम्नलिखित रूप से सतर्क किया जाएगा: "यदि आप कोई कथन करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप कथन करने के लिए बाध्य नहीं हैं और आप जो कुछ कहेंगे वह लिख लिया जाएगा और उसका साक्ष्य में प्रयोग किया जा सकेगा।" पूर्वोक्त रीति से सतर्क किए जाने के पश्चात् अभियुक्त जो कुछ कथित करता है वह लिख लिया जाएगा।

(4) अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा में साक्षी बुला सकेगा और साक्ष्य अभिलिखित करने वाले अधिकारी कोई भी ऐसा प्रश्न पूछ सकेगा जो ऐसे साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो।

(5) सभी साक्षी शपथ या प्रतिज्ञा पर साक्ष्य देंगे।

परन्तु अभियुक्त से कोई शपथ या प्रतिज्ञा नहीं कराया जाएगा और उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जाएगी।

(6) (क) साक्षियों द्वारा दिए गए कथन सामान्यतः कृतार्थ के रूप में अभिलिखित किए जाएंगे और साक्ष्य अभिलिखित करने वाला अधिकारी अभियुक्त के निवेदन पर, साक्ष्य के किसी भाग की प्रश्नोत्तर के रूप में अभिलिखित करने की अनुज्ञा दे सकेगा;

(ख) साक्षियों को उनके कथन पढ़कर सुनाए जाने और स्पष्ट किए जाने के पश्चात् साक्षी उन पर हस्ताक्षर करेंगे।

(7) अधिनियम की धारा 86 के उपबन्ध, साक्ष्य का अभिलेख तैयार करने वाले अधिकारी के समस्त साक्षियों को हाजिर कराने के लिए लागू होंगे। परिशिष्ट XII में दिए गए नमूने के अनुसार साक्षियों को समन किया जाएगा।

(8) जहाँ किसी साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है या वह उपलब्ध नहीं है या उसे समय या धन के अभाव में बिना हाजिर नहीं कराया जा सकता और जहाँ साक्ष्य अभिलिखित करने वाले अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्रमाणपत्र दिए जाने के पश्चात् वह ऐसे साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित कथन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जा सकेगा और वह साक्ष्य के अभिलेख में सम्मिलित किया जा सकेगा।

(9) साक्ष्य का अभिलेखन पूरा करने के पश्चात् साक्ष्य अभिलिखित करने वाला अधिकारी निम्नलिखित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र देगा:

"प्रमाणित किया जाता है कि-----कमांडर-----
द्वारा आदिष्ट साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति और सुनवाई में लेखबद्ध किया गया था और नियम 45 के उपबन्धों का पालन किया गया है।"

(10) किसी काउन्सेल या विधि व्यवसायी को साक्ष्य अभिलिखित करने वाले आफिसर के समक्ष उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

46. साक्ष्य का सार:—(1) साक्ष्य का सार या तो कमांडर या उसके द्वारा लगाया गया कोई आफिसर तैयार करेगा।

(2) (क) साक्ष्य के सार में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

(i) साक्षियों के हस्ताक्षरित कथन जहाँ कहीं उपलब्ध हों या उसके सारांश; और

(ii) विचारण में पेश की जाने के लिए आशयित सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ।

(ख) जहाँ किन्हीं साक्षियों के हस्ताक्षरित कथन उपलब्ध न हों, वहाँ उनके द्वारा दिए जाने वाले संभावित साक्ष्य का सारांश सम्मिलित होगा।

(3) साक्ष्य का सार तैयार करने वाले आफिसर द्वारा साक्ष्य के सार की एक प्रान्त अभियुक्त को दो जागृगी और अभियुक्त को, यदि वह चाहता है तो उसे नियम 15 के उपनियम (3) में अधिकथित रीति से सतर्क करने के पश्चात् कथन करने का अवसर दिया जाएगा :

परन्तु अभियुक्त को अपना कथन करने के लिए उतना समय दिया जाएगा जो परिस्थितियों में युक्तियुक्त हो, किन्तु किसी भी दशा में उसे साक्ष्य के सार की प्रान्त के पश्चात् चौबीस घंटे से कम समय नहीं दिया जाएगा।

47. पुलिस द्वारा मामलों का अन्वेषण:—जहाँ कमांडर ऐसा करना आवश्यक समझता है, वहाँ वह किसी मामले के अन्वेषण के लिए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा सकेगा।

48. साक्ष्य के अभिलेख या सार के पश्चात् कमांडर द्वारा मामले का निपटारा:—(1) जहाँ साक्ष्य का अभिलेख तैयार करने या उनका सार बनाने का कार्य किसी आफिसर को सौंपा गया हो, वहाँ वह उसे कमांडर को भेजेगा।

(2) कमांडर स्वयं अपने या किसी दूसरे आफिसर द्वारा तैयार किए गए साक्ष्य के अभिलेख या सार का अवलोकन करने के पश्चात्:—

(i) यदि अपेक्षित हो, मामले को अतिरिक्त साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए प्रतिप्रेषित कर सकेगा; या

(ii) आरोप खारिज कर सकेगा परन्तु जहाँ वरिष्ठ प्राधिकारी के निर्देश पर किसी आफिसर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरम्भ की गई है, वहाँ ऐसे प्राधिकारी को निर्देश किए बिना आरोप खारिज नहीं किया जाएगा; या

(iii) आरोप की पुनः सुनवाई कर सकेगा और संक्षिप्त दण्ड में से कोई दण्ड अधिनियमित कर सकेगा; या

(iv) धारा 31 के अधीन अभियुक्त का संक्षिप्त विचारण कर सकेगा या संक्षिप्त सुरक्षक न्यायालय द्वारा विचारण कर सकेगा जहाँ वह ऐसा करने को सक्षम है, या ;

(v) किसी आफिसर या सहायक कमांडर की दशा में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा संक्षिप्त निपटारे के लिए मामले को प्रतिप्रेषित कर सकेगा ; या

(vi) अभियुक्त के विचारण के लिए न्यायालय मंजूरित करने के लिए सक्षम आफिसर या प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

49. न्यायालय के लिए आवेदन:—न्यायालय के लिए आवेदन यथासंभव इन नियमों के परिशिष्ट 5 में दिए गए प्ररूप में कमांडर द्वारा किया जाएगा और उसके साथ साक्ष्य के अभिलेख या सार और आरोप-पत्र

की पाँच प्रतियाँ और ऐसे अन्य दस्तावेज होंगे जिनका उस आवेदन के प्ररूप में उल्लेख किया गया है।

अध्याय 8

आरोप और विचारण की पूर्वगामी बातें

50. आरोप-पत्र:—(1) आरोप-पत्र में संपूर्ण विवाद्यक या एक ही समय में विचारणीय सभी विवाद्यक होंगे और यदि आरोप उन्हीं तथ्यों पर आधारित है अथवा उसी या वैसे ही स्वरूप के अपराधों की श्रृंखला के भाग रूप है तो आरोप-पत्र में एक से अधिक आरोप हो सकेंगे :

परन्तु धारा 18, धारा 19, धारा 28 और धारा 31 के अधीन कोई आरोप किसी आरोप-पत्र में इस बात के होते हुए भी सम्मिलित किया जा सकेगा कि उस आरोप-पत्र में अन्य आरोप उन्हीं तथ्यों पर आधारित नहीं है अथवा उसी या वैसे ही स्वरूप के अपराधों की श्रृंखला के भागरूप नहीं है।

(2) प्रत्येक आरोप-पत्र यथासंभव इन नियमों के परिशिष्ट IV में दिए गए नमूने के अनुसार तैयार किया जाएगा।

51. आरोप:—प्रत्येक अपराध के लिए पृथक आरोप होगा।

(2) (क) यदि कोई एक कार्य या कार्यों की श्रृंखला ऐसी प्रकृति की है कि यह संदेह है कि उन तथ्यों से, जो सिद्ध किए जा सकते हैं, कई अपराधों में से कौन सा अपराध बनेगा तो अभियुक्त पर ऐसे सब अपराध या उनमें से कोई करने का आरोप लगाया जा सकेगा और किसी भी संख्या में ऐसे आरोपों का एक साथ तुरंत विचारण किया जा सकेगा; या उस पर उक्त अपराधों में से कोई अपराध करने का अनु-कल्पतः आरोप लगाया जा सकेगा।

(ख) अधिक गम्भीर अपराध के आरोप का उल्लेख उससे कम गम्भीर अपराध के आरोप के पहले किया जाएगा।

(3) प्रत्येक आरोप के दो भाग होंगे, अर्थात्:—

(क) अपराध का कथन, और

(ख) अपराध की विशिष्टियाँ।

(4) यदि अपराध सिविल अपराध नहीं है तो उसका कथन यथा साध्य अधिनियम के निकटतम शब्दों में किया जाएगा और यदि अपराध सिविल अपराध है तो उसका कथन ऐसे शब्दों में किया जाएगा जो उस अपराध का पर्याप्त रूप से वर्णन करते हैं।

(5) (क) विशिष्टियों में अधिकथित अपराध के समय और स्थान का और उस व्यक्ति का (यदि कोई हो) जिसके विरुद्ध अथवा उस वस्तु का (यदि कोई हो) जिसके विषय में वह अपराध किया गया है कथन होगा और ये विशिष्टियाँ अभियुक्त को उस बात की, जिसका उस पर आरोप है, सूचना देने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

(ख) यदि ऐसी विशिष्टियाँ अभियुक्त को उस बात की जिसका, उस पर आरोप है, सूचना देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो उस रीति की, जिससे अपराध किया गया था, ऐसी विशिष्टियाँ भी जो उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त हैं, आरोप में अन्तर्लिखित होंगी।

52. संयुक्त आरोप:—(1) कितनी भी संख्या में अभियुक्तों पर किसी ऐसे अपराध का जिसके बारे में यह प्रकथित है कि वह उन्होंने संयुक्त रूप से किया है, संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा और उनका एक साथ विचारण किया जा सकेगा।

(2) कितनी भी संख्या में अभियुक्तों का ऐसे अपराध के लिए, जिसके बारे में यह प्रकथित है कि वह उनमें से एक या अधिक द्वारा किया गया है और दूसरे या दूसरों द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है, एक साथ विचारण भी किया जा सकेगा भले ही उस पर संयुक्त रूप से आरोप नहीं लगाया गया है।

(3) जहाँ अभियुक्तों पर उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन इस प्रकार आरोप लगाया जाता है वहाँ उनमें से एक या अधिक पर किसी अन्य अपराध का जिसका उन पर नियम 50 के उपनियम (1) के अधीन आरोप लगाया जा सकता था, आरोप लगाया जा सकेगा।

53. आरोपपत्र की विधिमन्विता :—आरोपपत्र केवल इस तथ्य के कारण अधिमन्विता नहीं होगा कि उसमें अभियुक्त के नाम या वर्णन में कोई भूल है और आरोपपत्र का अर्थ लगाने में, ऐसी प्रत्येक प्रतिपादना की, जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह उपधारण की जा सकती है कि वह उनमें व्यक्त न होते हुए भी विवक्षित रूप से उसमें सम्मिलित है, उक्तता समर्थन करने के पत्र में उपधारण की जाएगी और अपराध का कथन तथा अपराध की विधिद्वितीया एक साथ पढ़ी जाएगी और उनका एक साथ अर्थ लगाया जाएगा।

54. सुरक्षक न्यायालय द्वारा आरोप का संशोधन :—(1) यदि विचारण के दौरान किसी समय न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि आरोपपत्र में :—

- (क) अभियुक्त के नाम या वर्णन में कोई भूल है, या
- (ख) कोई ऐसी भूल है जो स्पष्ट गलती या लोप के कारण हुई जाती जा सकती है,

तो न्यायालय उस भूल को सुधारने के लिए आरोपपत्र का संशोधन कर सकेगा।

(2) यदि विचारण के दौरान, जिसमें जज अटर्नी है, किसी समय न्यायालय को अपने निष्कर्षों पर विचार-विमर्श की समाप्ति से पूर्व यह प्रतीत होता है कि किसी आरोप में कोई परिवर्तन, उससे लोप या उसमें परिवर्तन, जो इस नियम के उपनियम (1) के अधीन नहीं किया जा सकता, करना न्याय के हित में वांछनीय है तो वह उस दशा में जब ऐसा परिवर्तन लोप या परिवर्तन अभियुक्त के प्रति अशुभता के बिना किया जा सकता है, जज अटर्नी की सहमति से आरोप का इस प्रकार संशोधन कर सकेगा।

(3) यदि विचारण के दौरान, जिसमें कोई जज अटर्नी नहीं है किसी समय न्यायालय को अपने निष्कर्षों पर विचार-विमर्श की समाप्ति से पूर्व यह प्रतीत होता है कि किसी आरोप में कोई परिवर्तन, उससे लोप या उसमें परिवर्तन, जो इस नियम के उपनियम (1) के अधीन नहीं किया जा सकता, करना न्याय के हित में वांछनीय है तो वह स्वयं ही कर सकेगा और संयोजक आफिसर को अपनी राय की रिपोर्ट भेज सकेगा और संयोजक आफिसर—

(क) यदि नियम 55 के अधीन अनुज्ञेय है तो अपराध का संशोधन कर सकेगा और अभियुक्त को संशोधन की सम्यक् सूचना देने के पश्चात् संशोधित रूप में उसका विचारण करने के लिए न्यायालय को निदेश दे सकेगा; या

(ख) आरोप का संशोधन किए बिना उसका विचारण करने के लिए न्यायालय को निदेश दे सकेगा; या

(ग) अभियुक्त के विचारण के लिए नया न्यायालय संयोजित कर सकेगा।

55. संयोजक आफिसर द्वारा आरोप का संशोधन :—जब कोई सुरक्षक न्यायालय नियम 54 या नियम 70 के अधीन संयोजक आफिसर को रिपोर्ट भेजा है, तब वह उस आरोप का, जिसकी बाबत न्यायालय ने रिपोर्ट भेजी है ऐसे परिवर्तन लोप या परिवर्तन द्वारा संशोधन कर सकेगा जो उसकी राय में न्याय के हित में वांछनीय है और जिसके बारे में उसका यह समाधान हो गया है कि वह अभियुक्त के प्रति अशुभता के बिना किया जा सकता है।

जनरल और पैटी सुरक्षक न्यायालय का संयोजन

56. न्यायालय संयोजित करने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई (i) जैसे ही वरिष्ठ आफिसर न्यायालय संयोजित करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त करता है, वह जहाँ आवश्यक हो वहाँ जज अटर्नी जनरल या ऐसे आफिसर के साथ जिसे जज अटर्नी जनरल द्वारा इस प्रयोजन के लिए लगाया गया है, के परामर्श से अभियुक्त के विरुद्ध आरोप और साक्ष्य की संवीक्षा करेगा और, यह :—

(i) जहाँ अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य अपर्याप्त है और अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है, कमांडर को आरोप खारिज करने के लिए निदेश देगा और यदि वह विचारण प्रारम्भ करता उपयुक्त नहीं समझता है तो आरोप खारिज करने के लिए निदेश दे सकेगा, या

(ii) संक्षिप्त सुरक्षक न्यायालय द्वारा विचारण के लिए या संवीक्षा : कार्रवाई करने के लिए मामला कमांडर को उस दशा में वापस कर सकेगा जब उसका विचार है कि उसका इस प्रकार पर्याप्त रूप से विचारण किया जा सकता है या कार्रवाई की जा सकती है; या

(iii) मामले का प्रशासनिक रूप से निपटारा कर सकेगा और यदि वह ऐसा करने को सक्षम नहीं है तो अपनी रिकार्डों के साथ उच्चतर प्राधिकारी के पास मामले को भेज सकेगा; या

(iv) अतिरिक्त साक्ष्य अधिलिखित करने के लिए मामला उस दशा में वापस कर लेगा जब उक्त विचार है कि अधिलिखित साक्ष्य अपर्याप्त है किन्तु अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध हो सकेगा।

(2) (क) किसी अन्य मामले में यह या तो न्यायालय का संयोजन स्वयं कर सकेगा या यदि उसका यह विचार है कि उच्चतर किस्म के न्यायालय का संयोजन किया जाना चाहिए और वह ऐसा न्यायालय संयोजित करने के लिए सक्षम नहीं है तो वह इस निष्कर्ष के साथ कि ऐसे न्यायालय का संयोजन किया जाए, मामला उच्चतर प्राधिकारी को भेज सकेगा।

(ख) उच्चतर प्राधिकारी, मामला प्राप्त होने पर, इस नियम के उपनियम (1) की गई शक्तियों में से किसी का प्रयोग कर सकेगा :

परन्तु वरिष्ठ आफिसर या उच्चतर प्राधिकारी, जनरल सुरक्षक न्यायालय या पैटी सुरक्षक न्यायालय का संयोजन करने से पूर्व जज अटर्नी जनरल या ऐसे आफिसर को जिसे जज अटर्नी जनरल द्वारा इस प्रयोजन के लिए लगाया गया है, सलाह देगा :

परन्तु यह और कि वरिष्ठ आफिसर या उच्चतर प्राधिकारी न्यायालय को संयोजित करने समय, ऐसा आरोप पत्र पुनः विरचित कर सकेगा जिस पर अभियुक्त का विचारण किया जाना है।

57. जनरल और पैटी सुरक्षक न्यायालय में सेवा करने से आफिसरों की निराहता :—कोई आफिसर, न्यायालय में सेवा करने के लिए निराहित होगा यदि :—

(i) वह ऐसा आफिसर है जिसने न्यायालय को संयोजित किया है; या

(ii) वह अभियोजक है या अभियोजन का साक्षी है; या

(iii) उसने मामले के अन्वेषण में ऐसा भाग लिया है जिसके कारण उसे साक्ष्य के किसी भाग पर या मामले के तथ्यों पर अपना विचार लगाना आवश्यक हो गया था; या

(iii) वह अभियुक्त का कमांडर है या उपमहानिरीक्षक जिसके कमान के अधीन वह यूनिट भी जिसमें अभियुक्त द्वारा अधिकृत प्रपराय किया गया था, सेवारत था

(v) उसका मामले में कोई व्यक्तिगत हित है।

58. जनरल और पैदी सुरक्षक न्यायालयों का गठन—

(1) न्यायालय, यथासाध्य विभिन्न यूनिटों के आफिसरों से मिलकर गठित होगा।

(2) किसी आफिसर के विचारण के लिए न्यायालय के सदस्य उस आफिसर की रैंक से निम्नतर रैंक के नहीं होंगे जब तक संयोजन आफिसर की राय में, ऐसे रैंक के आफिसर, लोग सेवा की प्रत्यावश्यकताओं का सम्यक ध्यान रखते हुए उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी राय संयोजन आदेश में अभिलिखित की जाएगी।

59. न्यायालयों का संयोजन करते समय संयोजक आफिसर के कर्तव्य—
जब कोई आफिसर किसी न्यायालय का संयोजन करता है, तब वह:—

(क) परिशिष्ट 6 में दिए गए समुचित प्ररूप में संयोजन आदेश जारी करेगा;

(ख) यह निदेश देगा कि अभियुक्त का किन आरोपों पर विचारण किया जाना है और यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त का इन आरोपों पर न्यायालय द्वारा विचारण के लिए उसके कमांडर द्वारा प्रतिप्रेषण कर दिया गया है;

(ग) यदि उसकी यह राय है कि आरोप पृथक आरोपपत्र में सम्मिलित किए जाए, तो ऐसा निदेश देगा और यह निदेश भी देगा कि उनका विचारण किस क्रम से किया जाना है,

(घ) यदि एक से अधिक अभियुक्त हैं तो यह निदेश देगा कि अभियुक्तों का विचारण संयुक्ततः किया जाना है या पृथकतः;

(ङ) न्यायालय के सदस्यों और किन्हीं प्रतीक्षा सदस्यों की नियुक्ति करेगा;

(च) यदि

जनरल सुरक्षक न्यायालय का या पैदी सुरक्षक न्यायालय का जिसके बारे में वह समझता है कि उसमें जज घटनी को हाजिर होना चाहिए, संयोजन करता है, तो जज घटनी जनरल द्वारा या उसकी ओर से जज घटनी की नियुक्ति कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और ऐसे आफिसर को भी नियुक्त कर सकेगा जो विचारण के समय उसके अनुदेश के अधीन रहें ;

(छ) अभियोजन करने के लिए अधिनियम के अधीन के किसी आफिसर की या ऐसे आफिसर द्वारा सहायता प्राप्त किसी काउन्सेल की नियुक्ति करेगा ;

परन्तु यदि संयोजक आफिसर ठीक समझता है तो वह अभियोजन करने के लिए एक से अधिक ऐसे आफिसर नियुक्त कर सकेगा ;

(ज) जहाँ कहीं आवश्यक हो एक दुभाषिए की नियुक्ति करेगा;

(झ) बरिष्ठ सदस्य को आरोप-पत्र, संयोजन आदेश और अभिलेख या साक्ष्य के सार की एक प्रति भेजेगा जिसमें से वह साक्ष्य निकाल दिया गया है, जिसके बारे में उसकी राय है कि वह विचारण में प्रभाव्य होगा;

(ञ) न्यायालय के प्रत्येक सदस्य को और प्रत्येक प्रतीक्षा सदस्य को आरोप पत्र और संयोजन आदेश की एक प्रति भेजेगा;

(ट) अभियोजक को आरोप पत्र और संयोजन आदेश की प्रतियाँ और मूल अभिलेख या साक्ष्य का सार, उसकी प्रशोधित प्रति के साथ भेजेगा जिसमें से लेखाश (यदि कोई है) दलित होंगे जो बरिष्ठ सदस्य को भेजी गई प्रति में से निकाल दिए गए हैं ;

(ठ) जज घटनी को (यदि कोई है) आरोपपत्र और प्रतीक्षा यादें की प्रतियाँ और अभिलेख या साक्ष्य के सार की संशोधित प्रति भेजेगा, जिसमें से लेखाश (यदि कोई है) दलित होंगे जो बरिष्ठ सदस्य को भेजी गई प्रति में से निकाल दिए गए हैं ;

(ड) यह सुनिश्चित करेगा कि कमांडर ने सब अभियोजन साक्षियों को और ऐसे प्रतिरक्षा साक्षियों को सनन किया है जिन्हें सनन करने के लिए अभियुक्त ने नियम 61 के अधीन निवेदन किया हो।

60. अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा की तैयारी:—(1) ऐसे अभियुक्त को जिसको विचारण के लिए प्रतिप्रेषित किया गया है, अपनी प्रतिरक्षा तैयार करने का समुचित अवसर दिया जायेगा और उसे अपने प्रतिरक्षा आफिसर या काउन्सेल के साथ और अपने माधियों के साथ उचित संपर्क करने दिया जाएगा।

(2) किसी ऐसे अभियुक्त की, जिसकी विचारण के लिए प्रतिप्रेषित किया गया है, प्रतिरक्षा के लिए यथासंभव अभियुक्त की इच्छानुसार प्रतिरक्षा आफिसर की नियुक्ति की जाएगी जब तक कि अभियुक्त लिखित में यह कथित नहीं करता कि वह ऐसी नियुक्ति किए जाने का इच्छुक नहीं है।

(3) यदि अभियोजन, वैध रूप से आई आफिसर या काउन्सेल द्वारा किया जाता है तो अभियुक्त को पर्याप्त समय पहले यह तथ्य सूचित किया जाएगा जिससे कि यदि वह चाहे तो अपनी प्रतिरक्षा के लिए वैध रूप से आई आफिसर या काउन्सेल की व्यवस्था कर सके।

(4) अभियुक्त का विचारण करने का विनिश्चय करने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र और किसी भी दशा में उसके विचारण से कम से कम चार दिन पूर्व उसे—

(क) आरोप पत्र की एक प्रति दी जाएगी ;

(ख) अभिलेख या साक्ष्य के सार की एक प्रशोधित प्रति दी जाएगी जिसमें से लेखाश (यदि कोई है) दलित होंगे जो बरिष्ठ सदस्य को भेजी गई प्रति में से निकाल दिए गए हैं ;

(ग) ऐसे प्रतिरिक्त साक्ष्य की सूचना दी जाएगी जो अभियोजन बना चाहता है ; और

(घ) यदि अभियुक्त ऐसी प्रपेक्षा करता है तो उन सदस्यों के जिनसे मिलकर न्यायालय का गठन होगा, और प्रतीक्षा सदस्यों के रैंकों, नामों और यूनिटों की सूची दी जाएगी।

(5) जब किसी अभियुक्त को इस नियम के अनुसार आरोप पत्र की और अभिलेख या साक्ष्य के सार की प्रति दी जाए तब:—

(क) वह आरोप को स्पष्ट कराएगा; और (ख) उसे सूचित किया जाएगा कि उससे विचारण से कम से कम चौबीस घंटे पूर्व कमांडर को उसके द्वारा लिखित निवेदन किए जाने पर, जिसमें (अभियोजन के साक्षी से भिन्न) किसे ऐसे साक्षी की, जिसे वह अपनी प्रतिरक्षा में बुलाना चाहता है (ऐसे साक्षी का उसके द्वारा नाम दिया जाएगा, उसके विचारण में हाँ की अपेक्षा की गई हो, उसके विचारण में ऐसे साक्षी को हाजिर कराने के लिए इन नियमों के अनुसार नियुक्त कदम उठाए जाएँ)।

(6) उपनियम (2) और (3) के उपबंध सनरी सुरक्षक न्यायालय के समक्ष विचारण के संबंध में लागू नहीं होंगे और ऐसे विचारण के संबंध में चार दिन की उस अवधि का अर्थ, जो उपनियम (4) में निर्दिष्ट है, चौबीस घंटे लगाया जाएगा।

61. प्रतिरक्षा साक्षियों को सनन करना:—(1) उपनियम (2) और (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कमांडर अभियुक्त द्वारा इस नमित निवेदन किए जाने पर उन साक्षियों को सनन करेगा जो अभियुक्त द्वारा निर्दिष्ट किए जाएँ।

(2) जहाँ कमांडर का यह समाधान हो जाता है कि किसी साक्षी द्वारा दिए जाने वाले बयान से विचारण में कोई उत्थिक सहायता न मिलेगी संभावना नहीं है, वहाँ वह ऐसे साक्षी को समन करने से इंकार कर सकेगा। और ऐसा करते हुए वह साक्षियों को नहीं बुलाने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

(3) कमांडर किसी साक्षी को समन करने से पूर्व अभियुक्त से ऐसे साक्षी की हाजिरी के ब्यय को पूरा करने की या पूरा करने का जिम्मा लेने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि अभियुक्त पूर्वोक्त ब्यय को पूरा करने से या पूरा करने का जिम्मा लेने से इंकार करता है तो कमांडर उस साक्षी को हाजिर कराने से इंकार कर सकेगा।

(4) जहाँ कमांडर ने साक्षी को समन करने से उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन इंकार कर दिया है, वहाँ अभियुक्त ऐसे साक्षी को समन करने के लिए न्यायालय को आवेदन कर सकेगा और न्यायालय, यदि वह न्याय के हित में ऐसा करना समीचीन समझता है, तो ऐसे साक्षी को समन करने का आदेश दे सकेगा और यदि आवश्यक हो तो ऐसे साक्षी की हाजिरी के लिए कार्यवाही स्वंगत कर सकेगा।

स्पष्टीकरण साक्षियों को समन करने के लिए परिशिष्ट 15 में दिए गए मूने के अनुसार समन जारी किए जाएंगे।

अध्याय 9

साधारण और पीटी सुरक्षक न्यायालयों के लिए प्रक्रिया

62. न्यायालय का समवेत होना और शपथ लेना :—(1) सुरक्षक न्यायालय के समवेत होने पर न्यायालय विचारण प्रारंभ करने से पूर्व बंध न्यायालय में अपना समाधान करेगा कि :—

(क) न्यायालय अधिनियम और इन नियमों के अनुसार संयोजित किया गया है ;

(ख) न्यायालय जिन प्राफिसरों से मिलकर बना है उनकी संख्या विधि द्वारा अपेक्षित प्राफिसरों की न्यूनतम संख्या से कम नहीं है।

(ग) सदस्य अपेक्षित रैंक के हैं।

(घ) सदस्यों की सम्यक् रूप से नियुक्ति की गई है और वे अधिनियम के अधीन विरहित नहीं हैं ;

(ङ) यदि कोई जज घटनी है तो उसकी नियुक्ति सम्यक् रूप से की गई है ;

(च) आरोप-पत्र से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त अधिनियम के अधीन का है और न्यायालय की अधिकारिता के अधीन है ; और

(छ) प्रत्येक आरोप विधि की दृष्टि से सही है और इन नियमों के अनुसार विरचित किया गया है।

(2) (क) जहाँ कोई रिक्ति, न्यायालय के किसी सदस्य के अधिनियम के अधीन निरहित होने या न्यायालय के समवेत होने पर उसके अनुपस्थित रहने के कारण होती है वहाँ पीठासीन प्राफिसर उस रिक्ति को भरने के लिए सम्यक्कतः अहित प्रतीक्षा सदस्य को नियुक्त कर सकेगा।

(ख) पीठासीन प्राफिसर, यदि न्याय के हित में ऐसा अपेक्षित हो तो, संयोजक प्राफिसर द्वारा नियुक्त किसी सदस्य के स्थान पर सम्यक्कतः अहित प्रतीक्षा सदस्य को प्रतिस्थापित कर सकेगा।

(3) यदि न्यायालय का उपनियम (1) में उल्लिखित विषयों में से किसी के संबंध में समाधान नहीं होता है और अधिनियम या इन नियमों के अधीन ऐसे विषयों का वह स्वयं परीक्षण करने के लिए सक्षम नहीं है तो वह विचारण प्रारंभ करने से पूर्व उस संबंध में संयोजक प्राफिसर को रिपोर्ट भेजेगा।

(4) जब न्यायालय ने इस नियम का अनुपालन कर लिया है और विचारण प्रारंभ करने के लिए तैयार है, तब पीठासीन प्राफिसर न्यायालय की कार्यवाही प्रारंभ करेगा और विचारण प्रारंभ होगा।

63. विचारण का प्रारंभ :—(1) न्यायालय संयोजित करने का आदेश और अभियुक्त का विचारण करने के लिए नियुक्त प्राफिसरों के नाम अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाएंगे, जिसे उन प्राफिसरों में से किसी पर अधिनियम की धारा 81 के अनुसार आरोप करने का अधिकार दिया जाएगा।

(2) जब न्यायालयों को एक से अधिक अभियुक्तों का पृथक्कतः या संयुक्ततः विचारण करना है तब प्रत्येक अभियुक्त को न्यायालय-सीन किसी प्राफिसर के बारे में पूर्वगामी उपनियम के अनुसार आरोप करने का अधिकार दिया जाएगा और उनसे प्रत्येक प्रत्येक पूछा जाएगा कि क्या वे कोई ऐसा आरोप करते हैं।

(3) अभियुक्त, किसी आरोप के निपटाए जाने के पूर्व, उन सब प्राफिसरों के नाम बताएगा जिनके बारे में वह आरोप करता है।

(4) यदि एक से अधिक प्राफिसरों के बारे में आरोप किया जाता है तो प्रत्येक प्राफिसर के बारे में आरोप पृथक् रूप से निपटाया जाएगा और सबसे छोटे रैंक वाले प्राफिसर के बारे में आरोप को सबसे पहले निपटाया जाएगा।

(5) अभियुक्त कोई कथन कर सकेगा और अपने आरोप के समर्थन में कथन करने के लिए किसी व्यक्ति को बुला सकेगा।

(6) ऐसा कोई प्राफिसर जिसके बारे में अभियुक्त ने आरोप किया है, वह अभियुक्त के वादों से मुक्तता किसी बात का कथन खुले न्यायालय में कर सकेगा चाहे वह उसके समर्थन में हों या उसके खंडन में।

(7) किसी प्राफिसर के बारे में आरोप पर विचार न्यायालय-सीन सभी अन्य प्राफिसरों द्वारा बंध न्यायालय में किया जाएगा और वह प्राफिसर जिसके बारे में आरोप किया गया है उस समय उपस्थित नहीं रहेगा।

(8) जब किसी प्राफिसर के बारे में कोई आरोप धारा 81 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञात किया जाता है तब वह प्राफिसर तत्काल निवृत्त हो जाएगा और कार्यवाहियों में अपने कोई भाग नहीं लेगा।

(9) जब कोई आक्षेपित आफिसर निवृत्त हो जाता है और सम्यक्तः अहित प्रतीक्षा सदस्य हाजिर है तब पीठासीन आफिसर उस आफिसर का, जो निवृत्त हो गया है, स्थान ग्रहण करने के लिए उसकी तत्काल नियुक्ति करेगा।

(10) न्यायालय अपना यह समाधान करेगा कि ऐसा कोई प्रतीक्षा सदस्य, जो न्यायालय के सदस्य का स्थान ग्रहण करता है, अपेक्षित रैंक का है और अधिनियम के अधीन निरहित नहीं है तो अभियुक्त को उसके बारे में आक्षेप करने का अवसर देगा और ऐसे किसी आक्षेप के संबंध में अधिनियम और इन नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

(11) यदि किसी सदस्य के बारे में कोई आक्षेप अनुज्ञात किए जाने के परिणामस्वरूप, अधिनियम के अनुपालन में न्यायालय का गठन करने के लिए आफिसर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो न्यायालय अपने विचारण के लिए अवसर हुए बिना संयोजक आफिसर को रिपोर्ट करेगा और संयोजक आफिसर या तो उस रिक्ति को भरने के लिए किसी आफिसर को सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकेगा या अभियुक्त के विचारण के लिए या नया न्यायालय संयोजित कर सकेगा।

64. सदस्यों का शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना—जैसे ही न्यायालय समुचित संख्या में ऐसे आफिसरों से, जिन पर आक्षेप नहीं किया गया है या जिनके बारे में आक्षेप नामजूर कर दिए गए हैं, गठित हो जाता है वैसे ही प्रत्येक सदस्य को अभियुक्त की उपस्थिति में निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक में या समान आशय के ऐसे अन्य प्रारूप में जैसा न्यायालय उस सदस्य के धर्म के अनुसार या अन्यथा उसके अंतःकरण पर आबद्ध कर अभिविज्ञित करता है, शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा।

शपथ का प्रारूप

“मैं.....सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं न्यायालय के सामने अभियुक्त (या अभियुक्तों) का साक्ष्य के अनुसार भलीभांति और सच्चाई से विचारण करूँगा और मैं पक्षपात अनुग्रह या स्नेह के बिना, राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 के अनुसार, सम्यक् रूप से न्याय करूँगा और मैं यह शपथ भी लेता हूँ कि जब तक किसी न्यायालय द्वारा ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी भी कारण से, किसी भी समय, इस न्यायालय के किसी सदस्य विशेष का मत या राय प्रकट नहीं करूँगा या उसका पता नहीं लगाऊँगा।”

प्रतिज्ञान का प्रारूप

“मैं.....सत्यनिष्ठा, सद्भाव और सच्चाई से घोषणा करता हूँ और प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं न्यायालय के समक्ष अभियुक्त (या अभियुक्तों) का साक्ष्य के अनुसार भलीभांति और सच्चाई से विचारण करूँगा और मैं पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के बिना राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 के अनुसार सम्यक् रूप से न्याय करूँगा और मैं सत्यनिष्ठा, सद्भाव और सच्चाई से यह घोषणा और प्रतिज्ञान भी करता हूँ कि जब तक किसी न्यायालय द्वारा ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी भी कारण से, किसी भी

समय, इस न्यायालय के किसी सदस्य विशेष का मत या राय प्रकट नहीं करूँगा या उसका पता नहीं लगाऊँगा।”

65. जज अटर्नी और अन्य आफिसरों का शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना.—न्यायालय के सभी सदस्यों को शपथ दिलाए जाने और प्रतिज्ञान कराए जाने के पश्चात् निम्नलिखित व्यक्तियों को, या उनमें से जो न्यायालय में उपस्थित हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से ऐसे प्रश्न में, जो उचित हो या समान आशय के ऐसे अन्य प्रश्न में जैसा न्यायालय शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने वाले व्यक्ति के धर्म के अनुसार या अन्यथा उसके अंतःकरण पर आबद्ध कर अभिविज्ञित करता है, शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा।

जज अटर्नी

शपथ का प्रारूप

“मैं.....सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी सर्वोत्तम योग्यता से राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार और पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के बिना जज अटर्नी के कर्तव्यों का पालन करूँगा और मैं यह शपथ भी लेता हूँ कि जब तक किसी न्यायालय द्वारा ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी भी कारण से, किसी भी समय, किसी विषय पर इस न्यायालय के किसी सदस्य विशेष का मत या राय प्रकट नहीं करूँगा या उसका पता नहीं लगाऊँगा।”

प्रतिज्ञान का प्रारूप

“मैं.....सत्यनिष्ठा, सद्भाव और सच्चाई से घोषणा करता हूँ और प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं अपनी सर्वोत्तम योग्यता से राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार और पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के बिना जज अटर्नी के कर्तव्यों का पालन करूँगा और मैं सत्यनिष्ठा, सद्भाव और सच्चाई से यह घोषणा और प्रतिज्ञान भी करता हूँ कि जब तक किसी न्यायालय द्वारा ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी भी कारण से किसी भी समय किसी विषय पर इस न्यायालय के किसी सदस्य विशेष का मत या राय प्रकट नहीं करूँगा या उसका पता नहीं लगाऊँगा।”

(ब) अनुवेश के प्रयोजन के लिए हाजिर रहने वाला आफिसर

शपथ का प्रारूप

“मैं.....सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जब तक कि किसी न्यायालय द्वारा ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी भी कारण से, किसी भी समय, इस न्यायालय के किसी सदस्य विशेष का मत या राय प्रकट नहीं करूँगा या उसका पता नहीं लगाऊँगा।”

प्रतिज्ञान का प्रारूप

"क्ष..... सत्यनिष्ठा, सद्भाव और सच्चाई घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूँ कि जब तक किसी न्यायालय द्वारा ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी भी कारण से, किसी भी समय, इस न्यायालय के किसी सदस्य विशेष का मत या राय प्रकट नहीं करूँगा या उसका पता नहीं लगाऊँगा।"

(ग) आशुलिपिक

शपथ का प्रारूप

"क्ष..... सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी सर्वोत्तम शक्ति से इस न्यायालय के समक्ष दिए जाने वाले साक्ष्य और किसी ऐसे अन्य बातों को, जिन्हें लिखने की मुझसे अपेक्षा की जाए, सच्चाई से लिखूँगा और जब अपेक्षा की जाए, न्यायालय को उसकी सच्ची अनुलिपि दूँगा।"

प्रतिज्ञान का प्रारूप

"क्ष..... सत्यनिष्ठा, सद्भाव और सच्चाई से घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं अपनी सर्वोत्तम शक्ति से इस न्यायालय के समक्ष दिए जाने वाले साक्ष्य और ऐसी अन्य बातों को, जिन्हें लिखने की मुझसे अपेक्षा की जाए, सच्चाई से लिखूँगा और जब अपेक्षा की जाए, न्यायालय को उसकी सच्ची अनुलिपि दूँगा।"

(घ) कुभाषिया

शपथ का प्रारूप

"क्ष..... सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं इस न्यायालय के समक्ष मानने से संबंधित ऐसी किसी बात का, जिसका भाषान्तर और अनुवाद करने की मुझसे अपेक्षा की जाए, निष्ठापूर्वक भाषान्तर और अनुवाद करूँगा।"

प्रतिज्ञान का प्रारूप

"क्ष..... सत्यनिष्ठा, सद्भाव और सच्चाई से घोषणा करता हूँ और प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं इस न्यायालय के समक्ष मामले से संबंधित ऐसी किसी बात का, जिसका भाषान्तर और अनुवाद करने की मुझसे अपेक्षा की जाए, निष्ठापूर्वक भाषान्तर और अनुवाद करूँगा।"

66. कुभाषिए या आशुलिपिक के बारे में आक्षेप—यदि किसी व्यक्ति के बारे में अभियुक्त द्वारा कोई आक्षेप किया जाता है तो उसे कुभाषिए या आशुलिपिक के रूप में तब तक शपथ नहीं दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान नहीं कराया जाएगा जब तक कि न्यायालय, अभियुक्त और अभियोजक की सुमवाई के पश्चात् ऐसे आरोप को व्यक्तिगुण के रूप में मामलूर नहीं कर देता है।

67. जज अटर्नी और अभियोजक के बारे में आक्षेप—अभियुक्त को जज अटर्नी या अभियोजक के बारे में कोई आक्षेप करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

68. दोषारोपण—(1) जब न्यायालय और जज अटर्नी (यदि कोई है) को शपथ दिलाई गई है, अभियुक्त को आरोप पत्र सुनाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि वह आरोप या आरोपों का दोषी होने का अभिवाक् करता है या दोषी न होने का अभिवाक् करता है।

(2) यदि अभियुक्त के विरुद्ध एक से अधिक आरोप हैं तो उससे प्रत्येक आरोप के बारे में पृथक् अभिवाक् करने की अपेक्षा की जाएगी।

(3) यदि अभियुक्त के विरुद्ध एक से अधिक आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष हैं तो वह ऐसे आरोप पत्रों में से पहले आरोप पत्र के आरोपों के संबंध में कार्यवाही करेगा और उस पर अपने निष्कर्ष सुनाएगा और यदि अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवचन किया है तो वह किसी पश्चात्बर्ती आरोप पत्र के आरोपों पर उसका दोषारोपण करने से पूर्व नियम 75 का अनुपालन करेगा।

69. अधिकारिता के संबंध में अभिवाक्—(1) अभियुक्त आरोप के संबंध में अभिवचन करने से पूर्व न्यायालय की अधिकारिता के बारे में अभिवचन कर सकेगा और ऐसी दशा में—

(क) अभियुक्त अभिवचन के समर्थन में साक्ष्य पेश कर सकेगा और अभियोजक उसके उत्तर में साक्ष्य पेश कर सकेगा, और

(ख) अभियोजन अभिवचन के उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा।

(2) यदि न्यायालय अभिवचन अनुज्ञात करता है, तो वह स्वयं ही जाएगा और संयोजक आफिसर को रिपोर्ट भेजेगा।

(3) जब न्यायालय इस नियम के अधीन संयोजक आफिसर को रिपोर्ट करता है तब संयोजक आफिसर—

(क) यदि वह अभिवचन अनुज्ञात करने के न्यायालय के विनिश्चय का अनुमोदन करता है तो न्यायालय का विघटन कर देगा;

(ख) यदि वह न्यायालय के विनिश्चय का अनुमोदन कर देता है तो वह या तो—

(i) मामला न्यायालय को वापस निर्देशित करेगा और उसे बिचारण के लिए भ्रमसर होने का निदेश करेगा, या

(ii) अभियुक्त के बिचारण के लिए तथा न्यायालय संयोजित करेगा।

70. आरोप के बारे में आक्षेप—(i) कोई अभियुक्त आरोप पर अभिवचन करने से पूर्व उस पर इस आधार पर आक्षेप कर सकेगा

कि वह बिधि की दृष्टि से सही नहीं है या उसकी विरचना इन नियमों के अनुसार नहीं की गई है और यदि वह ऐसा करता है तो अभियोजक आक्षेप के उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक के रजिस्ट्रार का उत्तर दे सकेगा।

(2) यदि न्यायालय आक्षेप को कायम रखता है तो वह या तो आरोप का, यदि नियम 54 के अधीन अनुज्ञेय है तो, संशोधन करेगा या स्थगित हो जाएगा और संयोजक आफिसर को रिपोर्ट भेजेगा :

परन्तु यदि न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा आरोप या आरोप पत्र है तो न्यायालय इस नियम के अधीन स्थगित होने से पूर्व ऐसे अन्य आरोप या आरोप-पत्र के विचारण के लिए अग्रसर हो सकेगा।

(3) जब न्यायालय इस नियम के अधीन संयोजक आफिसर को रिपोर्ट भेजता है तब संयोजक आफिसर—

(क) यदि वह न्यायालय के आक्षेप अनुज्ञात करने के विनिश्चय का अनुमोदन करता है तो—

(i) न्यायालय का विघटन कर देगा; या

(ii) जहाँ न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा आरोप या आरोप-पत्र है जिसका न्यायालय ने विचारण नहीं किया है वहाँ वह केवल ऐसे अन्य आरोप या आरोप-पत्र के विचारण के लिए अग्रसर होने के लिए न्यायालय को निदेश देगा; या

(iii) ऐसे आरोप को, जिससे आक्षेप का संबंध है, यदि नियम 55 के अधीन अनुज्ञेय है तो संशोधन करेगा और उसका संशोधित रूप में विचारण करने के लिए न्यायालय को निदेश देगा;

(ख) यदि वह न्यायालय के आक्षेप अनुज्ञात करने के विनिश्चय का अनुमोदन कर देता है, तो—

(i) आरोप के विचारण के लिए न्यायालय को निदेश देगा, या

(ii) जहाँ न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा आरोप या आरोप पत्र है या जिसके संबंध में आक्षेप नहीं है और जिसका न्यायालय ने विचारण नहीं किया है, वहाँ वह केवल ऐसे अन्य आरोप या आरोप-पत्र के विचारण के लिए अग्रसर होने के लिए न्यायालय को निदेश देगा, या

(iii) अभियुक्त के विचारण के लिए नया न्यायालय संयोजित करेगा।

71. विचारण के वर्जन का अभिवचन :—(1) कोई अभियुक्त आरोप पर अभिवचन करने से पूर्व यह अभिवचन कर सकेगा कि विचारण धारा 72 या धारा 73 के अधीन बजित है। यदि वह ऐसा करता है, तो—

(क) अभियुक्त अभिवचन के समर्थन में साक्ष्य पेश कर सकेगा और अभियोजक उसके उत्तर में साक्ष्य पेश कर सकेगा, और

(ख) अभियोजक अभिवचन के उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा।

(2) यदि न्यायालय अभिवचन अनुज्ञात करता है तो वह स्थगित हो जाएगा और संयोजक आफिसर को रिपोर्ट करेगा :—

परन्तु यदि न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा आरोप या आरोप-पत्र है तो न्यायालय, इस नियम के अधीन स्थगित करने से पूर्व ऐसे अन्य आरोप या आरोप-पत्र के विचारण के लिए अग्रसर हो सकेगा।

(3) जब न्यायालय इस नियम के अधीन संयोजक आफिसर को रिपोर्ट भेजता है, तब संयोजक आफिसर—

(क) यदि वह अभिवचन अनुज्ञात करने के न्यायालय के विनिश्चय का अनुमोदन करता है, तो—

(i) न्यायालय का विघटन कर देगा; या

(ii) जहाँ न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा आरोप या आरोप-पत्र है, जिसके संबंध में अभिवचन नहीं है और जिसका न्यायालय ने विचारण नहीं किया है, वहाँ वह केवल ऐसे अन्य आरोप या आरोप-पत्र के विचारण के लिए अग्रसर होने के लिए न्यायालय को निदेश देगा।

(ख) यदि वह अभिवचन मंजूर करने के न्यायालय के विनिश्चय का अनुमोदन कर देता है, तो—

(i) आरोप के विचारण के लिए न्यायालय को निदेश देगा, या

(ii) जहाँ न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा आरोप या आरोप-पत्र है जिसके संबंध में अभिवचन नहीं है और जिसका न्यायालय ने विचारण नहीं किया है, वहाँ वह केवल ऐसे अन्य आरोप या आरोप-पत्र के विचारण के लिए अग्रसर होने के लिए न्यायालय को निदेश देगा, या

(iii) अभियुक्त के विचारण के लिए नया न्यायालय संयोजित करेगा।

72. पृथक् विचारण के लिए आवेदन :—(1) जहाँ दो या दो से अधिक अभियुक्तों को संयुक्ततः आरोपित किया जाता है, वहाँ उनमें से कोई एक अभियुक्त आरोप पर अभिवचन करने से पूर्व इस आधार पर पृथक् रूप से विचारण किए जाने के लिए न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि यदि उसका पृथक्तः विचारण नहीं किया गया तो उसकी प्रतिरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(2) जहाँ अभियुक्त ऐसा कोई आवेदन करता है वहाँ अभियोजक उसके उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा।

(3) जहाँ न्यायालय की यह राय है कि न्याय के हित में ऐसा अपेक्षित है, वहाँ वह आवेदन अनुज्ञात करेगा और उस अभियुक्त का, जिसने आवेदन किया था, पृथक् रूप से विचारण करेगा।

73. पृथक् आरोप-पत्र पर विचारण के लिए आवेदन—

(1) जहाँ किसी आरोप-पत्र में एक से अधिक आरोप हैं, वहाँ अभियुक्त आरोपों पर अभिवचन करने से पूर्व, इस आधार पर उस आरोप-पत्र के किसी आरोप पर पृथक् रूप से विचारण किए जाने के लिए न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि यदि उसका उस आरोप पर पृथक् विचारण नहीं किया गया तो उसकी प्रतिक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(2) जहाँ अभियुक्त ऐसा कोई आवेदन करता है, वहाँ अभियोजक उसके उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक में संबोधन का उत्तर दे सकेगा।

(3) जहाँ न्यायालय की यह राय है कि न्याय के हित में ऐसा अपेक्षित है, वहाँ वह आवेदन मंजूर करेगा और अभियुक्त का उस आरोप पर जिससे उसका संबंध है, इस प्रकार पृथक् रूप से विचारण करेगा मानो वह आरोप किसी पृथक् आरोप-पत्र में रखा गया है।

74. आरोप पर अभिवचन करना—(1) नियम 69 और नियम 71 के अधीन किसी अभिवचन, नियम 70 के अधीन किसी आक्षेप और नियम 72 और नियम 73 के अधीन किसी आवेदन के संबंध में कार्रवाई किए जाने के पश्चात् अभियुक्त से उपनियम (2) के अधीन रहते हुए ऐसे प्रत्येक आरोप का, जिसका उम्र पर दोषारोपण किया गया है, दोषी होने या दोषी न होने का अभिवचन करने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) जहाँ कोई न्यायालय, अभियुक्त पर आरोपित अपराध से भिन्न अपराध के लिए उसे दोषी ठहराने के लिए या अपराध के ऐसी परिस्थितियों में, जिनमें कम मात्रा में वंड अन्तर्बलित है, किए जाने का दोषा ठहराने के लिए धारा 90 द्वारा सशक्त है या जहाँ वह साक्ष्य सुनने के पश्चात् नियम 95 के अनुसार, अपवाद या परिवर्तन के अधीन रहते हुए, दोषी होने का विशेष निष्कर्ष निकाल सकता था, वहाँ अभियुक्त ऐसे अन्य अपराध का या आरोपित अपराध के ऐसी परिस्थितियों में, जिनमें कम मात्रा में वंड अन्तर्बलित है, किए जाने का या ऐसे अपवाद या परिवर्तन के अधीन रहते हुए आरोपित अपराध का दोषी होने का अभिवचन कर सकेगा।

75. दोषी होने का अभिवचन स्वीकार करना—(1) जहाँ कोई अभियुक्त नियम 74 के उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन किसी अपराध का दोषी होने का अभिवचन करता है, वहाँ पीठासीन आफिसर

या जजमर्टनी, न्यायालय द्वारा अभिवचन स्वीकार करने का विनिर्देश किए जाने से पूर्व, आरोप की प्रकृति और उसके अभिवचन का साधारण प्रभाव और विनिष्टतया अभियुक्त के दोषी होने के अभिवचन और दोषी न होने के अभिवचन के कारण प्रक्रिया का अंतर अभियुक्त को स्पष्ट करेगा।

(2) न्यायालय जब अभियोजक के साक्ष्य का अभिलेख या सार न्यायालय में पढ़कर सुनवाएगा या न्यायालय को उसमें दिए गए तथ्यों को सूचित करेगा।

परन्तु यदि साक्ष्य के अभिलेख या सार की कोई परिशोधन प्रति पीठासीन आफिसर को भेजी गई थी तो अभियोजक न्यायालय को साक्ष्य के अभिलेख या सार के ऐसे भाग को पढ़कर नहीं सुनाएगा जिसका परिशोधन किया गया है या न्यायालय को उन भागों में दिए गए तथ्य सूचित नहीं करेगा और न्यायाय को साक्ष्य का मूल अभिलेख या सार तब तक नहीं देगा जब तक कि विचारण समाप्त नहीं हो जाता। जहाँ कोई अभिलेख या साक्ष्य का सार नहीं है वहाँ न्यायालय दण्ड का अवधारण करने में अपने को समर्थ बनाने के लिए इन नियमों के अनुसार पर्याप्त साक्ष्य अभिलिखित करेगा।

(3) न्यायालय नियम 77 के उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन दोषी होने का अभिवचन उस दशा में स्वीकार नहीं करेगा, यदि—

(क) न्यायालय का यह समाधान नहीं होता है कि अभियुक्त आरोप की प्रकृति या वह अपने अभिवचन का प्रभाव समझता है, या

(ख) पीठासीन आफिसर का साक्ष्य के अभिलेख में अंतर्विष्ट साक्ष्य या साक्ष्य के सार और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह विचार हो कि अभियुक्त को दोषी न होने का अभिवचन करना चाहिए, या

(ग) अभियुक्त शोषित होने पर मृत्यु वण्ड का भागी है।

(4) (क) नियम 76 के अधीन दोषी होने के अभिवचन की दशा में, न्यायालय अभिवचन तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक संयोजक आफिसर सहमत नहीं होता है और ऐसी कार्यवाही के न्यायोचित होने के बारे में उसका समझाने नहीं हो जाता है,

(ख) संयोजक आफिसर की सहमति अभियोजक द्वारा संशोधित की जा सकेगी।

(5) जब दोषी होने का अभिवचन नियम 74 के उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है या अभियुक्त आरोप पर अभिवचन करने से इंकार करता है या वह उस पर स्पष्ट रूप से अभिवचन नहीं करता है तो तब न्यायालय दोषी न होने का अभिवचन अभिलिखित करेगा।

(8) जब न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि वह नियम 74 के उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन दोषी होने का अभिवचन उचित रूप से स्वीकार कर सकता है तो वह उस बाबत दोषी होने का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(7) न्यायालय अपने निष्कर्ष अभिलिखित करने के पश्चात् अभियुक्त को चरित्ता का साक्ष्य पेश करने के लिए और बंड को कम करने के संबंध में कोई कथन करने के लिए अवसर देगा।

(8) यदि अभियुक्त द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और उपनियम (7) के अधीन किए गए उसके कथन से न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अभियुक्त ने दोषी होने के अभिवचन के प्रभाव को तभी समझा था तो वह अभिलेख में परिवर्तन कर सकेगा और दोषी न होने का अभिवचन की प्रविष्टि कर सकेगा तथा तदनुसार विचारण के लिए अग्रसर हो सकेगा।

(9) उपनियम (7) का अनुपालन किए जाने के पश्चात् और यदि न्यायालय ने दोषी होने के अभिवचन को स्वीकार करने का विनिश्चय किया है तो, न्यायालय नियम, 97 के निर्देशानुसार अग्रसर होगा।

76. आनुकूल्यिक आरोप की बाबत अभिवचन (1) जब अभियुक्त दो या अधिक आनुकूल्यिक आरोपों में से प्रथम की बाबत दोषी होने का अभिवचन करता है तब न्यायालय, यदि वह अभियुक्त का दोषी होने का अभिवचन स्वीकार करता है तो, प्रथम आरोप की बाबत दोषी होने का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा, और अभियोजक उस पर अभियुक्त को दोषारोपित किए जाने से पूर्व आनुकूल्यिक आरोप को वापस ले लेगा।

(2) जब अभियुक्त ऐसे दो या अधिक आरोपों में से, जो आनुकूल्यिक के रूप में अधिकृत किए गए हैं, उसे प्रथम आरोपों से भिन्न किसी एक आरोप की बाबत दोषी होने का अभिवचन करता है तब न्यायालय—

(क) इस प्रकार अग्रसर हो सकेगा मानो अभियुक्त ने सब आरोपों की बाबत दोषी नहीं होने का अभिवचन किया है, या

(ख) (i) संयोजक आफिसर की सहमति से (जो अभियोजक द्वारा संज्ञापित की जा सकेगी) उस आरोप की बाबत, जिसका अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवचन किया है, दोषी होने का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा और किसी उस आनुकूल्यिक आरोप की बाबत जो आरोप पत्र में इसके पूर्व हैं, दोषी न होने का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा।

(ii) जहां न्यायालय ऐसा निष्कर्ष अभिलिखित करता है, वहां अभियोजक उस पर अभियुक्त को दोषारोपित किए जाने से पूर्व किसी ऐसे आरोप को वापस ले लेगा जो उस आरोप का अनुकूल्यी है जिसके लिए न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया है और जो आरोप पत्र में उसके उसके पश्चात् है।

77. दोषी होने और दोषी न होने के अभिवचन की दशा में विचारण का आदेश—(1) दोषी होने का निष्कर्ष अभिलिखित करने के पश्चात् न्यायालय यदि उसी आरोप-पत्र में ऐसा अन्य आरोप नहीं है जिसकी बाबत अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवचन किया है और कोई ऐसा अभिवचन नहीं है जिसने उन आरोप-पत्र के किसी आरोप की बाबत दोषी न होने का अभिवचन किया है तो, यह नियम 75 के निर्देशानुसार विचारण के लिए अग्रसर होगा।

(2) जहां आरोप-पत्र में ऐसा अन्य आरोप है जिसकी बाबत अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवचन किया है या ऐसा अन्य अभियुक्त है जिसने उस आरोप-पत्र में किसी आरोप की बाबत दोषी न होने का अभिवचन किया है वहां न्यायालय नियम 75 का तब तक अनुपालन नहीं करेगा जब तक उमने ऐसे अन्य आरोप की बाबत कार्यवाई नहीं कर ली है या उमने ऐसे अन्य अभियुक्त का विचारण नहीं कर लिया है और उनकी बाबत अपना निष्कर्ष वापिस और अभिलिखित नहीं कर दिया है।

78. अभिवचन का परिवर्तन—(1) दोषी न होने का अभिवचन करने वाला अभियुक्त न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष पर विचार-विमर्श समाप्त किए जाने से पूर्व किसी भी समय दोषी न होने के अपने अभिवचन को वापिस ले सकेगा और उसके स्थान पर दोषी होने का अभिवचन (जिनके संबंधित नियम 76 के अधीन दोषी होने का अभिवचन भी है) कर सकेगा और ऐसी दशा में न्यायालय यदि उमका यह समाधान हो जाता है कि वह इन नियमों के अधीन अभियुक्त का परिवर्तित अभिवचन स्वीकार कर सकता है तो अभियुक्त के परिवर्तित अभिवचन के अनुसार निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और जहां तक अवश्यक हो नियम 75 के निर्देशानुसार अग्रसर होगा।

(2) जहां विचार के दौरान किसी भी समय न्यायालय को यह पता होता है कि वह अभियुक्त जिसने दोषी होने का अभिवचन किया है अपने अभिवचन के प्रभाव को या आरोप की प्रकृति की गंभीर समझता है तो न्यायालय दोषी न होने का अभिवचन प्रविष्टि करेगा और तदनुसार विचारण के लिए अग्रसर होगा।

(3) जब न्यायालय उपनियम (2) के अधीन किसी आरोप की बाबत दोषी न होने का अभिवचन अभिलिखित करता है तब वह यदि उसके अनुकूल्यिक के रूप में कोई ऐसा आरोप अधिकृत या जिससे अभियोजक ने नियम 76 के अधीन वापिस ले लिया था तो ऐसे आनुकूल्यिक आरोप को पुनः स्थापित करेगा उस पर अभियुक्त को दोषारोपित करेगा और विचारण के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह कभी भी वापिस नहीं लिया गया था।

79. दोषी न होने के अभिवचन प्रक्रिया—किसी आरोप की बाबत दोषी न होने का अभिवचन अभिलिखित किये जाने के पश्चात्—

(i) न्यायालय अभियुक्त ने पूछेगा कि क्या इस आधार पर कि विचारण के पूर्व की प्रक्रिया से संबंधित इन नियमों में से किसी का अनुपालन नहीं किया गया है और इसका उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या इस आधार पर कि उसे अपनी प्रतिरक्षा को तैयार करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिला है, स्थगन के लिए आवेदन करना चाहता है,

'(ii) जहां अभियुक्त स्थगन के लिए आवेदन करता है, वहां:

(क) अभियुक्त अपने अधिवक्ता के समर्थन में साक्ष्य पेश कर सकेगा और अभियोजक उसके उत्तर में साक्ष्य पेश कर सकेगा।

(ख) अभियोजक आवेदन के उत्तर में न्यायालय को संतुष्टित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक के संबंधित का उत्तर दे सकेगा।

(iii) यदि न्यायालय समझता है कि न्याय के हित में ऐसा अपेक्षित है तो वह स्थगन मंजूर कर सकेगा।

80. आरम्भिक सम्बोधन—(1) अभियोजक, यदि वह चाहे तो आरम्भिक सम्बोधन कर सकेगा यदि और न्यायालय द्वारा ऐसा करने की प्रपेक्षा की जाए तो ऐसा करेगा, जिसमें वह आरोप और उस साक्ष्य की प्रकृति और साधारण प्रभाव को स्पष्ट करेगा जो वह पेश करने की प्रस्तावना करता है।

(2) तब अभियोजन के लिए साक्षी बुलाए जाएंगे और वे अपना साक्ष्य देंगे।

81. प्रतिरक्ति साक्षी—जहां अभियोजक ऐसा साक्ष्य पेश करने का आशय रखता है, तो अभियुक्त को दिए गए साक्ष्य के किसी अभिलेख या सार में सम्मिलित नहीं है, वहां, साक्ष्य की विविधियों सहित, ऐसे आशय की सूचना, जब संभव हो, अभियुक्त को साक्ष्य पेश करने से उचित समय पूर्व दी जाएगी। यदि ऐसा साक्ष्य ऐसी सूचना या विविधियों दिए बिना पेश किया जाता है तो न्यायालय, यदि अभियुक्त चाहे तो, साक्ष्य देने के पश्चात् या तो स्वीकार कर सकेगा या उस साक्ष्य से उद्भूत प्रति-परीक्षा को मुक्तवीकर सकेगा और न्यायालय अभियुक्त को सूचित करेगा कि उसे ऐसे स्थगन या सूचना के लिए आवेदन करने का अधिकार है।

82. साक्षियों को छोड़ना :—अभियोजक, अभियुक्त के विरुद्ध उन सब साक्षियों को, जिनका साक्ष्य, साक्ष्य के अभिलेख या सार में है, बुलाने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही वह किसी ऐसे साक्षी को बुलाने के लिए बाध्य होगा जब वह अभियुक्त को यह सूचित कर चुका है कि वह नियम 81 के अधीन बुलाने का आशय रखता है, किन्तु यदि अभियोजक साक्ष्य देने के लिए ऐसे साक्षी को बुलाने का आशय नहीं रखता है तो वह या तो उसे अभियुक्त द्वारा प्रति-परीक्षा के लिए पेश करेगा या अभियुक्त को युक्तियुक्त सूचना देगा कि वह साक्षी को बुलाने का आशय नहीं रखता है और अभियुक्त को उससे पत्र-व्यवहार और यदि वह चाहे और साक्षी उपलब्ध हो तो उसे प्रतिरक्षा की ओर से साक्षी के रूप में बुलाने की अनुज्ञा दी जाएगी।

83. साक्षियों का वापस लिया जाना :—विचारण के दौरान, अभियोजक या अभियुक्त को छोड़कर, कोई साक्षी न्यायालय की इजाजत के बिना न्यायालय में तब नहीं रहेगा जब उसकी परीक्षा नहीं चल रही है और यदि उसकी परीक्षा चलने के दौरान उसकी परीक्षा की बाबत कोई प्रश्न अनुज्ञात करने या न करने के बारे में कोई विचार-विमर्श होता है तो न्यायालय ऐसे विचार-विमर्श के दौरान साक्षी को वापस आने के लिए निदेश दे सकेगा।

84. साक्षियों की परीक्षा :—(1) किसी साक्षी की परीक्षा उसे बुलाने वाले व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी और कार्यवाही के विरोधी पक्ष-कार द्वारा उसकी प्रति-परीक्षा की जा सकेगी और ऐसी प्रति-परीक्षा की समाप्ति पर, प्रति-परीक्षा से उद्भूत विषयों के संबंध में उसकी उस व्यक्ति द्वारा पुनः परीक्षा की जा सकेगी जिन्होंने उसे बुलाया है।

(2) (क) किसी साक्षी की परीक्षा करने वाला व्यक्ति साक्षी से प्रश्न मौखिक तौर पर पूछेगा और जब तक कि साक्षी, न्यायालय जज-अटर्नी, अभियोजक या अभियुक्त द्वारा कोई आक्षेप नहीं किया जाता, साक्षी तत्काल उत्तर देगा।

(ख) जहाँ ऐसा आक्षेप किया जाता है, वहाँ साक्षी तब तक उत्तर नहीं देगा जब तक आक्षेप निपटा नहीं दिया जाता।

(3) न्यायालय साक्षी की प्रति-परीक्षा या पुनः परीक्षा का मुक्तकी किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा।

(4) साक्षी की परीक्षा करने से पूर्व उसे निम्नलिखित प्रश्न में या समान आशय के ऐसे अन्य प्रश्न में, जैसा न्यायालय उसके धर्म के अनुसार या अन्यथा जो उसके प्रत्यक्ष-करण पर आवश्यक हो, अभिविधित करे, शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा।

शपथ का प्रारूप

मैं-----सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं जो कुछ कहूँगा सत्य कहूँगा, पूर्ण सत्य कहूँगा और सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा।

प्रतिज्ञान का प्रारूप

मैं-----सत्यनिष्ठ सद्भाव, और सम्मार्थ से श्रवण करता हूँ और प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं जो कुछ कहूँगा सत्य कहूँगा, पूर्ण सत्य कहूँगा और सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा।

85. न्यायालय द्वारा प्रश्न :—(1) पीठासीन अधिकार, जज-अटर्नी और न्यायालय का कोई सदस्य साक्षी से प्रश्न पूछ सकेगा।

(2) ऐसे प्रश्न का उत्तर दिए जाने पर, अभियोजक और अभियुक्त साक्षी से उस उत्तर से उद्भूत, जो वह देखे चुका है, ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जिन्हें न्यायालय उचित समझे।

86. साक्ष्य का पढ़कर सुनाया जाना :—(1) (क) साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य का अभिलेख उसे, उसके न्यायालय छोड़ने से पूर्व, पढ़कर सुनाया जाएगा और ऐसा किए जाने पर वह अभिलेख को शुद्ध करने के लिए कह सकेगा या उस साक्ष्य को स्पष्ट कर सकेगा जो उसने दिया है।

(ख) जहाँ कोई ऐसी शुद्धि की जाती है या स्पष्टीकरण दिया जाता है, वहाँ अभियोजक और अभियुक्त उस साक्षी से शुद्धि या स्पष्टीकरण के बारे में ऐसे प्रश्न पूछ सकेंगे जिन्हें न्यायालय उचित समझे।

(2) जब आशुलिपि-लेखक नियोजित किया जाए तब उपनियम (1) का अनुपालन करना आवश्यक नहीं होगा, यदि न्यायालय और जज-अटर्नी (यदि कोई है) की राय में ऐसा करना अनुपयोगिक है :—

परन्तु यदि कोई साक्षी ऐसी मांग करता है तो उपनियम (1) का अनुपालन किया जाएगा।

87. न्यायालय द्वारा साक्षियों को बुलाया जाना या पुनः बुलाया जाना :—

(1) (क) न्यायालय अपने निष्कर्ष पर विचार-विमर्श की समाप्ति से पूर्व या यदि कोई जज-अटर्नी है तो, उसके द्वारा उपसंहार प्रारम्भ किए जाने से पूर्व किसी समय किसी साक्षी को उस वक्ता में बुला सकेगा या पुनः बुला सकेगा, जब न्यायालय की राय में ऐसा करना न्याय के हित में है,

(ख) जहाँ न्यायालय इस नियम के अधीन किसी साक्षी को बुलाता है या पुनः बुलाता है वहाँ अभियोजक और अभियुक्त साक्षी से ऐसे प्रश्न पूछ सकेंगे जिन्हें न्यायालय उचित समझे।

(2) अभियोजक और अभियुक्त, न्यायालय द्वारा निष्कर्ष पर विचार-विमर्श की समाप्ति से पूर्व या यदि कोई जज-अटर्नी है तो उसके द्वारा उपसंहार प्रारम्भ किए जाने से पूर्व किसी समय, किसी साक्षी को न्यायालय की इजाजत से पुनः बुला सकेंगे और अभियोजक तथा अभियुक्त उस साक्षी से ऐसे प्रश्न पूछ सकेंगे जिन्हें न्यायालय उचित समझे।

88. उत्तर के लिए कोई मामला प्रस्तुत न करना और भासलों को रोकना :—(1) (क) अभियोजन की ओर से पक्ष कथन की समाप्ति पर अभियुक्त किसी आरोप की बाबत न्यायालय से यह निवेदन कर सकेगा कि अभियोजन पक्ष अपनी ओर से प्रथम दृष्टया ऐसा मामला सिद्ध करने में असफल रहा है जिसका उसके द्वारा उत्तर दिया जाए और उस आरोप पर उसे अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए,

(ख) जहाँ अभियुक्त ऐसा निवेदन करता है वहाँ अभियोजक उसके उत्तर में न्यायालय को सम्बोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक के सम्बोधन का उत्तर दे सकेगा।

(2) न्यायालय निवेदन को तब तक संजूर नहीं करेगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि :—

(क) अभियोजन ने अधिरुधित आरोप की बाबत प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध नहीं किया है, और

(ख) उसे साक्ष्य पर यह तो धारा 90 या नियम 95 के उपनियम (4) के अधीन विशेष निष्कर्ष निकालने की छुट नहीं है।

(3) (क) जहाँ न्यायालय निवेदन को अनुज्ञात करता है वहाँ वह अभियुक्त को उस आरोप की बाबत जिसके संबंध में वह है, बोली नहीं उठायेंगे और निष्कर्ष को, मुष्टि के अधीन रखे हुए, खुले न्यायालय में तत्काल सुनाया जाएगा।

(ख) जहाँ न्यायालय निवेदन को अनुज्ञात करता है वहाँ वह आरोपित रूप में अपराध के विचारण के लिए अपसर होगा।

(4) न्यायालय अभियोजन की ओर से पक्षकथन की सुनवाई की समाप्ति के पश्चात् ओर अभियोजक को सुनने के पश्चात्, स्वप्रेरणा से, अभियुक्त को आरोप की वाबत निर्दोश ठहरा सकेगा और निष्कर्ष को, पुष्टि के अधीन रहते हुए, खुले न्यायालय में तत्काल सुनाया जाएगा।

89. प्रतिरक्षा के लिए पक्षकथन—(1) अभियोजन की ओर से पक्षकथन की समाप्ति पर, पीठासीन अधिकार जजजटर्नी (यदि कोई है) अभियुक्त को यह स्पष्ट करेगा कि—

(क) यदि वह चाहे तो साक्षी के रूप में शपथ पर साक्ष्य दे सकता है या शपथ लिए बिना कथन कर सकता है किन्तु वह इनमें से कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं है,

(ख) यदि वह शपथ पर साक्ष्य देता है तो अभियोजक द्वारा उसकी प्रतिरोक्षा की जा सकेगी और न्यायालय द्वारा उससे प्रश्न पूछे जा सकेंगे।

(2) अभियुक्त को अपने विरुद्ध साक्ष्य के प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों को स्पष्ट करने में सहाय्य बनाने के प्रयोजन के लिए, न्यायालय विचारण के किसी प्रक्रम पर अभियुक्त को पूर्व चेतावनी दिए बिना उसमें ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जिन्हें न्यायालय आवश्यक समझे और अभियोजन के साक्षियों की परीक्षा के पश्चात् और अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा के लिए बुलाने के पूर्व पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उससे मामले के संबंध में साधारणतः प्रश्न पूछेगा।

(3) अभियुक्त ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करने के कारण या उनके मिथ्या उत्तर देने के कारण धष्ट का भागी नहीं होगा।

(4) अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों पर ऐसे विचारण में विचार किया जा सकेगा और ऐसे उत्तर किसी अन्य अपराध की जो ऐसे उत्तरों से यह दणित हो कि उसने किया है, किसी अन्य िष में या उसके विचारण में उसके पक्ष में या उसके विरुद्ध साक्ष्य में रखे जा सकेंगे।

(5) यदि अभियुक्त मामले के तथ्यों के लिए अपने से भिन्न कोई साक्षी बुलाना चाहता है तो वह प्रतिरक्षा के लिए साक्ष्य दिए जाने से पूर्व प्रतिरक्षा के मामले की रूपरेखा बताते हुए आरम्भिक सम्बोधन कर सकेगा।

90. प्रतिरक्षा के लिए साक्षी—(1) नियम 89 का अनुपालन किए जाने के पश्चात् प्रतिरक्षा के लिए साक्षियों को (यदि कोई हैं) अपना साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाएगा।

(2) नियम 84, 85 और 86 के संबंध प्रतिरक्षा के लिए साक्षियों को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे अभियोजन के लिए साक्षियों के साक्ष्य को लागू होते हैं।

91. ऊपर में साक्षी—प्रतिरक्षा के लिए साक्षियों द्वारा अपना साक्ष्य दिए जाने के पश्चात् अभियोजक, अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में उठाए गए किसी ऐसे विषय पर, जिसे अभियोजन पक्ष अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा प्रकट किए जाने से पूर्व न्यायालय को उचित रूप से दणित नहीं कर सका या जिसका अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त रूप से पूर्व कल्पना नहीं कर सकता था, साक्ष्य देने के लिए किसी साक्षी को न्यायालय की इजाजत से बुला सकेगा या पुनः बुला सकेगा।

92. सम्बोधनों का समापन—(1) सभी साक्ष्य दिए जाने के पश्चात् अभियोजक और अभियुक्त में से प्रत्येक न्यायालय को समापन सम्बोधन कर सकेगा।

(2) अभियुक्त, अभियोजक द्वारा समापन सम्बोधन किए जाने के पश्चात् अपना समापन सम्बोधन करने का हकदार होगा जब तक कि अभियुक्त ने तथ्यों के लिए अपने से भिन्न कोई साक्षी नहीं बुलाया है और ऐसे मामले में अभियोजक, अभियुक्त द्वारा समापन सम्बोधन किए जाने के पश्चात् अपना समापन सम्बोधन करने का, उपनियम (3) और (4) के अधीन रहते हुए, हकदार होगा।

(3) जहाँ दो या अधिक अभियुक्तों का एक साथ विचारण किया जाता है, वहाँ उनमें से कोई एक, जिसे ऐसा कोई साक्षी नहीं बुलाया है, अभियोजक के समापन सम्बोधन के पश्चात् अपना समापन सम्बोधन करने का हकदार होगा।

(4) (क) जहाँ दो या अधिक अभियुक्तों का एक ही प्रतिरक्षा अधिकार या काउन्सेल प्रतिनिधित्व कर रहा है, वहाँ यह केवल एक समापन सम्बोधन कर सकेगा,

(ख) जहाँ किसी अभियुक्त ने, जिसके लिए वह उपस्थित होता है, तथ्यों के लिए अपने से भिन्न कोई साक्षी नहीं बुलाया है, वहाँ ऐसा प्रतिरक्षा अधिकार या काउन्सेल अभियोजक द्वारा समापन सम्बोधन किए जाने के पश्चात् अपना सम्बोधन करने का हकदार होगा।

93. जजजटर्नी द्वारा उपसंहार—समापन सम्बोधन के पश्चात् यदि जजजटर्नी है तो वह खुले न्यायालय में साक्ष्य का उपसंहार करेगा और मामले से संबंधित विधि पर न्यायालय को सलाह देगा।

94. निष्कर्ष पर विचार-विमर्श—(1) न्यायालय जजजटर्नी की उपस्थिति में बंद न्यायालय में अपने निष्कर्ष पर विचार-विमर्श करेगा।

(2) न्यायालय का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष के बारे में अपनी राय मौखिक रूप से कनिष्ठतम रैंक से प्रारंभ करके, पृथक् रूप से देगा।

95. निष्कर्ष का अभिलेख और सुनाया जाना—(1) प्रत्येक आरोप पर, जिस पर अभियुक्त को दोषारोपित किया जाता है, निष्कर्ष अभिलिखित किया जाएगा और इन नियमों में जैसा उपबंधित है उसके निवाय “बोधी होते” या “बोधी न होने” के निष्कर्ष के रूप में ही अभिलिखित किया जाएगा।

(2) जहाँ किसी आरोप की वाबत न्यायालय की राय है कि साबित किए गए तथ्यों से आरोपित अपराध या ऐसा कोई अपराध प्रकट नहीं होता है जिसका वह लगाए गए आरोप पर अभिनियम के अधीन वैध रूप से बोधी ठहराया जा सके, वहाँ न्यायालय अभियुक्त को उस आरोप से दोषमुक्त कर देगा।

(3) यदि न्यायालय को किसी आरोप के बारे में ऐसा संदेह है कि साबित किए गए तथ्यों से यह दणित होता है या नहीं कि अभियुक्त पर लगाए गए आरोप का बोधी है, तो वह उस आरोप पर निष्कर्ष अभिलिखित करने से पूर्व, उन तथ्यों को अपवर्णित करने हुए जिसके बारे में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वे साबित हो गए हैं, पुष्टि करने वाले प्राधिकारी को उसकी राय के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा और यदि आवश्यक हो तो उस प्रयोजन के लिए स्थगित कर सकेगा।

(4) जहाँ किसी आरोप के बारे में न्यायालय की राय है कि वे तथ्य, जिनके बारे में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वे साक्ष्य से साबित हो गए हैं, आरोप की विशिष्टियों के कथन में अधिकथित तथ्यों से तात्त्विक रूप से भिन्न हैं किन्तु ऐसा होने पर भी वे आरोप में कथित अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं और बिना इतनी तात्त्विक नहीं है जिससे कि अभियुक्त पर उसकी प्रतिरक्षा में उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, वहाँ वह “बोधी न होने” के निष्कर्ष के बजाय विशेष निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(5) विशेष निष्कर्ष में अभियुक्त को, उनमें विनिर्दिष्ट प्रस्तावों या परिवर्तनों के अधीन रहते हुए, किसी आरोप का बोधी ठहराया जा सकेगा।

(6) जहाँ आनुकूलिक आरोप हैं और साबित तथ्यों से न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि उनमें उन आनुकूलिक आरोपों में से किसी में दणित अपराध नहीं बनता है, वहाँ न्यायालय उस आरोप पर “बोधी न होने” का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(7) यदि एक आरोप पर दोषसिद्धि से आवश्यक रूप से अनुकूलनी आरोप या आरोपों का बोधी होने का संकेत मिलता हो तो भी न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचेगा कि अभियुक्त अनुकूलतः अधिलिखित दो या अधिक आरोपों में से एक से अधिक का बोधी है।

(8) यदि न्यायालय का विचार है कि साबित तथ्यों से कोई ऐसा अपराध बनता है जो दो या अधिक अनुकूलनी आरोपों में कथित अपराधों में से एक है किन्तु उसे संदेह है कि उन तथ्यों से विधि की दृष्टि में कौन सा अपराध बनता है, तो वह उन आरोपों पर निष्कर्ष अभिलिखित करने से पूर्व उन तथ्यों को जिनके बारे में वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वे साबित हो गए हैं, उपरिगणित करते हुए और यह कथित करते हुए, कि उसे संदेह है कि विधि की दृष्टि में उन तथ्यों से ऐसे एक या अन्य आरोपों में कथित अपराध बनता है या नहीं, पुष्टि करने वाले प्राधिकारी को उसकी राय के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा और यदि आवश्यक हो तो उस प्रयोजन के लिए स्थगित कर सकेगा।

(9) प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष, पुष्ट किए जाने के अधीन रहते हुए, खुले न्यायालय में तत्काल सुनाया जाएगा।

96. दोषमुक्त किए जाने पर प्रक्रिया—यदि सभी आरोपों की बाबत “बोधी न होने” का निष्कर्ष है तो पीठासीन अधिकार निष्कर्ष पर तारीख डाल कर हस्ताक्षर करेगा और ऐसे हस्ताक्षर से सम्पूर्ण कार्यवाही अधि-प्रमाणित हो जाएगी और जजमर्टनी (यदि कोई है) द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर कार्यवाहियां पुष्टि के लिए तुरंत परेपिन कर दी जाएगी।

97. दोषसिद्धि पर प्रक्रिया—(1) यदि किसी आरोप की बाबत “बोधी होने” का निष्कर्ष है तो न्यायालय, आरोप के लिए दण्डादेशप्रवर्धन करने में अपने मार्गदर्शन के लिए और दण्डादेश पर विचार करने के लिए पुष्टिकर्ता प्राधिकारी के मार्गदर्शन के लिए, दण्डादेश पर विचार-विमर्श करने से पूर्व, अभियुक्त के साधारण खरिद, घास सेवा, रैक और शीर्ष के किन्हीं मान्यता प्राप्त कार्यों का या उसके विशिष्ट आचरण का और सुरक्षक या बंद न्यायालय द्वारा अभियुक्त की पूर्ण दोषसिद्धियों का यथास्थिति, धारा 51, 53 या 54 के अधीन प्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी अधिकार द्वारा उसके बारे में अधिनिर्णीत किए गए किन्हीं पूर्ण दंडों का, उस अवधि का जिसमें वह किसी पूर्ण दंड के कारण गिरफ्तार या परिरुद्ध रहा है और किसी अलंकरण या इनाम का, जो उसके कब्जे में है या जिसका वह हकदार है, जब कभी सम्भव हो साक्ष्य लेगा और उसे अभिलिखित करेगा।

(2) उपर्युक्त मामलों पर साक्ष्य किसी साक्षी द्वारा ऐसा कथन, जिसमें अभियुक्त की बाबत सेवा पुस्तिकाओं में का प्रविष्टियों को संक्षिप्त होगा, सत्यापित करके और अभियुक्त की उस संक्षिप्ति में निर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में पहचान करके दिया जा सकेगा।

(3) अभियुक्त किसी ऐसे साक्षी की प्रतिपरीक्षा कर सकेगा और ऐसे साक्ष्य का खंडन करने के लिए साक्षियों को बूला सकेगा और यदि अभियुक्त ऐसा निवेदन करता है तो सेवा पुस्तिकाएं या उनमें की तत्त्विक प्रविष्टियों की सम्पत्तः प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जाएगी और यदि अभियुक्त यह अभिलेखित करता है कि संक्षिप्ति किसी विषय में, यथास्थिति, सेवा पुस्तिकाओं या ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपि के अनुसार नहीं है, तो न्यायालय संक्षिप्ति का मिलान उन पुस्तिकाओं या प्रतिलिपि से करेगा और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि संक्षिप्ति उनसे अनुसार नहीं है तो वह संक्षिप्ति को शुद्ध कराएगा या अभियुक्त का आरोप अभिलिखित कराएगा।

(4) जब उपर्युक्त मामलों पर भी सभी साक्ष्य दे दिया गया हो तब अभियुक्त उसके बारे में और दंड तन करने के बारे में न्यायालय को सम्बोधित कर सकेगा।

98. दंडादेश—न्यायालय उन सब अपराधों की बाबत अभियुक्त को दोषी पाया जाता है, एक दण्डादेश अधिनिर्णीत करेगा और ऐसा दण्डादेश उनकी बाबत, जिनकी बाबत वह वैध रूप से दिया जा सकता है, अधि-निर्णीत किया गया माना जाएगा और जिनकी बाबत वह वैध रूप से नहीं दिया जा सकता है, अधिनियम अधिनिर्णीत किया गया नहीं समझा जाएगा।

99. दया की सिफारिश—(1) जहाँ न्यायालय दया की सिफारिश करता है, यहाँ वह अपनी ऐसी सिफारिश के कारण देगा।

(2) इस नियम में उल्लिखित दया या उससे संबंधित किसी प्रश्न के बारे में सिफारिश करने वाले न्यायालय के सदस्यों की संख्या की कार्यवाहियों में प्रविष्टि की जा सकेगी।

100. दण्डादेश सुनाया जाता और कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर और उनका परेपिन—(1) दया का सिफारिश और ऐसी सिफारिश के कारणों के साथ दण्डादेश न्यायालय में तत्काल सुनाया जाएगा। दण्डादेश पुष्ट किए जाने के अधीन रहते हुए सुनाया जाएगा।

(2) न्यायालय द्वारा दण्डादेश अधिनियमनिर्णीत किए जाने पर पीठासीन अधिकार दंडादेश पर तारीख डाल कर हस्ताक्षर करेगा और ऐसे हस्ताक्षरों से सम्पूर्ण कार्यवाही अधिप्रमाणित हो जाएगी और कार्यवाहियां अज मर्टनी (यदि कोई है) द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर तुरंत पुष्टि के लिए परिचित की जाएगी।

101. पुनरीक्षण—(1) (क) जहाँ निष्कर्ष धारा 100 के अधीन पुनरीक्षण के लिए वापस भेजा जाता है, वहाँ न्यायालय खुले न्यायालय में पुनः समक्ष होगा, पुनरीक्षण आवेदन पढ़ कर सुनाया जाएगा और यदि न्यायालय को नए सिरे से साक्ष्य लेने का निदेश है तो, ऐसा साक्ष्य खुले न्यायालय में लिया जाएगा।

(ख) जहाँ ऐसा नया साक्ष्य अभियुक्त की प्रेरणा से अन्यथा अधि-लिखित किया जाता है, वहाँ अभियुक्त को ऐसे नए साक्ष्य में लाए गए विषयों की बाबत साक्ष्य पेश करने के लिए और अवसर दिया जाएगा;

(ग) अभियोजक और अभियुक्त को पेश किए गए नए साक्ष्य की बाबत न्यायालय को सम्बोधित करने के लिए और अवसर दिया जाएगा;

(घ) अज मर्टनी भी और उपसंहार कर सकेगा।

(2) जहाँ निष्कर्ष के पुनरीक्षण में नया साक्ष्य का लिया जाना आवश्यक नहीं है, वहाँ अभियुक्त को पुनरीक्षण आवेदन में उठाए गए विषय की बाबत न्यायालय को सम्बोधित करने का अवसर दिया जाएगा।

(3) (क) तब न्यायालय अपने निष्कर्ष पर बंद न्यायालय में विचार-विमर्श करेगा और यदि न्यायालय अपने पूर्ण निष्कर्ष पर बंध नहीं रहता है तो वह निष्कर्ष और दण्डादेश का प्रसिंहकरण करेगा और नया निष्कर्ष अधि-लिखित करेगा और यदि ऐसे नए निष्कर्ष में दण्डादेश अन्तर्भूत है तो नया दण्डादेश पारित करेगा।

(ख) जहाँ मूल निष्कर्ष “बोधी न होने” का हो, वहाँ न्यायालय दण्डा-देश पारित करने से पूर्व नियम 97 और 98 का अनुपालन करेगा।

(4) (क) जहाँ केवल दण्डादेश ही पुनरीक्षण के लिए वापस भेजा जाता है, वहाँ पुनरीक्षण आवेदन खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया जाएगा और अभियुक्त को पुनरीक्षण आवेदन में निर्दिष्ट विषयों की बाबत न्यायालयों को सम्बोधित करने का अवसर दिया जाएगा।

(ख) तब न्यायालय अपने दण्डादेश पर बंद न्यायालय में पुनः विचार करेगा और यदि वह दण्डादेश पर बंध नहीं रहता है तो दण्डादेश का प्रसिंहकरण करेगा और नया दण्डादेश पारित करेगा।

(5) जहाँ केवल दण्डादेश ही पुनरीक्षण के लिए भेजा जाता है, वहाँ न्यायालय निष्कर्ष का पुनरीक्षण नहीं करेगा।

102. पुष्टि और प्रख्यापन—(1) जब पुष्टिकर्ता प्राधिकारी न्यायालय की कार्यवाहियों का अभिलेख प्राप्त करता है, तब वह उस पर और किसी ऐसे दण्डादेश और आदेश पर जो न्यायालय से परिशिष्ट 7 में दिए गए समुचित प्ररूप में कार्यवाहियों के अभिलेख पर धारा 102 के अधीन किया है, अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा और उसके विनिश्चय का ऐसा अभिलेख कार्यवाहियों के अभिलेख का भाग होगा।

(2) जब न्यायालय ने नियम 75 के अधीन बोधी होने के अभिवचन को स्वीकार कर लिया है तब पुष्टिकर्ता आफिसर इस बात के होते हुए भी कि न्यायालय ने संयोजक आफिसर की सहमति के बिना अभिवचन स्वीकार किया है, यदि उसकी राय में ऐसा करना न्याय के हित में है तो, उसके निष्कर्ष की पुष्टि कर सकेगा।

(3) (क) जब न्यायालय ने न्यायालय की अधिकारिता के बारे में अभिवचन या विचारण के वर्जन का अभिवचन नामंजूर कर दिया है या आरोप के बारे में किसी आरोप को उलट दिया है तब पुष्टिकर्ता आफिसर के लिए न्यायालय के विनिश्चय का निनिर्दिष्ट रूप से अनुमोदन करना आवश्यक नहीं होगा किन्तु अभिवचन या आरोप से संबंधित आरोप के निष्कर्ष की उसके द्वारा पुष्टि किए जाने में उसके विनिश्चय का अनुमोदन विवक्षित होगा।

(ख) जहाँ वह अभिवचन नामंजूर करने या आरोप उलटने के न्यायालय के विनिश्चय का अनुमोदन नहीं करता है, वहाँ वह अभिवचन या आरोप से संबंधित आरोप के निष्कर्ष की पुष्टि नहीं करेगा।

(4) पुष्टिकर्ता आफिसर किसी मामले में पुष्टि न करने के कारण कथित कर सकेगा किन्तु यदि वह वहाँ, जहाँ न्यायालय ने अधिकारिता के बारे में अभिवचन को या विचारण के वर्जन के अभिवचन को नामंजूर कर दिया है या उसने आरोपों की वास्तविकता किसी आरोप को उलट दिया है, इस कारण पुष्टि नहीं करता है कि वह न्यायालय के इस विनिश्चय का अनुमोदन नहीं करता है, तो वह उप-नियम (1) के अधीन अपना विनिश्चय अभिलिखित करते समय यह कथित करेगा कि उसने इस कारण से पुष्टि रोक ली है।

(5) जहाँ न्यायालय का दण्डादेश अनुचित रूप से अभिवचन अभिव्यक्त किया गया है, वहाँ पुष्टिकर्ता प्राधिकारी दण्डादेश की पुष्टि करने में उसके स्वरूप में परिवर्तन कर सकेगा जिससे कि वह समुचित रूप से अभिव्यक्त किया जाए।

(6) जब कभी यह प्रतीत होता है कि न्यायालय के निष्कर्ष को न्यायाचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है या नियम 75 के उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन बोधी होने का अभिवचन है तब ऐसे निष्कर्ष और उसके परिणामस्वरूप विधिपूर्ण दण्डादेश की पुष्टि की जा सकेगी और यदि पुष्टि की जाती है तो, इस बात के होते हुए भी कि इन नियमों से विचलन हुआ है, ऐसा निष्कर्ष या दण्डादेश उस दशा में विधि-मात्र होगा, जब ऐसे विचलन से अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(7) निष्कर्ष की पुष्टि करते समय पुष्टिकर्ता आफिसर या तो बिना शर्त या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें अभियुक्त स्वीकार करता है, दण्डादेश को धटा कर कम या उसके किसी भाग का पछार कर सकेगा या दंड को धारा 47 में दिए गए दंडों के मापमान में निम्नतर दंड में लघुकृत कर सकेगा।

(8) (क) जब पुष्टिकर्ता आफिसर ने न्यायालय के निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि कर दी है या उस की पुष्टि नहीं की है तब वह, यथा-स्थिति, निष्कर्ष और दण्डादेश तथा इस तथ्य को कि पुष्टि नहीं की गई है, अभियुक्त को प्रख्यापित करने के लिए कार्यवाहियों के अभिलेख को अभिव्यक्त के कर्मांडर को भेजेगा;

(ख) प्रख्यापन का तथ्य, परिशिष्ट 8 में दिए गए प्ररूप में, कार्यवाहियों के अभिलेख में अभिलिखित किया जाएगा।

(ग) जहाँ पुष्टि इस कारण नहीं की गई है कि पुष्टिकर्ता प्राधिकारी अधिकारिता के अभिवचन को या विचारण के वर्जन के अभिवचन को नामंजूर करने या आरोप के प्रति किसी आरोप को उलटने के न्यायालय के विनिश्चय का अनुमोदन नहीं करता है, वहाँ अभियुक्त को इसकी सूचना दी जाएगी।

अध्याय 10

सुरक्षित न्यायालयों की प्रक्रिया और आनुषंगिक विषय

103 सदस्यों का स्थान ग्रहण करना—न्यायालय के सदस्य अपने दैक के अनुसार स्थान ग्रहण करेंगे।

104. पीठासीन आफिसर का उत्तरदायित्व—(1) पीठासीन आफिसर विचारण को उचित ढंग से और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार और न्यायालय के लिए जो रीति उचित हो उससे संचालित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) पीठासीन आफिसर का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि अभियुक्त का विचारण श्रुतापूर्वक किया जाता है और यह कि विचारण के अधीन व्यक्ति के रूप में उसकी स्थिति या उसकी अभिव्यक्ति या वाक्पि की परीक्षा या प्रतिरोधा करने में उनकी प्रयोगिता के कारण या अन्यथा उसका कोई अहित नहीं होता है।

105. अभियोजक और अभियुक्त के सम्बोधन की वास्तविक न्यायालय की शक्ति—(1) अभियोजक का यह कर्तव्य है कि वह न्याय प्रशासन में न्यायालय की सहायता करे, पक्षपात रहित व्यवहार करे, संतुलित संव्यवहार न्यायालय के समक्ष आए और अभियुक्त के पक्ष में किसी साक्ष्य का कोई अनुचित फायदा न उठाए या उसे न दबाए।

(2) अभियोजक किसी ऐसे विषय को, जो उस समय न्यायालय के समक्ष आरोप या आरोपों से सुसंगत नहीं है, निरदिष्ट नहीं कर सकेगा और उसे ऐसा करने से रोकना और अभियोजक की ओर से प्रयुक्त भाषा की किसी अनुचित तीक्ष्णता तथा निषेधना या संयतता की कमी को रोकना न्यायालय का कर्तव्य होगा।

(3) न्यायालय अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा करने में युक्तियुक्त सुविधाएं देगा, अभियुक्त को न्यायालय के प्रति अवमानपूर्ण या अनादरपूर्ण टिप्पणियों करने से और अन्य व्यक्तियों के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने से प्रवृत्त रहना चाहिए, किन्तु वह अपनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए साक्ष्य को अधिभिन कर सकेगा और अन्य व्यक्तियों पर दोषारोपण कर सकेगा और अपराधिकता का आरोप भी लगा सकेगा किन्तु यदि वह ऐसा करता है तो वह उसके कारण उचित दायित्व के अधीन होगा। न्यायालय अभियुक्त को उसकी प्रतिरक्षा की विसंगति के बारे में चेतावनी दे सकेगा, किन्तु जब तक कि विशेष मामला न हो, उसकी प्रतिरक्षा एक मात्र ऐसी विसंगति के आधार पर नहीं रोकेगा।

106. बंद न्यायालय में बैठक—(1) न्यायालय, जहाँ इन नियमों द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए, बंद न्यायालय में अधिवेशन करेगा और सदस्यों के बीच विचार-विमर्श के किसी अन्य मामले में बंद न्यायालय में अधिवेशन कर सकेगा।

(2) बंद न्यायालय में न्यायालय के सदस्यों जत्र अटर्नी (यदि कोई है) और अनुपदेशाधीन किसी आफिसर के निवाय कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं होगा।

(3) इस नियम के पूर्वगामी उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, न्यायालय या तो एकल में जा सकेगा या उस स्थान को ऐसे सभी अन्य व्यक्तियों से बारी कर सकेगा जो वहाँ उपस्थित होने के हक्कार नहीं है।

(4) इस नियम के उप-नियम (1), (2) और (3) में वर्णित के सिवाय सब कार्यवाहियों, जिनके अन्तर्गत किसी स्थान का अवलोकन भी है, खुले न्यायालय में और उपनियम (5) के अधीन रहते हुए, अभियुक्त की उपस्थिति में की जाएगी।

(5) न्यायालय को किसी ऐसे साक्षी को, जिसे अभी साक्ष्य देना है, या अभियुक्त से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को, जो उसकी कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करता है, न्यायालय से अवर्जित करने की, शक्ति होगी।

107. विचारण का जारी रखा जाना और न्यायालय का स्थगन

(1) जब न्यायालय एक बार समवेत कर दिया जाता है और अभियुक्त को दोषारोपित कर दिया जाता है तब न्यायालय इन नियमों के अनुसार विचारण दिन-प्रति-दिन तब तक जारी रखेगा जब तक कि न्यायालय को यह प्रतीत नहीं होता है कि न्याय के उद्देश्य के लिए स्थगन आवश्यक है या विचारण इस प्रकार जारी रखना असाध्य है।

(2) (क) न्यायालय अपनी कार्यवाहियों को समय-समय पर स्थगित कर सकेगा और अपना अधिवेशन ऐसे स्थान पर कर सकेगा जो सुविधाजनक हो, और

(ख) जब कभी आवश्यक हो, घटनास्थल का निरीक्षण कर सकेगा।

(3) स्थल पर वरिष्ठ आफिसर भी, सेवा को असाधारणताओं के कारण, न्यायालय का स्थगन कर सकेगा या स्थगन को बढ़ा सकेगा।

(4) न्यायालय, जज अटर्नी की अनुपस्थिति में (यदि उस न्यायालय के लिए जज अटर्नी नियुक्त किया गया है) कार्यवाही नहीं करेगा और स्थगित हो जाएगा।

(5) यदि वह समय विनिर्दिष्ट नहीं है जिसके लिए स्थगन किया जाता है तो स्थगन उचित मुरक्षक प्राधिकारी का आगे आदेश होने तक के लिए होगा, और, वह स्थान विनिर्दिष्ट नहीं है जिसके लिए स्थगन किया गया है, तो स्थगन उसी स्थान या ऐसे अन्य स्थान के लिए होगा जो उचित मुरक्षक प्राधिकारी के आगे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

108. विचारण का निवर्तन :—जहां, न्यायालय की बैठक के समय उद्भूत किसी बात के परिणामस्वरूप, न्यायालय धारा 68 में विनिर्दिष्ट विघटन के कारण या अन्यथा, विचारण जारी रखने में असमर्थ है तो पीठासीन आफिसर या, उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित वरिष्ठ सदस्य, तत्काल संयोजक प्राधिकारी को तथ्यों की रिपोर्ट भेजेगा।

109. अभियुक्त की मृत्यु या रुग्णता की दशा में कार्यवाहियां—अभियुक्त की मृत्यु या ऐसी रुग्णता की दशा में, जिसके कारण विचारण जारी रखना संभव हो जाए, न्यायालय साक्ष्य लेकर मृत्यु या रुग्णता का तथ्य अभिलिखित करेगा और उसे अभिलिखित करेगा, और स्थगित हो जाएगा और कार्यवाहियों को संयोजक प्राधिकारी को परेषित करेगा।

110. पीठासीन आफिसर की मृत्यु, निवृत्ति या अनुपस्थिति—पीठासीन आफिसर की मृत्यु, आपत्ति के कारण निवृत्ति या अग्रिहाय्य अनुपस्थिति की दशा में, अगला वरिष्ठ आफिसर पीठासीन आफिसर का स्थान ग्रहण करेगा और यदि न्यायालय में अभी भी आफिसरों की कम से कम न्यूनतम संख्या वही है जो विधि के अनुसार अपेक्षित है, तो विचारण जारी रहेगा।

111. न्यायालय के सभी सदस्यों का प्रारम्भ से अंत तक उपस्थित रहना—(1) न्यायालय का वह सदस्य, जो अभियुक्त के विचारण में साक्ष्य के किसी भाग को ग्रहण किए जाने के दौरान अनुपस्थित रहा है, उस न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति के विचारण में आगे कोई भाग नहीं लेगा, किन्तु न्यायालय पर इसका तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक कि उसकी संख्या न्यूनतम विधिक संख्या से कम नहीं हो जाती।

(2) अभियुक्त को दोषारोपित किए जाने के पश्चात् न्यायालय में कोई आफिसर नहीं जोड़ा जाएगा।

112. न्यायालय के सदस्यों की राय लेना—(1) न्यायालय के प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक प्रश्न पर, जिसका न्यायालय को विनिश्चय करना है, मौखिक राय देना आवश्यक, और इस बात के होते हुए भी कि उसने दोषमुक्ति के पक्ष में अपनी राय दी है उसे दण्डादेश के बारे में अपनी राय देना आवश्यक है।

(2) न्यायालय के सदस्यों की राय, रैंक में निम्नतम सदस्य से आरम्भ करके, क्रमानुसार ली जाएगी।

113. आनुषंगिक प्रश्नों की बाबत प्रक्रिया—यदि विचारण के दौरान विधि, साक्ष्य या प्रक्रिया के किसी विषय पर अभियोजक द्वारा या अभियुक्त द्वारा या उसकी ओर से कोई आक्षेप किया जाता है तो (यथा-स्थिति) अभियोजक या अभियुक्त या काउन्सेल या प्रतिरक्षा आफिसर को उसका उत्तर देने का अधिकार होगा और आक्षेप करने वाले व्यक्ति को उसका उत्तर देने का अधिकार होगा।

114. साक्ष्य का कब अनुवाद किया जाएगा—जब कोई साक्ष्य ऐसी भाषा में दिया जाता है जिसे न्यायालय के सदस्य आफिसरों में से कोई आफिसर, अभियुक्त या जज अटर्नी नहीं समझता है तो उसका उस भाषा में अनुवाद किया जाएगा जिसे वह समझता है।

115. सुरक्षक न्यायालय के संयवहार की कार्यवाहियों का अभिलेख—(1) न्यायालय में जज अटर्नी या, यदि कोई जज अटर्नी नहीं है तो, पीठासीन आफिसर, उस न्यायालय के सभी संयवहार अभिलिखित करेगा या कराएगा, और अभिलेख की (जिसे इन नियमों में कार्यवाहियां कहा गया है) सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा, और यदि जज अटर्नी को अभियुक्त ने साक्षी के रूप में बुलाया है तो पीठासीन आफिसर जज अटर्नी के साक्ष्य की कार्यवाहियों के अभिलेख की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) साक्ष्य जहां तक सम्भव हो प्रयुक्त शब्दों में वृत्त के रूप में लिखा जाएगा किन्तु किसी ऐसे मामले में जहां अभियोजक, अभियुक्त जज अटर्नी या न्यायालय इसे तात्त्विक समझता है, वहां प्रश्न और उत्तर शब्दशः लिखे जाएंगे।

(3) जहां किसी प्रश्न पर या किसी साक्ष्य को ग्रहण किए जाने पर या न्यायालय की प्रक्रिया पर आक्षेप किया जाता है, वहां ऐसा आक्षेप, यदि अभियोजक या अभियुक्त ऐसा आवेदन करता है या न्यायालय उचित समझता है तो, आक्षेप के आधारों और उन पर न्यायालय के विनिश्चयों के साथ, कार्यवाहियों में प्रविष्ट किया जाएगा।

(4) जहां अभियोजक या अभियुक्त द्वारा या उसकी ओर से किया गया कोई सम्बोधन लिखित रूप में नहीं है, वहां उसे आगे, या न्यायालय जैसा उचित समझता है उससे अन्यथा, कार्यवाहियों में अभिलिखित करना आवश्यक नहीं होगा, किन्तु—

(क) न्यायालय प्रत्येक मामले में अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिरक्षा का ऐसा अभिलेख अभिलिखित करेगा जो पुष्टि करने वाले आफिसर को अभियुक्त द्वारा, या उसकी ओर से, उसके विरुद्ध प्रत्येक आरोप की वाबत दिए गए उत्तर का निर्णय करने में समर्थ बना सके; और

(ख) न्यायालय अभियोजक या अभियुक्त द्वारा या उसकी ओर से किए गए सम्बोधन में से किन्हीं ऐसे विशिष्ट विषयों को अभिलिखित करेगा, जिनकी, यथास्थिति, अभियोजक या अभियुक्त अपेक्षा करे।

(5) न्यायालय कार्यवाहियों में कोई टीका-टिप्पणी या ऐसी कोई बात जो न्यायालय के समझ नहीं है या किसी ऐसे तथ्य की कोई रिपोर्ट जो विचारण का भाग नहीं है, कार्यवाहियों में दर्ज नहीं करेगा, किन्तु यदि कोई ऐसी टीका-टिप्पणी या रिपोर्ट न्यायालय को आवश्यक प्रतीत होती है तो न्यायालय इसे पीठासीन आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित पृथक दस्तावेज के रूप में समुचित प्राधिकारी को भेज सकेगा।

116. कार्यवाहियों की अभिरक्षा और निरीक्षण—कार्यवाहियाँ जज घटनों की (यदि कोई हो), या यदि कोई जज घटनों नहीं है तो, पीठासीन आफिसर की अभिरक्षा में समझी जाएगी, किन्तु उनकी सुरक्षा की बाबत उचित सावधानी बरतते हुए, न्यायालय के सर्वस्य, अभियोजक या अभियुक्त, निष्कर्ष पर विचार-विमर्श करने के लिए न्यायालय के बंद होने से पूर्व किसी भी उचित समय पर उसका निरीक्षण कर सकेंगे।

117. जनरल/पैटी सुरक्षक जज घटनों न्यायालय की कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन—यह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा में जनरल और पैटी सुरक्षक न्यायालय की कार्यवाहियाँ हैं, उन्हें पुनर्विलोकन के लिए जज घटनों जमन को भेजेगा जो उन्हें पुष्टि करने वाले प्राधिकारी को भेजेगा।

118. प्रतिरक्षा, आफिसर, अभियुक्त का मित्र और काउन्सेल—

(1) किसी जनरल या पैटी सुरक्षक न्यायालय में अभियुक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किसी काउन्सेल द्वारा या अधिनियम के अधीन के किसी आफिसर द्वारा, जो “प्रतिरक्षा आफिसर” कहलाएगा किया जा सकेगा या उसकी सहायता किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी जिस की सेवाएँ उपाप्त करने में वह समर्थ हो सके और वह “अभियुक्त का मित्र” कहलाएगा।

(2) प्रतिरक्षा आफिसर के वही अधिकार और कर्तव्य होंगे जो इन नियमों के अधीन काउन्सेल के हैं और वह समान बाधयताओं के अधीन होगा।

(3) अभियुक्त का मित्र सभी प्रश्नों पर अभियुक्त को सलाह दे सकेगा और साक्षियों से किए जान वाले प्रश्न मुझा सकेगा किन्तु वह साक्षियों की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा नहीं करेगा या न्यायालय को सम्बोधित नहीं करेगा।

119. काउन्सेल की हाजिरी के लिए अपेक्षाएँ—(1) काउन्सेल द्वारा प्रतिनिधित्व कराने का आग्रह रखने वाला अभियुक्त अपने कमांडर या संयोजक आफिसर को ऐसे आग्रह की यथासाध्य शीघ्र सूचना देगा और यदि पर्याप्त सूचना नहीं दी गई है और न्यायालय यदि उचित समझता है तो अभियोजक के आवेदन पर, विचारण में अभियोजक की ओर से काउन्सेल अभिप्राय करने में उसे समर्थ बनाने के लिए स्थगित हो सकेगा।

(2) जहाँ संयोजक आफिसर ऐसा निदेश देता है वहाँ काउन्सेल अभियोजक के साथ हाजिर हो सकेगा, किन्तु ऐसी दशा में, जब तक उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना अभियुक्त द्वारा न दे दी गई हो काउन्सेल के हाजिर होने के निदेश की सूचना अभियुक्त को, विचारण से पूर्व ऐसे समय (जो किसी भी दशा में मान दिन से कम नहीं होगा) दी जाएगी, जिससे कि, न्यायालय की राय में, अभियुक्त विचारण में सहायता प्राप्त करने के लिए काउन्सेल अभिप्राय करने में समर्थ हो सके।

(3) अभियोजक या अभियुक्त की ओर से न्यायालय के समक्ष हाजिर होने वाले काउन्सेल को साक्षियों को बुलाने, उसकी मौखिक परीक्षा, प्रतिपरीक्षा या पुनः परीक्षा करने, कोई अभिवचन करने और कार्यवाहियों का निरीक्षण करने के वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उस अभियोजक या अभियुक्त को प्राप्त है, जिसके लिए वह हाजिर होगा है और उस व्यक्ति की ओर से जिसकी ओर से वह हाजिर होता है, विचारण के अनुक्रम में अन्यथा कार्य करने का अधिकार होगा और वह इन नियमों का पालन उभी प्रकार करेगा मानो वह स्वयं वह व्यक्ति हो और ऐसी दशा में स्वयं उस व्यक्ति को उपायुक्त कार्यों में से कोई कार्य करने का अधिकार नहीं होगा, किन्तु वह नियम 90 के उपनियम (2) और नियम 97 के उपनियम (4) द्वारा अनुज्ञात कथन या व्याख्यान द्वारा अनुज्ञा दिए जाने पर ऐसा कार्य कर सकता है।

(4) जब काउन्सेल अभियोजक की ओर से हाजिर होता है तब यदि अभियोजक को साक्षी के रूप में बुलाया जाता है तो अभियोजक की किसी अन्य साक्षी की भांति परीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकेगी।

120. जज घटनों की निरहता—ऐसा आफिसर जो न्यायालय में प्रासीन होने के लिए निरहृत है वह उस न्यायालय में जज घटनों के रूप में कार्य करने के लिए निरहृत होगा।

121. जज घटनों की मृत्यु, रुग्णता या अनुपस्थिति में प्रतिस्थापन—यदि जज घटनों की मृत्यु हो जाती है या रुग्णता से ग्रस्त किसी अन्य कारण से वह हाजिर रहने में समर्थ है तो न्यायालय स्थगित हो जाएगा और पीठासीन आफिसर परिस्थितियों की रिपोर्ट संयोजक आफिसर को भेजेगा और उस आफिसर द्वारा एक उपायुक्त व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकेगी और उसे शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञा कराया जाएगा और वह शेष विचारण के लिए या जब तक कि जज घटनों वापस नहीं आ जाता है, जज घटनों के रूप में कार्य करेगा।

122. जज घटनों की शक्तियाँ और कर्तव्य—जहाँ किसी जज घटनों को न्यायालय में कार्य करने के लिए नामित किया गया है, वहाँ वह—

(क) जब कभी न्यायालय, अभियोजक, या अभियुक्त द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, आरोप या विचारण से संबंधित विधि के प्रश्न पर अपनी राय देगा;

(ख) कार्यवाहियों में किसी अनियमितता या अन्य कमजोरी के बारे में न्यायालय को सूचित करेगा;

(ग) आरोप में या न्यायालय के गठन में किसी कमजोरी या त्रुटि के बारे में संयोजक आफिसर और न्यायालय को सूचित करेगा;

(घ) साक्ष्य का उपसंहार करेगा और न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष पर विचार-विमर्श करने से पूर्व विधि के किसी प्रश्न पर अपनी राय देगा।

2. जज घटनों का कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अभियुक्त की उस रूप में स्थिति के परिणामस्वरूप या उसकी अनभिज्ञता या साक्षियों की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा करने में उसकी अनुपस्थिति के कारण उसका कोई अहित नहीं होता है और इन प्रयोजन के लिए जज घटनों न्यायालय की अनुज्ञा से, साक्षी बुला सकेगा और उनसे ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जो उसे आवश्यक या बांछनीय प्रतीत होते हैं।

3. अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, जज घटनों पूर्ण रूप से निरहता का दृष्टिकोण रखेगा।

4. जहाँ जज घटनों द्वारा न्यायालय की उनके समक्ष किसी विषय पर कोई राय दी गई है, वहाँ वह, यदि जज घटनों या न्यायालय ऐसा चाहे तो, कार्यवाहियों में प्रविष्ट की जा सकेगी।

(5) जज घटनों सुरक्षक न्यायालय में मुख्य जज घटनों जनरल का प्रतिनिधित्व करेगा।

123. पाणवपन का निष्कर्ष—जहाँ न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्त चित्त-विकृति के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है या उसके अभिकथित कार्य तो किया है किन्तु चित्त-विकृति के कारण वह कार्य की प्रकृति को या वह समझने में असमर्थ या कि वह कार्य दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल था, वहाँ पीठासीन आफिसर या संक्षिप्त सुरक्षक न्यायालय को दशा में, विचारण करने वाला आफिसर निष्कर्ष पर अपनी हस्ताक्षर करेगा और शारीरिक डोनेगा

और उस पर जज अदालतों की (यदि कोई है) हस्ताक्षर करेगा और तब कार्यवाही तुरन्त पुष्टिकर्ता प्राधिकारी को या, संश्लेष मुरक्षक न्यायालय की दशा में, उस पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए मजबूत उप महानिरीक्षक को, भेजी जाएगी।

124. कार्यवाहियों का परिरक्षण—प्रत्येक न्यायालय की कार्यवाहियों, प्रख्यापन के पश्चात् जज अदालतों जनरल के कार्यालय की भेजी जाएगी और वे वहाँ सात वर्ष से अन्यून तक या तब तक जब तक कि न्यायालय द्वारा अधिनियमित ढँड का अवधान नहीं हो जाता है, इनमें से जो पश्चात्कर्ता हों, परिरक्षित रखी जाएगी।

125. विचारण किए गए व्यक्ति का कार्यवाहियों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार—मुरक्षक न्यायालय द्वारा विचारण किया गया प्रत्येक व्यक्ति निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि, जहाँ ऐसी पुष्टि अपेक्षित हो, किए जाने के पश्चात् और कार्यवाहियों के तष्ट किए जाने से पूर्व किसी समय उसकी एक प्रति, जिसके अन्तर्गत, यदि कोई पुनरीक्षण हुआ है तो, पुनरीक्षण की कार्यवाहियां भी हैं, मांग करने पर जज अदालतों जनरल से प्राप्त करने का हक्कार होगा।

126. कुछ दशाओं में कार्यवाहियों की प्रति न दिया जाना—नियम, 125 में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार का, उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे यह धनाधान हो जाता है कि उक्त नियम के अधीन, कार्यवाहियों या उनके किसी भाग की प्रति देना राज्य की सुरक्षा के हितों या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के विरुद्ध होगा तो उसे ऐसी प्रति नहीं दी जाएगी:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि प्रति की मांग करने वाला व्यक्ति निष्कर्ष या दण्डादेश के सम्बन्ध में अधिनियम के अनुसार अर्जी प्रस्तुत करने या किसी न्यायालय में कोई कार्यवाई संस्थित करने का हक्कार है तो वह ऐसे व्यक्ति या उसके विधि सलाहकार को, यदि कोई हो निम्नलिखित शर्तों पर, कार्यवाहियों का निरीक्षण करने की अनुज्ञा देगा, अर्थात्:—

(क) निरीक्षण ऐसे सनकों और ऐसे स्थानों पर किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी निदिष्ट करे; और

(ख) कार्यवाहियों का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात व्यक्ति ऐसा निरीक्षण करने के पूर्व:—

(1) लिखित रूप में यह वचनबंध पेश करेगा कि वह कार्यवाहियों या उनके किसी भाग की प्रतियां नहीं बनाएगा और ऐसी कार्यवाहियों में सम्मिलित जान-कारी या दस्तावेजों का, उक्त निष्कर्ष या दण्डादेश के संबंध में अधिनियम के अनुसार अर्जी प्रस्तुत करने या न्यायालय में कार्यवाई संस्थित करने के प्रयोजन में निम्न किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं करेगा; और

(2) एक प्रमाणपत्र पेश करेगा कि वह इन बातों से अवगत है कि यदि वह उक्त कार्यवाहियों में सम्मिलित किन्हीं दस्तावेजों या जानकारी के सम्बन्ध में भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा 3 और धारा 5 में विनिर्दिष्ट कोई कार्य करता है तो वह उक्त धाराओं के अधीन अभियोजन के लिए अपने भागी बनाएगा।

127. कार्यवाहियों के अभिलेख का खो जाना—(1) यदि, पुष्टि के पूर्व, न्यायालय की उस मूल कार्यवाही का जिसकी पुष्टि अपेक्षित है, अभिलेख या उनका कोई भाग खो जाता है तो न्यायालय के पीठासीन आफिसर या वहाँ के जज अदालतों द्वारा प्रमाणित उसकी प्रति, यदि कोई है, मूल प्रति के स्थान पर स्वीकार की जा सकेगी।

(2) यदि कोई ऐसी प्रति नहीं है और आरोप, निष्कर्ष दण्डादेश और न्यायालय के संयवहारों की वास्तव पर्याप्त साध्य उपाप्त किया जा सकता है, तो वह साध्य, अभियुक्त की सहमति से, मूल कार्यवाहियों के अभिलेख या उस भाग के स्थान पर जो खो गया है, ग्रहण किया जा सकेगा।

(3) इस नियम के उपनियम (1) और (2) में वर्णित किसी भी दशा में, निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि की जा सकेगी, और वह वैसे ही विधिमान्य होगा, मानो मूल कार्यवाहियों का अभिलेख या उनका भाग, खोया ही नहीं था।

(4) यदि अभियुक्त उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट सहमति से हंकार करता है, तो उसका पुनः विचारण किया जा सकेगा, और पूर्व न्यायालय का निष्कर्ष और दण्डादेश, जिसकी कार्यवाहियां खो गई हैं, शून्य होगा।

(5) यदि पुष्टि के पश्चात् या किसी ऐसे मामले में जहाँ पुष्टि अपेक्षित नहीं है, न्यायालय की मूल कार्यवाहियों का अभिलेख या उसका कोई भाग खो जाता है, और आरोप, निष्कर्ष, दण्डादेश और न्यायालय के संयवहार और निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि का (यदि अपेक्षित हो) पर्याप्त साध्य विद्यमान है, तो वह साध्य सभी प्रयोजनों के लिए विचारण का विधिमान्य और पर्याप्त अभिलेख होगा।

128. साक्षियों और प्रत्यक्ष वक्ताओं द्वारा प्रमाण—जब किसी न्यायालय की राय है कि धारा 37 और 38 में विनिर्दिष्ट और उसके समक्ष किए गए या कार्यवाहियों के दौरान उसके ध्यान में लाए गए किसी अपराध की, जो यदि अधिनियम के अधीन के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता तो ऐसा अपराध गठित करना, जांच करने के लिए आधार है, तो ऐसा न्यायालय निम्नलिखित कार्यवाई कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) यदि वह व्यक्ति, जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि उसने अपराध किया है वह अधिनियम के अधीन है तो न्यायालय उसके आचारण की सूचना उसके कानून को दे सकेगा;

(ख) यदि वह व्यक्ति, जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि उसने वह कार्य किया है जो किसी सशस्त्र बल विधि के अधीन है, तो न्यायालय उसके आचारण की सूचना यथास्थिति समुचित सशस्त्र बल प्राधिकारी को दे सकेगा;

(ग) अन्य मामलों में, यथास्थिति वह आफिसर जिसने साक्षी की हजरि होने के लिए समन किया है, या पीठासीन आफिसर या न्यायालय अधिविष्ट करने वाला आफिसर अधिकांश रखने वाले निकटतम प्रथम वर्ग भजिस्ट्रेट को लिखित निहायत भेजेगा और उन कार्यों के मामले में, जो यदि अधिनियम के अधधीन के व्यक्ति द्वारा किए गए होते तो धारा 36 के खंड (ड) या धारा 37 के अधीन अपराध होते, न्यायालय ऐसी प्रारंभिक जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, मामले को, अधिकांश रखने वाले निकटतम प्रथम वर्ग भजिस्ट्रेट को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 340 के अनुसार जांच या विचारण के लिए भेज सकेगा।

अध्याय II

प्रतिज्ञान का प्रारूप

समरी सुरक्षक न्यायालय

129 कार्यवाहियां—(1) विचारण करने वाला अधिकारी, (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् न्यायालय कहा गया है) प्रत्येक समरी सुरक्षक न्यायालय के संव्यवहार अभिलिखित करेगा या कराएगा।

(2) न्यायालय, न्यायालय की कार्यवाहियों को अभिलिखित करने के लिए आशुनिपिक की नियुक्ति कर सकेगा। ऐसे आशुनिपिक को नियम 65 में दिए गए प्रावधान में सम्यक् रूप से शपथ बिलाई जाएगी या प्रतिज्ञा कराई जाएगी।

130. साक्ष्य का कब अनुवाद किया जाएगा—(1) जब कोई साक्ष्य ऐसी भाषा में दिया जाता है जिसे न्यायालय या अभियुक्त नहीं समझता है, तो उस साक्ष्य का अनुवाद, यथास्थिति, न्यायालय या अभियुक्त के लिए ऐसी भाषा में किया जाएगा जिसे वह न्यायालय या अभियुक्त समझता है।

(2) न्यायालय इस प्रयोजन के लिए या तो एक दुभाषिया नियुक्त करेगा या स्वयं समरी सुरक्षक न्यायालय में दुभाषिए के लिए विहित शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।

(3) जब अभिलेख औपचारिक सत्र के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं तब उसके उतने भाग का, जितना आवश्यक प्रतीत हो, अनुवाद कराना न्यायालय के विवेक पर होगा।

131. समवेत होना—न्यायालय जब, दुभाषिया (यदि कोई है) और विचारण में हाजिर होने वाले अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी समवेत हो जाते हैं तब अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष लाया जायेगा और उसमें उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा नियम 132 में विहित शपथ ली जायेगी या प्रतिज्ञान किया जायेगा।

132. न्यायालय और दुभाषिए द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान—

(1) न्यायालय निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में या समान आशय के ऐसे अन्य प्रारूप में, जो न्यायालय का गठन करने वाले अधिकारी के धर्म के अनुसार या अन्यथा उसके अन्तःकरण पर आवश्यक हो, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।

शपथ का प्रारूप

“मैं-----सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के बिना राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 के अनुसार सम्यक् रूप से न्याय करूँगा।”

प्रतिज्ञान का प्रारूप

“मैं-----मृत्युनिष्ठा सद्भाव और सच्चाई से घोषणा करता हूँ और प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के बिना राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 के उपबन्धों के अनुसार सम्यक् रूप से न्याय करूँगा।”

(2) न्यायालय या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अन्य व्यक्ति दुभाषिए को (यदि कोई हो) निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में या समान आशय के ऐसे अन्य प्रारूप में जैसा न्यायालय उस व्यक्ति के, जिसे दुभाषिए के रूप में कार्य करता है, धर्म के अनुसार या अन्यथा उसके अन्तःकरण पर आवश्यक अभिनिश्चित करे, शपथ दिलायेगा या प्रतिज्ञान करायेगा।

शपथ का प्रारूप

“मैं-----सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं इस न्यायालय के समक्ष उत्पन्न होने वाले विषय के संबंध में मुझसे अपेक्षा किये जाने पर निष्ठापूर्वक भाषान्तर और अनुवाद करूँगा।”

“मैं-----मृत्युनिष्ठा, सद्भाव और सच्चाई से घोषणा करता हूँ और प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं इस न्यायालय के समक्ष उत्पन्न होने वाले विषय के संबंध में मुझसे अपेक्षा किये जाने पर निष्ठापूर्वक भाषान्तर और अनुवाद करूँगा।”

(3) शपथ बिलाने जाने और प्रतिज्ञान कराये जाने के पश्चात्, साक्षी न्यायालय में बाहर चले जायेंगे।

133. अनेक अभियुक्तों के विचारण के लिये न्यायालय को शपथ दिलाता—(1) समरी सुरक्षक न्यायालय को, एक ही समय पर, उसके मामले उस समय उपस्थित कितने ही अभियुक्तों के विचारण के लिये शपथ बिलाई जा सकेगी या प्रतिज्ञान कराया जा सकेगा, चाहे उन अभियुक्तों का संयुक्त विचारण किया जाना हो या पृथक् विचारण किया जाना हो।

(2) पृथक्-पृथक् विचारण किये जाने वाले अनेक अभियुक्त व्यक्तियों की दशा में, न्यायालय शपथ बिलाने या प्रतिज्ञान कराये जाने पर अन्य मामलों को मुस्तवी करने हुए एक मामले में कार्यवाही करेगा और तत्पश्चात् क्रमानुसार अन्य मामलों को लेगा।

(3) जहाँ एक ही व्यवहार से उत्पन्न होने वाले आरोपों पर अनेक अभियुक्तों का पृथक्-पृथक् विचारण किया जाना है, वहाँ न्यायालय यदि वह समझता है कि यह न्याय के हित में वांछनीय है तो ऐसे अभियुक्तों में से किसी एक या अधिक को अधिनियमित किये जाने वाले किसी दण्डादेश पर विचार तब तक के लिये मुस्तवी कर सकेगा जब तक ऐसे सब अभियुक्तों के विचारण पूरे नहीं हो जाते हैं।

134. अभियुक्त को दोषारोपित किया जाना—(1) न्यायालय और दुभाषिए को (यदि कोई हो) ऊपर वर्णित शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के पश्चात् अभियुक्त को उसके विरुद्ध आरोपों में दोषारोपित किया जायेगा।

(2) वे आरोप जिनसे अभियुक्त को दोषारोपित किया जाता है, उसे पढ़कर सुनाये जायेंगे और यदि आवश्यक हो तो, उसे उनका अनुवाद करके सुनाया जायेगा और वे उसे स्पष्ट किये जायेंगे और उससे हर आरोप पर पृथक् रूप से अभिवचन करने की अपेक्षा की जायेगी।

135. आरोप के बारे में अभियुक्त द्वारा आक्षेप—अभियुक्त से जब किसी आरोप पर अभिवचन करने की अपेक्षा की जाये तब वह इस आधार पर आरोप के बारे में आक्षेप कर सकेगा कि उससे अधिनियम के अधीन कोई अपराध प्रकट नहीं होता है या वह इन नियमों के अनुसार नहीं है।

136. आरोप का संशोधन—(1) विचारण के दौरान किसी समय यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि आरोपपत्र में अभियुक्त के नाम या वर्णन में कोई भूल है तो न्यायालय उस भूल को शुद्ध करने के लिये आरोपपत्र का संशोधन कर सकेगा।

(2) यदि किसी आरोप के विचारण में न्यायालय को साक्षियों की परीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व किसी समय यह प्रतीत होता है कि न्याय के हित में आरोप में कोई परिवर्धन, उसमें से कोई लोप, या उसमें कोई परिवर्तन अपेक्षित है, तो वह ऐसे आरोप का संशोधन कर सकेगा और अभियुक्त को सम्यक् सूचना देने के पश्चात् यदि संशोधित आरोप के लिये ऐसी मंजूरी अपेक्षित है तो अभियुक्त के विचारण के लिये पेटी सुरक्षक न्यायालय का संयोजन करने के लिये सशक्त अधिकारी की मंजूरी से, ऐसे संशोधित आरोप पर आगे विचारण के लिये प्रसर हो सकेगा।

137. विशेष अभिवचन—यदि अभियुक्त ने न्यायालय की साधारण अधिकारिता के बारे में विशेष अभिवचन या विचारण के वर्तन के बारे में अभिवचन किया है तो ऐसे अभिवचनों को निपटाने के लिये अध्याय 9 में अधिकृत प्रक्रिया का, जहाँ तक वह लागू होती है, अनुपालन किया जायेगा।

138. "दोषी होने" या "दोषी न होने" का साधारण अभिवचन—

(1) अभियुक्त व्यक्ति का "दोषी होने" या "दोषी न होने" का अभिवचन या यदि वह अभिवचन करने से इंकार करता है या किसी आरोप पर स्पष्ट रूप से अभिवचन नहीं करता है तो प्रत्येक आरोप की बाबत "दोषी न होने" का अभिवचन अभिलिखित किया जायेगा।

(2) यदि कोई अभियुक्त व्यक्ति "दोषी होने" या अभिवचन करता है तो वह अभिवचन न्यायालय के निष्कर्ष के रूप में अभिलिखित किया जायेगा, किन्तु इसे अभिलिखित किये जाने से पूर्व न्यायालय यह अभिलिखित करेगा कि अभियुक्त उस आरोप की प्रकृति समझता है जिसके बारे में उसने "दोषी होने" का अभिवचन किया है और उसे उस अभिवचन का साधारण प्रभाव और विशेषकर उस आरोप का अर्थ जिसके लिये उसने "दोषी होने" का अभिवचन किया है और प्रक्रिया का वह अन्तर जो "दोषी होने" के अभिवचन के कारण होगा, सूचित करेगा और यदि अभिलेख या साक्ष्य के सार से (यदि कोई है) या अन्यथा, यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को "दोषी न होने" का अभिवचन करना चाहिये या तो उसे अभिवचन को वापस लेने की सलाह देगा।

(3) जहाँ अभियुक्त अनुकूलतः लगाये गये दो या अधिक आरोपों में से प्रथम के लिये "दोषी होने" का अभिवचन करता है, वहाँ न्यायालय उपनियम (2) का अनुपालन किये जाने के पश्चात् और अनुकूल्य आरोप या आरोपों पर अभियुक्त को दोषारोपित किये जाने के पूर्व, अभियुक्त से उस आरोप के पश्चात् वाले, जिसका दोषी होने का अभियुक्त ने अभिवचन किया है, अनुकूल्य आरोप या आरोपों पर अभिवचन करने की अपेक्षा किये बिना उन्हें वापस ले सकेगा और न्यायालय की कार्यवाहियों में बैसा आशय अभिलिखित किया जायेगा।

139. "दोषी होने" के अभिवचन के पश्चात् प्रक्रिया—

(1) "दोषी होने" का अभिवचन अभिलिखित किये जाने पर, यदि उसी आरोप-पत्र में अन्य आरोप है, जिनका अभिवचन "दोषी न होने" का है, तो विचारण पहले उन अन्य आरोपों के संबंध में होगा, और उन आरोपों पर निष्कर्ष के पश्चात्, उन आरोपों पर होगा जिनकी बाबत "दोषी होने" का अभिवचन दर्ज किया गया है, किन्तु यदि अनुकूल्य आरोप है तो न्यायालय या तो सभी आरोपों के बारे में ऐसे कार्यवाही करेगा मानो अभियुक्त ने किसी आरोप की बाबत "दोषी होने" का अभिवचन नहीं किया है या उसका विचारण करने की बजाय उन अनुकूल्य आरोपों में से किसी एक पर, जिसकी बाबत उसने "दोषी होने" का अभिवचन किया है, "दोषी होने" का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा और अन्य सभी अनुकूल्य आरोपों की बाबत "दोषी न होने" का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा।

(2)(क) किसी आरोप की बाबत "दोषी होने" का अभिवचन अभिलिखित करने के पश्चात् (यदि किसी अन्य आरोप पर विचारण अभी जारी नहीं रखा जाता तो) न्यायालय अभिलेख या साक्ष्य के सार को पढ़ कर सुनायेगा और उसे कार्यवाहियों में संलग्न करेगा और यदि कोई ऐसा अभिलेख या सार नहीं है तो पर्याप्त साक्ष्य लेगा और अभिलिखित करेगा जिससे कि वह दण्डादेश प्रवर्धित करने में समर्थ हो सके और पुनरोद्योग आक्षेप को अपराध से संबंधित सभी परिस्थितियों को जानकारी हो सके;

(ख) साक्ष्य उसी रीति से लिया जायेगा जो इन नियमों में "दोषी न होने" के अभिवचन की दशा में निर्दिष्ट किया गया है।

(3) यथास्थिति, ऐसा साक्ष्य लिये जाने या अभिलेख या साक्ष्य का सार पढ़कर सुनाये जाने के पश्चात् अभियुक्त आरोप के बारे में और दण्ड कम करने के बारे में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और और अपने चरित्र के बारे में साक्षी बुला सकेगा।

(4)(क) यदि अभियुक्त के कथन से, या साक्ष्य के अभिलेख से या अन्यथा न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त "दोषी होने" के अपने अभिवचन का प्रभाव नहीं समझता है तो न्यायालय अभिलेख में परिचर्च करेगा और "दोषी न होने" का अभिवचन प्रविष्ट करेगा और तदनुसार आगे विचारण करेगा।

(ख) उपनियम (1) के अधीन वापस लिये गये किन्हीं अनुकूल्य आरोपों को आरोप-पत्र में पुनः स्थापित किया जायेगा और विचारण इस प्रकार किया जायेगा मानो वे कभी वापस नहीं लिये गये।

(5) यदि उसी आरोप-पत्र के कुछ आरोपों की बाबत "दोषी होने" का अभिवचन अभिलिखित किया जाता है और अन्य आरोपों की बाबत विचारण किया जाता है तो उपनियम (2) और उपनियम (3) के अधीन कार्यवाहियाँ उसी आरोप-पत्र के अन्य आरोपों की बाबत निष्कर्ष अभिलिखित किये जाने के पश्चात् की जायेंगी।

(6) जब अभियुक्त दण्ड को कम करने से संबंधित किसी बात का कथन करता है, जिसका न्यायालय की राय में साबित किया जाना अपेक्षित है, और यदि उसके साबित कर देने से दण्ड की मात्रा पर प्रभाव पड़ेगा, तो न्यायालय अभियुक्त को उसे साबित करने के लिये साक्षी बुलाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

140. "दोषी न होने" का अभिवचन वापस लिया जाना—यदि अभियुक्त विचारण के दौरान किसी भी समय उचित समझता है तो वह "दोषी न होने" के अपने अभिवचन का वापस ले सकेगा और "दोषी होने" का अभिवचन कर सकेगा और ऐसी दशा में न्यायालय तुरन्त, नियम 138 के उपनियम (2) के अनुपालन के अधीन रहते हुए, "दोषी होने" का अभिवचन और निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा और, जहाँ तक आवश्यक हो, नियम 139 में उल्लिखित रीति से कार्यवाही करेगा।

141. "दोषी न होने" के अभिवचन के पश्चात् प्रक्रिया—

(1) किसी आरोप की बाबत "दोषी न होने" का अभिवचन अभिलिखित किये जाने के पश्चात्, अभियोजन के लिये साक्ष्य लिया जायेगा।

(2) अभियोजन के लिये साक्ष्य को समाप्ति पर अभियुक्त से पूछा जायेगा कि क्या उसे अपनी प्रतिज्ञा में कुछ कहना है या वह, प्राप्त साक्ष्य सुनाये जाने तक के लिये ऐसा सम्भवतः आस्पृहित कर सकेगा।

(3) तब अभियुक्त अपने साक्षी, जिनके अन्तर्गत चरित्र के बारे में साक्षी भी हैं, बुला सकेगा।

142. प्रतिरक्षा के उत्तर में साक्षी—न्यायालय, यदि वह न्याय के हित में आवश्यक समझता है तो, प्रतिरक्षा के उत्तर में साक्षी बुला सकेगा।

143. साक्षियों का साक्ष्य—नियम 85, नियम 86 और नियम 87 के उपबन्ध, यथासाध्य, सन 1974 के न्यायालय में साक्षियों के साक्ष्य को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे साधारण या पैटो सुल्ता न्यायालय में साक्षियों के साक्ष्य को लागू होते हैं।

144. निष्कर्ष का अभिलेख और घोषणा—(1) न्यायालय, अभियोजन और प्रतिरक्षा की ओर से साक्ष्य सुनने के पश्चात्, अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(2) ऐसे प्रत्येक आरोप पर जिस पर अभियुक्त को दोषारोपित किया गया है निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा, और, इस नियमों में जैसा बर्णित है उसके सिवाय, “दोषी होने” या “दोषी न होने” के निष्कर्ष के रूप में ही अभिलिखित किया जायेगा।

(3) जब किसी आरोप की बाबत न्यायालय की राय है कि साबित किये गये तथ्यों से आरोपित अपराध या ऐसा कोई अपराध प्रकट नहीं होता है जिसका उसे लगाये गये आरोप पर अधिनियम के अधीन विधिक रूप से दोषी ठहराये जा सके, तो न्यायालय यह निष्कर्ष निकालेगा कि अभियुक्त उस आरोप का “दोषी नहीं” है।

(4) जब किसी आरोप की बाबत न्यायालय की राय है कि साक्ष्य में साबित किये जाने के लिये पाये गये तथ्य आरोप में विशिष्टियों के कथन में अभिकथित तथ्यों से तार्किक रूप से भिन्न हैं, किन्तु फिर भी आरोप में कथित अपराध साबित करने के लिये पर्याप्त हैं, और विभिन्नता इतनी तार्किक नहीं है जिससे अभियुक्त की प्रतिरक्षा पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो तो न्यायालय “दोषी न होने” के निष्कर्ष के स्थान पर विशेष निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा।

(5) विशेष निष्कर्ष में अभियुक्त को किसी आरोप का, उसमें विनिर्दिष्ट अपराधों या भिन्नताओं के कथन के अधीन रहते हुए, दोषी ठहराया जा सकेगा।

(6) न्यायालय अभियुक्त को अनुकूल्य रूप से लगाये गये दो या अधिक आरोपों में से एक से अधिक का दोषी नहीं ठहरायेगा, भले ही एक आरोप पर दोषसिद्धि से आवश्यक रूप से अनुकूल्य आरोप या आरोपों का “दोषी होने” का अर्थ निकलता हो।

145. दोषमुक्त किए जाने पर प्रक्रिया यदि आरोप-पत्र के आरोपों में से प्रत्येक की बाबत “दोषी न होने” का निष्कर्ष है तो न्यायालय कार्यवाही पर हस्ताक्षर करेगा और तारीख डालेगा। निष्कर्ष खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा और अभियुक्त को उन आरोपों की बाबत, यदि गिरफ्तार है तो, मुक्त कर दिया जाएगा।

146. “दोषी होने” के निष्कर्ष पर प्रक्रिया—(1) जहाँ किसी आरोप की बाबत “दोषी होने” का निष्कर्ष है वहाँ न्यायालय अभियुक्त के साधारण चरित्र, आयु, सेवा, रैंक और बीरता के मात्थताप्राप्त कार्यों या उसके विशिष्ट आचरण की ओर सुरक्षक न्यायालय या दण्ड न्यायालय द्वारा अभियुक्त की पूर्ण दोषसिद्धियों को, धारा 51 के अधीन प्राधिकार का प्रयोग करते वाले किसी आफिसर द्वारा अभियुक्त की बाबत अधिनिर्णीत किए गए किसी पूर्ण दण्ड को, उस अधिक को जिसमें वह किसी पूर्ण दण्ड के लिए गिरफ्तार या परिरुद्ध रहा है, और किसी अलंकरण या इनाम को, जो उसके कब्जे में है या जिसका वह हकदार है, अपनी स्वयं की जानकारी के आधार पर अभिलिखित करेगा या किसी अभिलेख से उसका साक्ष्य लेगा।

(2) जहाँ न्यायालय अपनी जानकारी के आधार पर इस नियम में बर्णित बातें अभिलिखित नहीं करता है वहाँ इन विषयों पर साक्ष्य उसी प्रकार के साक्ष्य के लिए नियम 97 में निर्दिष्ट रीति से लिया जा सकेगा।

147. दण्डादेश—न्यायालय उन सभी अपराधों की बाबत, जिनके लिए अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है, एक दण्डादेश अधिनिर्णीत करेगा।

148. कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करना—न्यायालय, दण्डादेश पर हस्ताक्षर करके तारीख डालेगा और ऐसे हस्ताक्षर से सम्पूर्ण कार्यवाही अधिप्रमाणित हो जाएगी।

149. भिन्न-भिन्न आरोप-पत्रों में आरोप—(1) जब समरी सुरक्षक न्यायालय द्वारा विचारण में आरोप भिन्न-भिन्न आरोप-पत्रों में दिए गए हैं, तब अभियुक्त का, विचारण निष्कर्ष निकालने के प्रक्रम को सम्मिलित करते हुए निष्कर्ष निकालने के प्रक्रम तक प्रत्येक आरोप-पत्र पर पृथक् रूप से, किया जाएगा।

(2) तत्पश्चात् न्यायालय, यथास्थिति, नियम 145 या नियम 146 का अनुपालन करेगा।

150. न्यायालय खाली करवाना—(1) विचारण करने वाला आफिसर साक्ष्य पर विचार करने और विचारण में हाजिर रहने वाले आफिसरों और सहायक कमांडर से परामर्श करने के लिए न्यायालय खाली करा सकेगा।

(2) उपनियम (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी कार्यवाहियाँ, जिनके अन्तर्गत किसी स्थान का दृश्य भी है, खुले न्यायालय में और अभियुक्त की उपस्थिति में की जाएगी।

151. स्थगत न्यायालय—

(क) अपनी कार्यवाहियों को समय-समय पर स्थगित कर सकेगा और ऐसे स्थान पर समयेत हो सकेगा जो सुविधाजनक हो, और

(ख) जब कभी आवश्यक हो घटनास्थल का निरीक्षण कर सकेगा

152. अभियुक्त का मिस—समरी सुरक्षक न्यायालय में विचारण के दौरान, अभियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे वह आवश्यक समझे, जिसके अन्तर्गत विधि व्यवसायी भी है, सहायता ले सकेगा :

परन्तु ऐसा व्यक्ति साक्षियों की परीक्षा या प्रतिरीक्षा नहीं करेगा या न्यायालय को सम्बोधित नहीं करेगा।

153. कार्यवाहियों से संलग्न किया जाने वाला ज्ञापन—जहाँ समरी सुरक्षक न्यायालय किसी ऐसे अपराध का विचारण करता है, जिसका विचारण धारा 71 की उपधारा (2) में उल्लिखित किसी प्राधिकारी को निर्देश किए बिना साधारणतया नहीं किया जाएगा, वहाँ कार्यवाहियों के साथ एक व्याख्यात्मक ज्ञापन संलग्न किया जाएगा।

154. प्रस्थापन—समरी सुरक्षक न्यायालय का दण्डादेश, सुनाए जाने के पश्चात्, शीघ्रतम अवसर पर सेवा की सामान्य रीति से प्रस्थापित किया जाएगा और, अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रस्थापन के पश्चात् अविलम्ब कार्यान्वित किया जाएगा।

155. कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन—समरी सुरक्षक न्यायालय की कार्यवाहियाँ, प्रस्थापन के पश्चात् तुरन्त जजमटनीं जमरल या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नाम निर्दिष्ट आफिसर की मार्फत उस उप महानिरीक्षक को भेजी जाएगी जिसके अधीन अभियुक्त सेवा कर रहा हो।

156. उप महानिरीक्षक द्वारा कार्रवाई—(1) जहाँ उस उप महानिरीक्षक का, जिसे नियम 155 के अधीन समरी सुरक्षक न्यायालय की कार्यवाहियाँ भेजी गई हैं, यह समाधान हो जाता है कि कार्यवाहियों में गम्भीर अनियमितता के कारण या अन्य अभियुक्त के साथ अन्याय हुआ है, वहाँ वह-

(क) न्यायालय की कार्यवाहियों को अपास्त कर सकेगा, या

(ख) दण्डादेश को कम या अधिनिर्णीत दण्ड को धारा 47 में दिए गए दण्ड के निम्नतर मापमान में लघुकृत कर सकेगा।

(2) जहाँ उपनियम (1) के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की गई है, वहाँ वह कार्यवाही पर प्रलुप्ताक्षर करेगा और उसे प्रख्यापन के लिए अभियुक्त की यूनिट को वापस कर देगा।

(3) कार्यवाही, प्रख्यापित किए जाने के पश्चात् जज अदनी जनरल को अभिरक्षा के लिए भेजी जाएगी।

अध्याय 12

दण्डादेश का निष्पादन

157. कारावास के दण्डादेश के बारे में निदेश—(1) पुष्टिकर्ता प्राधिकारी, या समरी सुरक्षक न्यायालय की दशा में, न्यायालय यह निदेश देगा कि कारावास का सुरक्षक दण्डादेश या तो सिविल कारावास में या सुरक्षक अभिरक्षा में परिकल्पित रह कर भुगतना जाएगा।

(2) ऐसे निदेश में किसी बरिष्ठ आफिसर द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

158. बारण्ट—(1) कारावास का दण्डादेश भुगतने के लिए सिविल कारावास को किसी व्यक्ति की सुपुर्ग की लिए या, यदि ऐसा अपेक्षित हो तो, ऐसे व्यक्ति को सुरक्षक अभिरक्षा में वापस लेने के लिए या ऐसे व्यक्ति को सिविल कारावास से छोड़े जाने का आदेश करने के लिए या किसी बरिष्ठ आफिसर द्वारा किए गए किसी परिवर्तन के लिए बारण्ट ऐसे प्ररूप में होगा जो परिशिष्ट 9 में निविष्ट प्रत्येक मामले में उपयुक्त हो।

(2) ऐसे बारण्ट पर अभियुक्त के कमांडर द्वारा या उप महानिरीक्षक, महानिरीक्षक या महानिदेशक की ओर से स्टाफ आफिसर द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

159. मृत्यु के दण्डादेश की दशा में बारण्ट—जहाँ किसी व्यक्ति को फांसी लगाकर मृत्यु का दण्डादेश दिया जाता है, वहाँ परिशिष्ट 10 में दिए गए प्ररूप में बारण्ट, केन्द्रीय सरकार द्वारा दण्डादेश की पुष्टि किए जाने के पश्चात् महानिदेशक द्वारा ऐसे कारागार के अधीक्षक को जहाँ ऐसे दण्डादेश के कार्यान्वयन की सुविधाएं विद्यमान हैं, भेजा जाएगा और अभियुक्त का कमांडर अभियुक्त को समुचित बारण्ट पर उसी कारागार के सुपुर्द करेगा।

160. दण्डादेश में परिवर्तन—जहाँ पहले ही सिविल कारागार को सुपुर्द, किसी व्यक्ति के दण्डादेश में कोई परिवर्तन किया जाता है, वहाँ ऐसे परिवर्तन की संसूचना परिशिष्ट (11) में दिए गए प्ररूप में कमांडर द्वारा या नियम 158 में उल्लिखित अन्य व्यक्ति द्वारा उस कारागार के अधीक्षक को दी जाएगी जिसे ऐसा व्यक्ति सुपुर्द किया गया है।

161. पदच्युति का दण्डादेश—(1) पदच्युति का दण्डादेश ऐसे दण्डादेश की प्रख्यापना की तारीख से या ऐसी किसी पश्चात्बर्ती तारीख से, जो प्रख्यापन के समय विनिविष्ट की जाए, प्रभावी होगा।

(2) सिविल कारागार में भुगले जाने वाले कारावास के साथ संयोजित पदच्युति का दण्डादेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक ऐसा व्यक्ति सिविल कारागार को सुपुर्द नहीं कर दिया जाता है।

अध्याय 13

याचिकाएं

162. न्यायालय के निष्कर्ष और दण्डादेश के विरुद्ध याचिकाएं—(1) कोई व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन है और जिसका न्यायालय द्वारा विचारण किया गया है, पुष्टि से पूर्व प्राधिकारी को एक याचिका देने के लिए और पुष्टि के पश्चात् धारा 113 में उल्लिखित किसी आफिसर को एक याचिका देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) समरी सुरक्षक न्यायालय की दशा में वह धारा 113 में उल्लिखित आफिसरों में से केवल किसी एक को याचिका देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

163. परिसीमा काल—(1) पुष्टि से पूर्व याचिका, विचारण की समाप्ति के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(2) पुष्टि के पश्चात् याचिका उस तारीख से तीन मास के भीतर प्रस्तुत की जाएगी जिसको दण्डादेश प्रख्यापित किया गया था :—

परन्तु कार्यवाहियों की प्रतिलिपि प्राप्त करने में ऐसे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय तीन मास की इस अवधि की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

164. याचिकाएं प्रस्तुत करने का ढंग—(1) (क) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अभी तक भी सुरक्षक का सदस्य है, याचिका उसके कमांडर के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी,

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो सुरक्षक का सदस्य नहीं रहा है याचिका उस यूनिट के कमांडर को प्रस्तुत की जा सकेगी जिसमें विचारण किया गया था।

(2) वह आफिसर, जिसे याचिका प्रस्तुत की जाती है या जिसे याचिका भेजी जाती है, उसे एक सप्ताह की अवधि के भीतर अपने से अपने बरिष्ठ आफिसर को भेजेगा :

परन्तु ऐसा आफिसर किसी याचिका को नहीं भेज सकता है यदि वह माने गए अनुतोष को देने के लिए सज्ज है और ऐसा करने का विनिश्चय करता है।

(3) याचिका प्राप्त करने वाला आफिसर याचिका को जज अदनी जनरल या उसके द्वारा अनुमोदित आफिसर को सप्ताह के लिए भेजा जा सकेगा।

अध्याय 14

जांच—न्यायालय

165. रचना—(1)—जांच-न्यायालय एक या अधिक सदस्यों से मिल कर बन सकेगा। यदि केवल एक ही सदस्य की नियुक्ति की जाती है तो वह आफिसर होगा। यदि एक से अधिक सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है तो उनमें से कम से कम एक आफिसर होगा। जब न्यायालय को विशिष्ट प्रकृति के ऐसे मामलों का अन्वेषण करना हो जिसमें उचित अनुवेषण के लिए विशिष्ट व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता हो तब ऐसे व्यक्ति को, जो अधिनियम के अधीन नहीं हैं, अतिरिक्त सदस्यों के रूप में नियुक्ति की जा सके।

(2) किसी आफिसर के आचरण के बारे में आदेश किए गए जांच न्यायालय के सदस्य सदस्यों का रैंक ऐसे आफिसर के रैंक से निम्न रैंक का नहीं होगा। यदि उसी या उच्चतर रैंक के सभी आफिसरों की नियुक्ति संभव नहीं है तो कम से कम ऐसे जांच न्यायालय का पीठासीन आफिसर ऐसे आफिसर के, जिसके आचरण के बारे में जांच की जा रही है, उच्चतर रैंक का होगा।

166. समवेत होना—जांच न्यायालय कमांडर के जो, ग्रुप कमांडर के रैंक से नीचे का न हो, आदेश से या उस से बरिष्ठ किसी आफिसर का प्राधिकारी के आदेश से समवेत हो सकेगा।

167. समवेत होने का आदेश—जांच न्यायालय को समवेत करने वाले आदेश में न्यायालय की, संरचना, उसके समवेत होने के समय और स्थान का उल्लेख किया जाएगा और उसमें उन विषयों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा जिनका अन्वेषण न्यायालय करेगा। इसमें न्यायालय की प्रशासनिक आवश्यकताओं के बारे में उपबन्ध किया जाएगा।

168. जांच न्यायालय की प्रक्रिया—(1) जांच-न्यायालय की कार्य-वाहियां जनता के लिए खुली नहीं होंगी। कार्यवाहियों में केवल वे ही व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे जिन्हें ऐसा करने के लिए न्यायालय द्वारा अनु-ज्ञात किया जाए।

(2) सभी साक्षियों का साक्ष्य शपथ या प्रतिज्ञान पर लिया जाएगा और उस को उन्हें सुनाने और स्पष्ट करने के पश्चात् उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे।

(3) साक्षियों द्वारा दिया गया साक्ष्य बृत्तों के रूप में अभिलिखित किया जाएगा, जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि किन्हीं प्रश्नों और उत्तरों को उसी रूप में अभिलिखित किया जाए।

(4) न्यायालय किन्हीं दस्तावेजों पर विचार कर सकता है भले ही वे औपचारिक रूप से साबित न किए गए हों।

(5) न्यायालय किसी भी रूप में साक्षियों से ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जिन्हें वह सच्चाई कहलवाने के लिए आवश्यक समझे और वह किसी साक्ष्य पर विचार कर सकेगा चाहे वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के अधीन ग्राह्य हो या न हो।

(6) किसी काउन्सेल या विधि व्यवसायी को जांच-न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(7) जांच-न्यायालय के समक्ष साक्षियों की हाजिरी उपाप्त करने के लिए धारा 86 के उपबन्ध लागू होंगे। साक्षियों को परिशिष्ट 15 में दिए गए नमूनों के अनुसार समन किया जाएगा।

(8) (i) जहाँ जांच की विषयवस्तु किसी विशिष्ट व्यक्ति का आचरण या चरित्र है वहाँ ऐसे व्यक्ति को जांच के साथ निरन्तर सह्युक्त रखा जाएगा और उसे कोई ऐसा कथन करने, या ऐसा साक्ष्य देने का जिसे वह करना चाहे या देना चाहे, किसी साक्षी की, जिसका साक्ष्य उसकी राय में, उसके चरित्र या ब्याप्ति पर प्रभाव डालता है, प्रति परीक्षा करने का पूर्ण अवसर दिया जाएगा।

(ii) अन्य मामलों में अधिनियम के अधीन के किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई राय देने से पूर्व न्यायालय उस व्यक्ति को वे सब बातें जानने का जो उसके विरुद्ध कही गई है, ऐसे साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने का जिन्होंने उसके विरुद्ध साक्ष्य दिया है और अपने प्रतिरक्षा में कथन करने और साक्षी बुलाने का अवसर प्रदान करेगा।

(9) न्यायालय के समक्ष पूछे गए किसी प्रश्न का साक्षी द्वारा दिया गया उत्तर, ऐसे न्यायालय के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने के किसी आरोप के सिवाय किसी, पश्चात्पूर्वी अवसर पर किसी आरोप से ऐसे साक्षी के विरुद्ध ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

(10) जहाँ किसी जांच की कार्यवाहियों को नियम 170 के अधीन आवेगों के लिए किसी उच्चतर प्राधिकारी को भेजा जाता है, वहाँ ऐसा प्राधिकारी, न्यायालय की राय से असहमत होने से पूर्व, ऐसा करने के कारण अभिलिखित करेगा, ऐसे मामलों में, उप नियम (8) के खण्ड (ii) के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया जा सकेगा।

(11) न्यायालय उतनी बार पुनः समवेत हो सकेगा जितनी बार वह आफिसर, जिसने न्यायालय को समवेत किया, अतिरिक्त साक्षियों की परीक्षा के लिए या किसी साक्षी की अतिरिक्त परीक्षा के लिए या और अधिक जानकारी अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए निदेश दे। ऐसे मामलों में, न्यायालय यदि वह आवश्यक समझे तो, उपनियम (8) के खण्ड (ii) के उपबन्धों का अनुपालन करने के पश्चात् नहीं राय अभिलिखित कर सकेगा।

169. जांच न्यायालय कब अधिविष्ट होगा—(1) जांच-न्यायालय किसी अनुशासनिक बात का या किसी अन्य महत्वपूर्ण बात का अन्वेषण करने के लिए अधिविष्ट किया जा सकेगा।

(2) धारा 60 के अधीन अधिविष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित जांच-न्यायालय के अतिरिक्त, जांच न्यायालय निम्नलिखित मामलों में अधिविष्ट किया जाएगा :—

(क) (i) अधिनियम के अधीन व्यक्तियों की या सुरक्षक साक्ष्यों के भीतर अन्य व्यक्तियों की अप्राकृतिक मृत्यु के सब मामलों की तत्काल एक रिपोर्ट संदेशवाहक के माध्यम से उग पुलिस यानि के प्रभारी को भेजी जाएगी जिसकी अधिकारिता में वह स्थान पड़ता है जिसमें ऐसी अप्राकृतिक मृत्यु हुई है:

(ii) उन मामलों में, जिनमें ऐसी रिपोर्ट किसी कारण से मुक्तिपुस्तक समय के भीतर परिचल नहीं की जा सकती है, उपस्थित कमांडर या यूनिट का ज्येष्ठतम आफिसर परिशिष्ट II में उपबर्णित प्रोफार्म में एक रिपोर्ट तैयार करेगा:

(ख) अधिनियम के अधीन के व्यक्तियों को हुई ऐसी सब शक्तियां, जिनसे पूर्ण या आंशिक निशक्ता होने की सम्भावना है। न्यायालय ऐसे मामलों में यह अवधारित करेगा कि ऐसी शक्तियां ऐसी सेवा से हुई मानी जा सकती है या नहीं:

(ग) लोक या सुरक्षक सम्पत्ति की सब वित्तीय अनियमितताएं, हानि, चोरी, या बुविनियोग, जहाँ ऐसी अनियमितताओं, हानि चोरी या बुविनियोग के बारे में बरिष्ठ आफिसर का आदेश प्राप्त करना आवश्यक है:

(घ) गोपनीय दस्तावेजों और गोपनीय या सुरक्षा के उपर वर्गीकरण की अन्य सामग्रियों को खो जाने के सब मामले। ऐसे जांच न्यायालय के लिए आदेश उस यूनिट कमांडर से बरिष्ठ किसी आफिसर या प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा जिसके प्रभाव में खो गया दस्तावेज या सामग्री थी:

(ङ) प्राप्तेत व्यक्तियों या सम्पत्ति के हुए सब नुकसान जिनकी बाबत सरकार या सुरक्षक के विरुद्ध दावा किए जाने की सम्भावना है।

170. जांच-न्यायालय की कार्यवाहियों पर कार्रवाई—जांच-न्यायालय की कार्यवाहियां पीठासीन आफिसर द्वारा उस आफिसर या प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएंगी जिसने न्यायालय का आदेश दिया था। ऐसा आफिसर या प्राधिकारी कार्यवाहियां प्राप्त होने पर यदि वह ऐसा करने के लिए मशवत है तो कार्यवाहियों पर अंतिम आदेश स्वयं पारित कर सकेगा या उन्हें बरिष्ठ प्राधिकारी को निर्देशित कर सकेगा।

171. जांच न्यायालय की कार्यवाहियों की प्रतियां—अधिनियम के अधीन का वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध जांच-न्यायालय ने कोई राय दी है या जिसका जांच न्यायालय द्वारा अन्वेषण किए गए विषयों से संबंधित आरोप पर सुरक्षक न्यायालय द्वारा विचारण किया जा रहा है, जांच न्यायालय की कार्यवाहियों की प्रतियों का हकदार होगा, जब तक कि महानिदेशक अन्यथा आदेश न करे।

अध्याय 15

प्रकीर्ण

172. धारा 10(2) के अधीन विहित आफिसर—ऐसा आफिसर जो ग्रुप कमांडर के रैंक में लीचे का न हो, अपने कमान के अधीन किसी आफिसर या अधीनस्थ आफिसर से भिन्न किसी व्यक्ति को धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन सेवा में पदस्थ कर सकेगा या हटा सकेगा।

173. धारा 12(1) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी—धारा 12 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे :—

- (i) आफिसरों से भिन्न अधिनियम के अधीन के सभी कामियों की बाबत महानिरीक्षण;
- (ii) आफिसरों की बाबत केन्द्रीय सरकार।

174. धारा 60 की उपधारा (1) के अधीन शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने की निहित रीति न्यायालय साक्षियों की ऐसे शपथ दिलाएगा या प्रतिज्ञान करेगा मानो वह न्यायालय सुरक्षक न्यायालय हो।

175. धारा 96 या 97 के अधीन अभिरक्षा की निहित रीति और विहित आफिसर—(1) धारा 97 के प्रयोजन के लिए विहित आफिसर निम्नलिखित होंगे :—

(क) समरी सुरक्षक न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने की दशा में, उस यूनिट का कमांडर जिसके अधीन अभियुक्त है या ऐसे कमांडर से बरिष्ठ कोई आफिसर।

(ख) किसी अन्य न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने की दशा में संयोजक आफिसर या उससे बरिष्ठ कोई प्राधिकारी।

(2) जब कोई आफिसर जो उपनियम (1) के अधीन विहित आफिसर के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव करता है, किसी ऐसे आफिसर के कमान के अधीन है जिसने उस मामले में धारा 96 की उपधारा (4) के अधीन कार्रवाई की है, तो वह कार्रवाई करने से पूर्व सामान्यतः ऐसे आफिसर का अनुमोदन प्राप्त करेगा। किन्तु यदि उसकी यह राय है कि सेवा की आकस्मिकताओं या अनुशासनिक आवश्यकताओं के कारण ऐसा अनुमोदन प्राप्त करना असंभव या अशुभ है तो वह ऐसा अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही कार्रवाई कर सकेगा, किन्तु वह ऐसी कार्रवाई और इसके कारणों के बारे में ऐसे आफिसर को रिपोर्ट देगा।

(3) धारा 96 की उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, वह रीति जिसमें किसी अभियुक्त को अभिरक्षा में रखा जाएगा, निम्नलिखित होगी :—

अभियुक्त की ऐसी रीति से निरुद्ध रखा जाएगा जैसा ममुक्ति सुरक्षक प्राधिकारी की राय में, बिना अनावश्यक कठोरता के, उसे सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी समझी जाए क्योंकि उसे अपराधी नहीं माना

जाना चाहिए किन्तु उसे ऐसा व्यक्ति माना जाना चाहिए जो किसी रोग के कारण कष्ट में है।

176. प्राधिकृत कटौतियाँ—इस अधिनियम के अधीन के किसी व्यक्ति को संदेह बेधन और सभी अन्य परिस्थितियों में निम्नलिखित कटौतियाँ की जा सकेंगी :—

(क) केन्द्रीय सरकार के साधारण और विशेष आदेश पर, किसी लोक दावे को पूरा करने के लिए अपेक्षित धनराशि जो उस के नाम हो;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भविष्य निधि, कल्याण निधि या किसी अन्य निधि में अनिवार्य अभिदाय को पूरा करने के लिए या किसी मुश्किल जैसे रीम, कैदीन और दमों प्रचार की संस्था, संस्था के नाम उसमें देय किसी ऋण को पूरा करने के लिए अपेक्षित कोई राशि।

स्पष्टीकरण—“लोक दावे” से कोई ऐसा लोक ऋण या भत्ता निवेदन अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत लोक धन या स्टोर से अत्यधिक निरीसन या कर्मा या अनियमित व्यय, है, जिसके बारे में, सम्भव अन्वेषण के पश्चात् उस व्यक्ति द्वारा जो उसके लिए जिम्मेदार है, केन्द्रीय सरकार को समाधान-प्रद रूप में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

(ii) पूर्वोक्त कटौतियाँ, अधिनियम, में विनिर्दिष्ट कटौतियों के अतिरिक्त हैं।

177. निरसन और व्यावृत्ति—(1) इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों में संश्लिष्ट सब नियम और आदेश, जहाँ तक कि वे इन नियमों के उपबन्धों से असंगत हैं, निरसित हो जाएंगे।

(2) ऐसे निरसन के होने हुए भी, हम प्रकार निरसित नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन की गई कोई भी बात या कार्रवाई जहाँ तक कि ऐसी बात या कार्रवाई इन नियमों के उपबन्धों के असंगत नहीं है, इन नियमों के उपबन्धों के अधीन ऐसे की गई समझी जाएगी मानो उक्त उपबन्ध उस समय प्रवृत्त थे जब ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी और तदनुसार तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि वह इन नियमों के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई से अप्रतिष्ठित नहीं कर दी जाती।

178. अस्थायी उपबन्ध—इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को सुरक्षक को लागू कोई नियम या आदेश जब तक कि वह इन नियमों के विरुद्ध न हो, तब तक लागू बना रहेगा जब तक कि वह केन्द्रीय सरकार या और सशम प्राधिकारी द्वारा निरुद्ध या उपास्तित नहीं कर दिया जाता है।

परिशिष्ट 1
(नियम 34 देखिए)
विलम्ब रिपोर्ट का प्रारूप

गोपनीय

में
यूनिट का पता
तारीख

सेवा में

विषय. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 57 और नियम 34 के अनुसरण में, झोठ दिन विलम्ब की प्रथम, (द्वितीय), (तृतीय), (चतुर्थ) आदि रिपोर्ट।

1. सं. रैंक नाम
2. अपराध
3. अपराध की तारीख
4. अपराध का पता लगाने की तारीख
5. खुली/बंद गिरफ्तारी की तारीख
6. खुली गिरफ्तारी में छोड़े जाने/पुन. गिरफ्तारी पर
प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना/छोड़े जाने की तारीख
(यदि छोड़ा नहीं गया है तो कारण बताएं)
7. माध्यम अभिलिखित करने की तारीख (यदि अभिलिखित नहीं किया गया है तो कारण बताएं)
8. विचारण के लिए आवेदन करने की तारीख
9. वह तारीख जिसको विचारण किया जाना है
10. विलम्ब के कारण

(कमांडर)

निम्नलिखित को प्रतिलिपि—

1. महानिरीक्षक (आउटरी और पश्चातवर्ती रिपोर्टों की दशा में)
2. महानिदेशक (उम दशा में विशेष रिपोर्टें जब अधियुक्त विचारण के बिना तीन मास से अधिक के लिए बंद गिरफ्तारी में हैं)

परिशिष्ट 2

[नियम 25 (2) (ख)]

| क्रम सं. | तारीख | अधियुक्त का नाम | उम आफिसर या सहायक कमांडर का नाम जिसे आवेदन या अभ्यावेदन किया गया है | आवेदन या अभ्यावेदन कमांडर के आदेश की विशिष्टियां | अधियुक्त की कमांडर के आदेश टिप्पणियां संयुक्त करने वाले आफिसर या सहायक कमांडर के हस्ताक्षर और तारीख | | |
|----------|-------|-----------------|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

परिशिष्ट 3

(नियम 38)

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 51 के अधीन रेंजर्स और योद्धक व्यक्तियों की समरी कार्यवाहियों में प्रयोग के लिए प्रारूप

अपराध की रिपोर्ट

| सं. | अपराध का स्थान और तारीख | अपराध | अभियुक्त | साक्षियों के नाम | निष्कर्ष | अधिनिर्णित दंड | दंड अधि निर्णित करने वाले आफिसर के हस्ताक्षर, और पदनाम तथा अधिनिर्णय की तारीख | यूनिट के विरुद्ध आरोप | टिप्पणियां |
|-----|-------------------------|-------|----------|------------------|----------|----------------|---|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

यूनिट कमांडर के हस्ताक्षर

अनुदेश .

- स्तम्भ 1. छुट्टी के बिना अनुपस्थिति/अभियोजन की दशा में, "अपराध की तारीख" अनुपस्थिति का पहला दिन होगा।
 स्तम्भ 2. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा और उपधारा, जिसके अधीन आरोप लगाया गया है, आरोप के विवरण के ऊपर लिखी जाएगी।
 स्तम्भ 4. कोई आफिसर किसी ऐसे मामले में संक्षिप्त कार्यवाही नहीं कर सकता है जिसमें वह एकमात्र अभियोजन साक्षी है।
 स्तम्भ 6. सर्वथा शीर्षक के अनुसार भरा जाना चाहिए।

परिशिष्ट 5

(नियम 49)

सुरक्षा न्यायालय के लिए आवेदन का प्रारूप

यूनिट

स्टेशन तारीख

सुरक्षा न्यायालय के लिए आवेदन।

महोदय

मैं अपने कमान के अधीन यूनिट के सं. रैंक (नाम)

..... के विरुद्ध आरोप प्रस्तुत करता हूँ और आपसे इस बात की मंजूरी देने/इस बात के लिए की मंजूरी अभिप्राप्त करने का अनुरोध करता हूँ कि, उसके विचारण के लिए (स्थान) में सुरक्षा न्यायालय समवेत किया जाए।

मामले का अन्वेषण (क) द्वारा किया गया था।

न्यायालय जांच (ख) तारीख को (स्थान) में अधिविष्ट किया गया था।

पीठासीन आफिसर का रैंक नाम और यूनिट सदस्य

अभियुक्त इन समय (स्थान) में है। उसका साधारण चरित्र (ग) है। (मैं निम्नलिखित दस्तावेज (घ) इसके साथ भेज रहा हूँ।

1. आरोप पत्र (..... प्रतियाँ) (ङ)
2. अभिलेख का साक्ष्य का मार, मूल (च) और पांच प्रतियाँ
3. मूल प्रवर्ण (छ)
4. पत्राचार (ज)
5. अभियुक्त के चरित्र (.....) और आरोप-पत्र के बारे में विवरण (छ)
6. अभियोजन पक्ष और प्रतिरक्षा पक्ष के साक्षियों की सूची (उनके वर्णमान पते सहित) (छ)
7. अभियुक्त का यह कथन कि वह अपने विचारण में अपने प्रतिमित्रत्व के लिए संयोजक आफिसर द्वारा किसी आफिसर को समनुदेशित करवाना चाहता है या नहीं (नियम 62) (ज)

कमांडर के हस्ताक्षर

(क) यहाँ निम्नलिखित के नाम लिखें :—

(i) वह आफिसर जिसने आरोपों का अन्वेषण किया है।

(ii) वह आफिसर जिसने मामले में प्रारंभिक सुनवाई की है (नियम 39)

(iii) वह आफिसर जिसने माध्यम अभिलिखित किया है (नियम 45)

(ख) तब भरा जाए जब लोगों से संबंधित किसी विषय की आवश्यक कोई जांच-न्यायालय रहा है। अन्यथा इसे काट दिया जाए (नियम 57) (iii)।

(ग) कमांडर द्वारा भरा जाए।

(घ) जो सब लागू न होती हो वह काट दी जाए।

(ङ) पीठासीन आफिसर, जज अदालत (यदि कोई हो) सदस्य, अभियोजक और अभियुक्त को एक-एक प्रति।

(च) मूल अभिलेख या साक्ष्य का मार अभियोजक को भेजा जाए।

(छ) 3, 4, 5 और 6 विचारण की सूचना के साथ, अभियुक्त के यूनिट के कमांडर को वापस कर दी जाए।

(ज) 7 पीठासीन आफिसर को भेजी जाए।

परिशिष्ट 4

[नियम 50 (2)]

आरोप-पत्र

अभियुक्त, सं. _____ (यदि लागू होता है) रैंक _____ नाम _____ यूनिट _____
निम्नलिखित आरोप लगाया जाता है।

अपने बरिष्ठ आफिसर के विधिपूर्ण समावेश की अवज्ञा

राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम

धारा 21 (2)

उसने तारीख _____ को _____ वजे जब उसे उसी यूनिट के उसके बरिष्ठ आफिसर, रैंक _____ नाम _____ के कमांडर की परेड में आने का आदेश दिया तो उसमें न आकर उसके विधिपूर्ण समावेश की अवज्ञा की।

स्थान _____

तारीख _____

कमांडर, राष्ट्रीय सुरक्षक

*जनरल/पैटी सुरक्षक न्यायालय द्वारा विचारण किया जाए।

स्थान _____

तारीख _____

हस्ताक्षरित

महानिदेशक/उपमहानिदेशक

या महानिदेशक/उपमहानिदेशक

*जब समरी सुरक्षक न्यायालय द्वारा गंभीर अपराधों के विचारण के लिए मंजूरी दे दी जाए (राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम की धारा 71(2)) तब इसी प्रकार की प्रविष्टि आरोप-पत्र में की जानी चाहिए।

परिशिष्ट 6

(नियम 59)

सुरक्षक न्यायालय के संबंध में प्ररूप

जनरल और पैटी सुरक्षक न्यायालय के समवेत होने के लिए प्ररूप

राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम 1986 के अधीन जनरल (या पैटी) सुरक्षक न्यायालय के समवेत आवेश का प्ररूप।

_____ के आवेश।

(स्थान— _____ तारीख— _____)

सं. _____

रैंक _____

नाम _____

यूनिट _____

नीचे वर्णित आफिसर, पार्श्व में नामित अभियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) का (और ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का जो उनके समक्ष लाए जाएं) सुरक्षक न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने के प्रयोजन के लिए तारीख _____ को _____ पर समवेत होंगे।

उपेष्ट आफिसर पीठासीन आफिसर के रूप में बैठेगा।

सदस्य _____

प्रतीक्षारत सदस्य _____

जज अटर्नी

_____ को जज अटर्नी नियुक्त किया जाता है।

बुभाषिया

_____ को बुभाषिया नियुक्त किया जाता है।

अभियोजक

_____ को अभियोजक नियुक्त किया जाता है।

* अभियुक्त को चेतावनी दी जाएगी और सभी साक्षियों से हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी कार्यवाहियां (जिसकी केबल को प्रतियां अवेक्षित है)। _____ को अपेक्षित की जाएगी।

आज तारीख _____ को हस्ताक्षर किए गए।

संयोजक आफिसर

*न्यायालय की संरचना की बाबत संयोजक आफिसर की कोई राय (नियम 58 देखिए) यहां इस प्रकार जोड़ी जानी चाहिए :—

“संयोजक आफिसर की राय में विभिन्न/यूनिटों के आफिसरों को नियुक्त करना साध्य नहीं है।”

“संयोजक आफिसर की राय में, अभियुक्त के समान या बरिष्ठ रैंक वाले आफिसर, लोक सेवा का सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध नहीं हैं।

* यहां काउन्सेल की बाबत आदेश जोड़िए (नियम 59 (छ) देखिए)

परिशिष्ट-7

(नियम 102)

मैं, राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आदेश देता हूँ कि ----- का परिचय/संवाद ----- को कर दिया जाए (को अधिस्त/नष्ट किया जाए)

स्थान -----
 तारीख -----

हस्ताक्षर
 (पुष्टिकर्ता आफिसर)

परिशिष्ट-8

(नियम 102 (8) देखिए)

अभियुक्त ----- के विचारण के लिए तारीख ----- से तारीख ----- तक ----- (स्थान) में अधिविष्ट जनरल/पैटी सुरक्षक न्यायालय का निष्कर्ष और दण्डादेश मेरे द्वारा अभियुक्त को तारीख ----- को ----- (स्थान) में सुनाया गया था।

यूनिट के अभिलेखों के लिए उद्धरण के लिए है। * निष्कर्ष और दण्डादेश का कोई अभिलेख नहीं रखा गया है।

स्थान -----
 तारीख -----

हस्ताक्षर
 (कमांडर)

* सभी आरोपों पर दोषमुक्ति की दशा में प्रयोग किया जाए।

परिशिष्ट-9

(नियम 158)

राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 की धारा, 117 और 121 के अधीन बारण्ट

प्रारूप "क"

किस्ती कैदी को आजीवन कारावास का दण्डादेश दिए जाने पर प्रयोग में लाया जाने वाला सुपुर्वगी बारण्ट (धारा 117)

सेवा में,

अधीक्षक

----- (क) कारागार।

तारीख ----- को ----- (स्थान) में अधिविष्ट जनरल सुरक्षक न्यायालय ने (सं. -----) को ----- (यहां अपराध का संज्ञे में उल्लेख होजिए, जैसे "मरिफ सेवा में होते हुए अभित्यजन") के अपराध के लिए सिद्धोष उद्घारया था

और उक्त जनरल सुरक्षक न्यायालय ने तारीख ----- को उक्त (नाम -----) को निम्नलिखित दण्डादेश पारित कर दिया है, अर्थात्,

(दण्डादेश पूर्णतया लिखिए, किन्तु उस पर हस्ताक्षर न किए जाएं)

और उक्त दण्डादेश (ख) विधि अपेक्षित रूप में ----- (ग) द्वारा सम्यक् रूप से पुष्ट किया गया है।

इसलिए आपसे यह अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त (नाम) ----- को विधि द्वारा प्रेषित रूप में उक्त कारागार में अपनी अभिरक्षा में हम बारण्ट सहित लें और उसे वहां तक तक रखें जब तक आप उसे कारावास का पूर्वोक्त दण्डादेश भोगने के प्रयोजन के लिए समुचित प्राधिकारी को उसकी अभिरक्षा में उक्त बारण्ट सहित न सौंप दें। पूर्वोक्त दण्डादेश ----- (घ) से प्रभावी होगा।

आज ----- (स्थान) में तारीख ----- को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ताक्षर (ङ)

(क) सिविल कारागार का नाम लिखिए।

(ख) पुष्टिकर्ता प्राधिकारी का नाम और वर्णन।

(ग) यदि आवश्यक हो तो "----- का परिहार करते हुए" शब्द जोड़ें।

(घ) वह तारीख लिखिए जिसको मूल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ङ) कैदी के कमांडर या अन्य बिहित आफिसर के हस्ताक्षर।

परिशिष्ट—9

(नियम 158)

प्रश्न "ख"

सिविल कारागार में भुगतने जाने वाले कारावास से वण्डाविष्ट कैदी की दशा में प्रयोग के लिए सुपुर्दगी वारण्ट
(राष्ट्रीय सुरक्ष अधिनियम की धारा 117)

सेवा में,

अधीक्षक,

----- (क) कारागार

----- तारीख ----- को ----- (स्थान) में अधिविष्ट ----- (ख) सुरक्षक न्यायालय ने (सं. ----- रैंक -----
नाम ----- यूनिट -----) को -----) यहाँ अपराध का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, जैसे "अभित्यजन", "चीरो", "चुराई हुई
सम्पत्ति प्राप्त करना", "कपट", "विधिपूर्ण समावेश की अवज्ञा करना" आदि के अपराध के लिए सिद्धबोध अह्वानता या।

और उक्त ----- (ख) सुरक्षक न्यायालय ने तारीख ----- को उक्त (नाम -----) को निम्नलिखित वण्डादेश दिया है, अर्थात्

(वण्डादेश पूर्णतया लिखिए, किन्तु उस पर हस्ताक्षर न किए जाएं)

उक्त वण्डादेश (ग) विधि द्वारा अपेक्षित रूप में ----- (घ) द्वारा सम्यक रूप से पुष्ट किया गया है / (ङ) पुष्टि के बिना विधिमार्ग है।

इसलिए आपसे यह अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त (नाम) ----- को अपनी अभिरक्षा में इस
वारण्ट सहित लें और वहाँ कारावास के पूर्वोक्त वण्डादेश को विधि के अनुसार निष्पादित करें। वण्डादेश ----- (ख) से प्रभावी होगा।

आज ----- (स्थान) में तारीख ----- को मेरे हस्ताक्षरों से दिया गया।

हस्ताक्षर (ङ)

- (क) सिविल कारागार का नाम लिखिए
- (ख) जनरल, पेटी या समरी
- (ग) जो लागू न हो उन शब्दों को काट दीजिए
- (घ) पुष्टिकर्ता प्राधिकारी का नाम और वर्णन।
- (ङ) यदि आवश्यक हो तो "----- का परिहार करते हुए" शब्द जोड़ें।
- (ख) वह तारीख लिखिए जिसको मूल वण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- (ख) कैदी के कमांडर या अन्य विहित अधिकार के हस्ताक्षर।

परिशिष्ट 9

(नियम 158)

प्रश्न "ग"

वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भाजीवन कारावास के वण्डादेश को कम करके किसी कम अवधि के कारावास का वण्डादेश दिए जाने पर प्रयोग में लाया
जाने वाला वारण्ट (धारा 121)

सेवा में,

अधीक्षक,

(क) ----- कारागार।

तारीख ----- को ----- (स्थान) में अधिविष्ट (घ) ----- सुरक्षक न्यायालय द्वारा ----- यूनिट के (भूत
पूर्व) (संख्यांक ----- रैंक ----- नाम -----) को दिए गए ----- (ग) के वण्डादेश के अनुसरण
में ----- (ख) द्वारा जारी किए वारण्ट के अधीन उक्त व्यक्ति ----- (क) कारागार में परिरक्ष है और -----

(ङ) ने राष्ट्रीय सुरक्ष अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त वण्डादेश के संबंध में निम्नलिखित आदेश दिया है, अर्थात्:

(ख) -----
इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त ----- (नाम) को विधि द्वारा अपेक्षित रूप में
उक्त कारागार में अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट सहित लें और उसे वहाँ तक रखें जब तक आप उसे उक्त आदेश के अधीन कारावास का वण्ड भोगने के
प्रयोजन के लिए समुचित प्राधिकारी को उसकी अभिरक्षा में उक्त वारण्ट सहित न सौंपें। आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया
जाता है कि जिस मूल वारण्ट के बदले यह वारण्ट जारी किया गया है, उसे मूझे लौटा दें।

ऐसे कारावास की अवधि की गणना ----- (ङ) से की जाएगी।

आज तारीख ----- को ----- में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ताक्षर (ज)

- (क) सिविल कारागार का नाम लिखिए।
- (ख) उस आफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल बारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे।
- (ग) मूल दण्डादेश लिखें (यदि पुष्टिकर्ता आफिसर या अन्य बरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा घटा कर कम दिया गया था तो दण्डादेश इस प्रकार लिखा जाना चाहिए :—
- “आजोवन कारावास जिसे पुष्टिकर्ता आफिसर ने घटा कर 10 वर्ष कर दिया है।”
- (घ) जनरल
- (ङ) दण्डादेश में परिवर्तन करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम
- (च) पूरा आदेश लिखा जाए।
- (छ) वह तारीख लिखें जिसको मूल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- (ज) विहित आफिसर के हस्ताक्षर।

परिशिष्ट 9

(नियम 15)

प्रारूप “ब”

तब प्रयोग के लिए बारण्ट जब केरी को सुरक्षक की अभिरक्षा में सुपुर्द किया जाना है

सेवा में,

अधीक्षक,

(क) -----कारागार।

तारीख ----- को ----- (स्थान) में अधिविष्ट (घ) सुरक्षक न्यायालय द्वारा ----- यूनिट के (भूतपूर्व) (संख्यांक) ----- रैंक ----- नाम ----- को दिए गए ----- (ग) के दण्डादेश के अनुसरण में ----- (ख) द्वारा जारी किए गए बारण्ट के अधीन उक्त व्यक्ति ----- (क) कारागार में परिरक्ष्य है और ----- (ङ) ने राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त दण्डादेश के संबंध में निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :—

(च) -----

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप अपनी अभिरक्षा से उक्त ----- (नाम) को, यह बारण्ट लाने वाले आफिसर या सहायक कमांडर की सौंप दें।

आज तारीख ----- को ----- में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ताक्षर (छ)

- (क) सिविल कारागार का नाम लिखें।
- (ख) उस आफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल बारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे।
- (ग) मूल दण्डादेश लिखें (यदि वह पुष्टिकर्ता आफिसर या अन्य बरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा कम कर दिया गया था तो दण्डादेश इस प्रकार लिखा जाना चाहिए :—“2 वर्ष का कठिन कारावास जिसे पुष्टिकर्ता आफिसर ने घटाकर एक वर्ष कर दिया है।”
- (घ) जनरल, वेंटी या समरी।
- (ङ) आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम।
- (च) पूरा आदेश लिखा जाए।
- (छ) विहित आफिसर के हस्ताक्षर।

परिशिष्ट 10

(नियम 159 (1))

प्ररूप "क"

मृत्यु से दण्डादिष्ट व्यक्ति को सिविल कारागार की अभिरक्षा में सुपुर्द करने के लिए वारण्ट

सेवा में,

अधीक्षक,

(क) ----- कारागार।

तारीख ----- को ----- में अधिविष्ट (ख) ----- सुरक्षक न्यायालय ने ----- यूनिट के (सं. -----
 रैंक ----- नाम -----) को ----- (यहां अपराध का संक्षेपतः उल्लेख करें) के अपराध के लिए
 दण्डादिष्ट किया था:

और उक्त (ख) ----- सुरक्षक न्यायालय ने तारीख ----- को उक्त ----- (नाम) को फांसी लगाकर मृत्यु से
 दण्डादिष्ट किया था और मृत्यु के उक्त वण्डादेश की केन्द्रीय सरकार ने पुष्टि कर दी है।

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त ----- (नाम) को अपनी अभिरक्षा में लें और
 तारीख ----- को मृत्यु के वण्डादेश का निष्पादन करें।

आज तारीख ----- को ----- में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ताक्षर (ग)*

(क) सिविल कारागार का नाम लिखें।

(ख) जमरल।

(ग) महानिदेशक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 10

[नियम 159 (2)]

प्ररूप "ख"

मृत्यु से दण्डादिष्ट व्यक्ति को ऐसे वण्डादेश के निष्पादन के लिए सिविल अभिरक्षा से अभिप्राप्त करने के लिए वारण्ट

सेवा में,

अधीक्षक,

(क) ----- कारागार।

----- तारीख को ----- मृत्यु वंड भोगने के लिए दण्डादिष्ट किए जाने पर ----- यूनिट के (भूत-
 पूर्व) (सं. ----- रैंक ----- नाम -----) को (ग) ----- द्वारा
 जारी किए गए वारण्ट के अधीन उक्त कारागार में रखा गया है।

और उक्त वण्डादेश की (घ) ----- द्वारा, विधि द्वारा अपेक्षित रूप से सम्यक्तः पुष्टि किए जाने पर, उक्त वण्डादेश का निष्पादन
 करने के लिए मुझे (ङ) ----- (नाम और रैंक) आदेश जारी किया गया है।

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त ----- (नाम) को यह वारण्ट लाने वाले
 आफिसर/सहायक कमांडर/रिजर ध्येणी-I को तत्काल सीप दें।

आज तारीख ----- को ----- में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया

हस्ताक्षर (च)

(क) सिविल कारागार का नाम लिखें।

(ख) उस आफिसर का या पदनाम लिखें जिसने मूल वारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे।

(ग) पुष्टिकर्ता प्राधिकारी का नाम और वर्णन।

(घ) उस आफिसर का नाम और पदनाम लिखें जिसे आदेश जारी किया गया है।

(च) उस आफिसर के हस्ताक्षर जिसने आदेश जारी किया है।

परिशिष्ट 11

(नियम 160)

प्रारूप "क"

जब मृत्यु से दण्डादेश और सिविल कारागार की अभिरक्षा में सुपुर्व किसी व्यक्ति का दण्डादेश प्राजीवन कारावास के दण्डादेश में लघुकृत कर दिया जाता है तब प्रयोग में लाया जाने वाला वारंट

सेवा में,

अधीक्षक

(क) ----- कारागार।

तारीख ----- को ----- (स्थान) में अधिविष्ट (ग) ----- सुरक्षक
न्यायालय द्वारा ----- यूनिट के भूतपूर्व (सं. ----- रैंक ----- नाम -----)
को दिए गए मृत्यु के दण्डादेश के अनुसरण में ----- (ख) द्वारा जारी किए गए वारंट के अधीन उक्त व्यक्ति को -----
(क) कारागार में रखा गया है और ----- (घ) ने राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम द्वारा प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त दण्डा-
देश के बारे में निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :-- (ङ) -----

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त ----- (नाम) को विधि द्वारा अपेक्षित रूप में
उक्त कारागार में अपनी अभिरक्षा में इस वारंट सहित लें और उसे वहाँ तक रखें जब तक आप उसे उक्त आदेश के अधीन प्राजीवन कारावास का दण्ड
भोगने के प्रयोजन के लिए समुचित प्राधिकारी को उसकी अभिरक्षा में उक्त वारंट सहित न सौंप दें। आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधि-
कृत किया जाता है कि जिस मूल सुपुर्वगी वारंट के बदले यह वारंट जारी किया गया है, उसे मुझे लौटा दे। ऐसे प्राजीवन कारावास की अवधि की गणना
तारीख -----; (च) से की जाएगी।

आज तारीख ----- को ----- मैं मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ताक्षर (छ)

- (क) सिविल कारागार का नाम लिखें।
- (ख) उस आफिसर का नाम और पदनाम लिखें जिसने मूल वारंट पर हस्ताक्षर किए थे।
- (ग) जनरल
- (घ) दण्डादेश का लघुकरण करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम।
- (ङ) पूरा आदेश लिखा जाए।
- (च) वह तारीख लिखें जिसको मूल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- (छ) कमांडर के हस्ताक्षर।

परिशिष्ट II

(नियम 160)

प्रारूप "ख"

तब प्रयोग में लाया जाने वाला वारंट जब मृत्यु के दण्डादेश के अधीन और सिविल कारागार की अभिरक्षा में सुपुर्व किए गए व्यक्ति का
दण्डादेश, कारावास के ऐसे दण्डादेश में लघुकृत कर दिया जाता है जिसे उसी कारागार में भुगतना है

सेवा में

अधीक्षक,

(क) ----- कारागार।

तारीख ----- को ----- (स्थान) में अधिविष्ट (छ) ----- सुरक्षक न्यायालय
द्वारा ----- यूनिट के (भूतपूर्व) (संख्यांक ----- रैंक ----- नाम -----)
को दिए गए मृत्यु के दण्डादेश के अनुसरण में ----- (ख) द्वारा जारी किए गए वारंट के अधीन उक्त व्यक्ति को -----
----- (क) कारागार में रखा गया है और ----- (घ) ने, राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम द्वारा प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए पूर्वोक्त दण्डादेश के संबंध में निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :-- (ङ) -----

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है और आप को प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त (नाम) ----- को इस
वारंट सहित अपनी अभिरक्षा में रखें और उक्त आदेश के अधीन कारावास के बंड का निष्पादन विधि के अनुसार करें।

आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि सुपुर्वी के जिस मूल वारण्ट के बदले वह वारण्ट जारी किया गया है उसे मूल लौटा दें। ऐसे कारावास की अवधि की गणना (क) से की जाएगी।

आज तारीख को में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ताक्षर (छ)

(क) सिविल कारागार का नाम लिखें।

(ख) उस अधिकार का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल वारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे।

(ग) जनरल

(घ) वण्डादेश का लघुकरण करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम।

(ङ) पूरा आदेश लिखा जाए।

(च) वह तारीख लिखें जिसको मूल वण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(छ) कमांडर के हस्ताक्षर।

परिशिष्ट II

(नियम 160)

प्रारूप "ग"

जब मृत्यु से वण्डादेश किए जाने के पश्चात् सिविल कारागार की अभिरक्षा में सुपुर्वी किए गए किसी व्यक्ति को मृत्यु के वण्डादेश का निष्पादन करने से भिन्न प्रयोजन के लिए सुरक्षक की अभिरक्षा में रखा जाता है तब प्रयोग में लाया जाने वाला वारण्ट सेवा में,

अधीक्षक,

(क) कारागार।

तारीख को (स्थान) में अधिविष्ट (ग) सुरक्षक स्वायालय द्वारा यूनिट के (भूतपूर्व) (संख्यांक रैंक नाम) को दिए गए मृत्यु के वण्डादेश के अनुसरण से (ख) द्वारा जारी किए गए वारण्ट के अधीन उक्त व्यक्ति

(क) कारागार में रखा गया है और,

(घ) ने, राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त वण्डादेश के संबंध में निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात्—

(ङ)

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त (नाम) को इस वारण्ट को खाने वाले अधिकार/सहायक कमांडर या रैंजर श्रेणी-1 को तुरंत सौंप दें।

आज तारीख को में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ताक्षर (च)

(क) सिविल कारागार का नाम लिखें।

(ख) उस अधिकार का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल वारण्ट पर हस्ताक्षर किए थे।

(ग) जनरल।

(घ) आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम।

(ङ) पूरा आदेश लिखा जाए।

(च) कमांडर के हस्ताक्षर।

परिशिष्ट-11

(विप्रम 160)

प्रकाश "द"

जब कैदी को क्षमा कर दिया जाता है या उसका बिचारण अमान्य कर दिया जाता है या जब पूर्ण दण्डादेश या उसके अमान्यनमित भाग का परिहार कर दिया जाता है तब प्रयोग में लाया जाने वाला बारण्ड (धारा 121)।

जिस में,

अधीक्षक,

(क)..... कारागार।

तारीख.....को.....(स्थान)।

जो अधिविष्ट (घ)..... मुख्य न्यायालय द्वारा.....युनिट में (संख्यांक).....रैक.....नाम.....को दिए गए.....(ग) के दण्डादेश के अनुसरण में.....(ख) द्वारा जारी किए गए बारण्ड के अधीन उक्त व्यक्ति.....(क) कारागार में परिगढ़ है और.....(ङ) ने, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त दण्डादेश के बारे में निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात्—

(च).....

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त.....(नाम) को जब तक वह किसी अन्य कारण से निरुद्ध किए जाने के दायित्वाधीन न हों, अपनी अभिरक्षा में तत्काल छोड़ दें और इस प्रकार उसे छोड़ने के लिए वह आपके लिए पर्याप्त बारण्ड होगा।

आज तारीख.....19.....को.....में भेजे हस्ताक्षर से दिया गया।

हस्ताक्षर (छ)

(क) निम्न कारागार का नाम लिखें।

(ख) उस आफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल बारण्ड पर हस्ताक्षर किए थे।

(ग) मूल दण्डादेश लिखें यदि वह पुष्टिकर्ता आफिसर या अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा कम कर दिया गया था, तो दण्डादेश इस प्रकार लिखा जाना चाहिए—
“दो वर्ष का कठिन कारावास जिसे वरिष्ठ पुष्टिकर्ता आफिसर ने कम करके एक वर्ष कर दिया है।

(घ) जनरल, पेटी और (या) समरी।

(ङ) कैदी को क्षमादान करने वाले, दण्डादेश को कम करने वाले या बिचारण को अमान्य करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम।

(च) पूरा आदेश लिखा जाए।

(छ) विहित आफिसर के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 12

[नियम 169 (2) (क) (ii)]

वैद्यकृतिक मृत्यु के बारे में रिपोर्ट

1. मृत्यु का स्थान या बहुराज्य जहाँ शव मिला था (व्योम दीर्घ)।
2. मृत्यु की जानकारी प्राप्त होने की तारीख और समय।
3. शव की पहचान करने वाले दो या अधिक व्यक्तियों के नाम और वर्णन।
4. मृतक का नाम और उसकी विशेषताएँ और उसकी प्राम्थि।
5. मृतक द्वारा पहने हुए कपड़ों की तालत।

टिप्पण : यदि डाक्टर द्वारा परीक्षा की जाती है तो उक्त व्योम मृतक के कपड़े आदि हटाए बिना एकत्र किया जाना चाहिए और अन्य व्योम डाक्टर की परीक्षा के पश्चात् पूरा किया जाना चाहिए।

6. अंग, नेत्र और मूत्र की तालत।

7. मृत्यु की आकृति।

8. शव पर संघर्ष के चिह्नों, यदि कोई हैं, अस्थियों और खुरों की, उनका आकार और उनकी अवस्थिति बनाने हुए, अभिलिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : क्षति की गहराई अभिलिखित की जानी चाहिए किन्तु अस्थियों की छाना नहीं चाहिए। यदि डाक्टर द्वारा परीक्षा की जाती है तो उक्त जानकारी उसके द्वारा परीक्षा के पश्चात् अभिलिखित की जानी चाहिए।

9. स्थिति तालत या स्कन्दित है। यह किस स्थान से और कितनी मात्रा में निकला है।

10. किस साधन, शस्त्र या उपकरण से क्षति या संघर्ष के चिह्न कारित किए गए प्रतीत होते हैं।
11. क्या गर्दन के चारों ओर कोई रस्सी बंधी हुई थी या उसके चारों ओर किसी चीज के बांधे जाने का कोई चिह्न है।
12. क्या रस्सी या किसी अन्य चीज का प्रयोग गला घोटने या शव को लटकाने के लिए किया गया था, क्या वह बलन सम्भालने के लिए काफी मजबूत थी और क्या इसका दूसरा सिरा किसी चीज से बांधा हुआ था।
13. क्या बाँस आदि जैसे बाहरी पदार्थ बालों से लगे हुए थे या उसके हाथ में थे या उसके शरीर के किसी अन्य भाग में बिपके हुए थे।
14. क्या शव किसी लूट-पुट और नुपठित आदमी का है या वह किसी कमजोर या बूढ़ा आदमी का है।
15. क्या शव मजबूत है या वह कमजोर हो गया है या उसमें सडन पैदा हो गई है।
16. सिर से पैर तक शव की लम्बाई।
17. पहचान चिह्न और चारों की अवस्थिति और उनका आकार।
18. मृत्यु का दृश्यमान कारण।
19. क्या कोई ऐसी अफवाह या ऐसी अन्य परिस्थितियाँ हैं जिससे यह दृष्टित होता है कि यह आत्महत्या का मामला है।

शव पर या उसके समीप पड़ी हुई मिली वस्तुओं का व्योम।

20. शव पर मिली वस्तुएं (प्रत्येक वस्तु पर एक पंथी बिपकाई जानी जो स्थापित होगी)।

21. शब्द के समीप पड़ी हुई मिला वस्तु (प्रत्येक वस्तु पर गम्यक रूप से स्थापित नहीं बिपकाई जाएगी)।

सुद्धा का वर्णन

22. उस स्थान का नक्शा जहाँ शब्द मिला था। मामले का संक्षिप्त विवरण।

परिच्छेद के ऐसे दो या अधिक प्रतिष्ठित साक्षियों के हस्ताक्षर
जिनकी उपस्थिति ने अन्वेषण किया गया था।

स्थान

मामले का अन्वेषण करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख

नाम रैंक

परिच्छेद 13

(नियम 175)

भाग 1

प्रकरण 1

आफिसरों के सहायक कमांडरों के (अधिनियम की धारा 53 और 54 के प्रचीन) संक्षिप्त विचारण में प्रयोग के लिए प्रेषण

अभिमुख

रैंक और नाम

बुद्धि

जब मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी (अभिमुख की लिखित सहमति से) साक्षियों की हाजिरी से अभिवृत्ति देने का विनिश्चय करता है, तब अभिमुख से पूछे जाने वाले प्रश्न—

1. क्या आपको आरोप पत्र और अभिलेख या साक्ष्य के सार या साक्ष्य के संक्षेप की प्रति प्राप्त हो गई है ?

उत्तर :

2. क्या आपको अपनी प्रतिष्ठा का तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिला है ?

उत्तर .

3. आरोप पत्र पढ़ा जाता है। क्या आप अपने विरुद्ध लगाए गए उस आरोप/उन आरोपों के, जो आपने सुने/पढ़े हैं, दोषी है या दोषी नहीं हैं ?

उत्तर .

यदि अभिमुख किसी आरोप के लिए "दोषी नहीं" होने का अभिव्यक्त करना है तो यथास्थिति, साक्ष्य के अभिलेख या साक्ष्य के सार, या साक्ष्य के संक्षेप अभिमुख की सुनवाई के भीतर पढ़े जाएंगे और इस आशय की कार्यवाही अभिलिखित किया जाएगा।

4. क्या आप कोई कथन करना चाहते हैं ?

उत्तर .

यदि अभिमुख कोई कथन करना चाहता है तो उसे इस समय ऐसा करना चाहिए। यदि मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी सुनवाई की समाप्ति पर यह समझता है कि आरोप खारिज नहीं किया जाना चाहिए, तो उसे अभिमुख का मेधा अभिलेख या आचरण पत्र देखना चाहिए। यदि मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने

वाला प्राधिकारी खिगदण्ड, तीव्र खिगदण्ड या शास्त्रिक कटीनियों से भिन्न कोई दण्ड अधिनियमित करने की प्रस्तापना करना है तो यह अभियुक्त में निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे :

5. क्या आप यह चाहते हैं कि आपका विचारण सुरुभक्त त्वासात्म्य द्वारा किया जाए या आप मेरा अधिनियम स्वीकार करेंगे ?

उत्तर :

निष्कर्ष
अधिनियम
स्टेशन
तारीख

टिप्पण—प्रश्न 4 में उत्तर में अभियुक्त का मौखिक कथन अभिलिखित नहीं किया जाएगा। यदि अभियुक्त ने लिखित कथन प्रस्तुत किया है तो ऐसा कथन ही इस प्रश्न के साथ तब भेजा या संलग्न किया जाएगा जब साक्ष्य के अभिलेख या मार या साक्ष्य के संक्षेप की प्रति इस प्रकार भेजी या संलग्न की जाती अपेक्षित है। यह प्रश्न आफिसर सहायक कमांडर की सेवा अभिलेख के साथ रखा जाएगा।

परिशिष्ट 14

(नियम 175)

भाग 1

प्रश्न 2

आफिसर और सहायक कमांडरों के (अधिनियम की धारा 53 और 54 के अधीन) संक्षिप्त विचारण में प्रयोग के लिए प्रश्न।

अभियुक्त

रैंक और नाम

धुनि

जब मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी साक्षियों की हाजिरी से अभियुक्त देने का विनिश्चय नहीं करता है या जब अभियुक्त उनकी हाजिरी की अपेक्षा करता है, तब

अभियुक्त में पूछे जाने वाले प्रश्न—

1. क्या आपको आरोप पत्र और अभिलेख या साक्ष्य के या साक्ष्य के संक्षेप की प्रति प्राप्त हो गई है ?

उत्तर :

2. क्या आपको अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिला है ?

उत्तर :

3. क्या आप अपने बिरुद्ध लगाए गए उस आरोप/उन आरोपों के, जो आपने सुने/पढ़े हैं, दोषी हैं या दोषी नहीं हैं ?
माझी अपनी माध्य देने है, अभियुक्त को उनकी प्रति परीक्षा करने की अनुमति दी जाती है।

4. क्या आप कोई कथन करना चाहते हैं ?

उत्तर :

5. क्या आप किसी साक्षी को बुलाना चाहते हैं ?

उत्तर :

अभियुक्त कथन करता है और उसके साक्षी साक्ष्य देते हैं। यदि मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी सुनवाई की समाप्ति पर यह समझता है कि आरोप खारिज नहीं किया जाना चाहिए, तो उसे अभियुक्त का सेवा अभिलेख या आचरण पत्र देखना चाहिए। यदि मामले के संबंध में संक्षिप्त रूप में कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी, धिस्दण्ड, तीव्र धिस्दण्ड या शास्तिक कटौतियों से भिन्न कोई दण्ड अधि-निर्णीत करने की प्रस्थापना करता है तो वह अभियुक्त से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगा :—

6. क्या आप यह चाहते हैं कि आपका विचारण सुरक्षक न्यायालय द्वारा किया जाए या आप मेरा अधिनिर्णय स्वीकार करेंगे ?

उत्तर :

निष्कर्ष

अधिनिर्णय

स्थान

तारीख

टिप्पण : प्रश्न 4 के उत्तर में अभियुक्त का मौखिक कथन अभिलिखित नहीं किया जाएगा। यदि अभियुक्त ने लिखित कथन प्रस्तुत किया है तो ऐसा कथन ही इस प्रारूप के साथ तब भेजा या संलग्न किया जाएगा जब अभिलेख या साक्ष्य के सार या साक्ष्य या संक्षेप की प्रति इस प्रकार भेजी या संलग्न की जाती अपेक्षित है। यह प्रारूप आफिसर/सहायक कमांडर के सेवा अभिलेख के साथ रखा जाएगा।

परिशिष्ट 15

(नियम 45, 61 और 168)

साक्षियों को समन करने का प्रारूप

(क) साक्ष्य के अभिलेख की दशा में सुरक्षक न्यायालय द्वारा विचारणीय सं० रैंक
नाम यूनिट
के विशुद्ध अपराध का आरोप मेरे समय प्रस्तुत किया गया है और मैंने तारीख को
वजे स्थान पर लिखित साक्ष्य का अभिलेख लेने का निदेश दिया है।

मैं आपकी (नाम) समन करता हूँ और उक्त स्थान और समय पर साक्षी के रूप में उपस्थित होने की (और अपने साथ इसमें इसके पश्चात् वर्णित दस्तावेज अर्थात्—लाने की) अपेक्षा करता हूँ।

यदि ऐसा करने में आप असफल रहते हैं तो आप अपने जोखिम पर करेंगे।

आज तारीख 19 को में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

(हस्ताक्षर)

अभियुक्त का कमांडर

(ख) मुरक्षक न्यायालय की दशा में।

..... यूनिट क थी के निवारण के लिए तारीख को स्थान पर बजे मुरक्षक न्यायालय को सम्बत होने का आदेश दिया गया है। मैं आपको क ख को समझ करता हूँ और उक्त न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में तारीख को बजे स्थान पर उपस्थित हान की (और अपने साथ इसमें इसके पश्चात् भणित दस्तावेज अर्थात्— जाने की) और इस प्रकार दिन प्रतिदिन कार्रवाई में तब तक उपस्थित होने की जब तक आप सम्यक् रूप से उन्मुख नही कर दिए जाने, आदेश करता हूँ; यदि ऐसा करने में आप असफल रहते हैं तो आप अपनी जॉबिस पर करेंगे।

प्राप्त तारीख 19 को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

(हस्ताक्षर)

संयोजक आफिसर या

प्रदर्शी या न्यायालय का पीठासीन,

आफिसर या अभियुक्त का कमांडर

(ग) जॉब न्यायालय की दशा में।

तारीख का स्थान पर जॉब न्यायालय का उक्त परिस्थितियों की शिममें जॉब करने के लिए सम्बत होने का आदेश किया गया है मैं आपके क ख क उक्त जॉब न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में तारीख का बजे उपस्थित होने की (और इसमें इसके पश्चात् भणित दस्तावेज अर्थात् अपने साथ जाने की) तथा इस प्रकार दिन प्रतिदिन कार्रवाई में तब तक उपस्थित होने की जब तक आप सम्यक् रूप से उन्मुख नहीं कर दिए जाने, आदेश करता हूँ। यदि ऐसा करने में आप असफल रहते हैं तो आप अपनी जॉबिस पर करेंगे।

..... प्राप्त तारीख 19 को में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

(हस्ताक्षर)

पीठासीन आफिसर या

यूनिट का कमांडर

[सं० के 16011/3/86-एन एस जी]

बि० कु० जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(National Security Guard Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 1987

G.S.R. 688(E).—In exercise of the powers conferred by section 139 of the National Security Guard Act, 1986 (47 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

The National Security Guard Rules, 1987.

CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short title, commencement and application.—

(1) These rules may be called the National Security Guard Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall apply to all persons subject to the Act :

Provided that the provisions of Chapter IV thereof shall not apply to the persons on deputation with the National Security Guard :

Provided further that the provisions of Chapters IX and X thereof shall not apply to trials by Summary Security Guard Courts in so far as they are inconsistent with any of the provisions contained in Chapter XI thereof pertaining to Summary Security Guard Courts.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Security Guard Act, 1986 (47 of 1986).

(b) "Appendix" means an Appendix, annexed to these rules,

(c) "Court" means the Security Guard Court,

(d) "Detachment" includes any part of a Group or a unit of the Security Guard required or ordered to proceed on duty away from Headquarters.

(e) "proper Security Guard authority" when used in relation to any power, duty, act or matter, means such Security Guard authority as, in pursuance of these rules made under the Act, exercises, or performs that power or duty or is concerned with that matter.

(f) "section" means a section of the Act.

(g) All other words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

3. Reports and applications.—Any report or application required by these rules to be made to a superior authority or is otherwise made to a superior authority shall be made in writing and through proper channel.

4. Forms in appendices.—(1) The forms set forth in the appendices, with such variations as the circumstances of each case may require, may be used for the respective purpose therein mentioned, and if used shall be sufficient, but a deviation from such form shall not, by reason only of such deviation, render invalid any charge, warrant, order, proceedings or any other document relevant to these rules.

(2) Any omission of any such form shall not, by reason only of such omission, render any act or thing invalid.

(3) The directions in the notes to and the instructions in the form shall be duly complied with in all cases to which they relate, but any omission to comply with any such direction in the notes or instructions shall not, merely by reason of such omission, render any act or thing invalid.

5. Exercise of power vested in holder of an office in the Security Guard.—Any power or jurisdiction given to any person holding any office in the Security Guard to do any act or thing to, or before, any person, may, for the purposes of these rules, be exercised by any other person who may, for the time being, be performing the functions of that office in accordance with the rules and practice of the Security Guard.

6. Case unprovided for.—In regard to any matter not specifically provided for in these rules, it shall be lawful for the competent authority to do such thing or take such action as he may deem fit in the circumstances of the case.

CHAPTER II RECRUITMENT

7. Ineligibility.—(1) No person, who has more than one wife living or who having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reasons of its taking place during the life time of such spouse, shall be eligible for appointment, or employment in the Security Guard.

(2) Any person subject to the Act, who contracts or enters into a second marriage during the life time of his first spouse, shall render himself ineligible for retention in service and may be dismissed, removed or retired from service on ground of unsuitability :

Provided that the Central Government may, if satisfied, that there are sufficient grounds for so ordering exempt any person from the operation of this rule.

8. Ineligibility of aliens.—No person who is not a citizen of India shall, except with the consent of the Central Government signified in writing, be appointed, or employed in the Security Guard :

Provided that nothing contained in this rule shall bar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Security Guard.

9. Appointment of Officers.—The Central Government may appoint such persons as it considers to be suitable as officers in the Security Guard in the following manner and their conditions of service shall be such as may be provided in the rules made in this behalf by the Central Government :—

- (a) by direct recruitment ;
- (b) by deputation from the All India Services, Defence Forces, Armed Forces of the Union, any other Department of the Central Government or of the State Government or Autonomous bodies ;
- (c) by promotion as may be prescribed from time to time.

10. Probation.—(1) An officer appointed through direct recruitment to the Security Guard shall be on probation for a period of two years and the Central Government may, for reasons to be recorded in writing, extend the period of probation for such further period or periods not exceeding one year ;

(2) The Central Government may, during the period of probation, terminate the services of an officer without assigning any reasons.

11. Appointment of Assistant Commanders, Rangers and Combatised Tradesmen.—(1) Appointments to the posts of Assistant Commanders Grade I may be made by the Inspector-General, Assistant Commanders Grade II and III by the Deputy Inspector-General and the Rangers and Combatised Tradesmen by the Group Commander or any other officer of the Security Guard who may be appointed as recruiting officer by the Director-General, respectively in the following manner and their conditions of service shall be such as may be prescribed :—

- (a) by direct recruitment ;
- (b) by deputation from the Defence Forces or any of the Armed Forces of the Union, any other Department of the Central Government or of the State Government or Autonomous bodies ;
- (c) by promotion as may be prescribed from time to time.

(2) A person appointed through direct recruitment as Assistant Commander, Ranger or a Combatised Tradesman shall be on probation for a period of two years. The authority prescribed in sub-rule (1) may during the period of probation, terminate his services without assigning any reasons.

12. Procedure for appointment, mode of appointment of Rangers and Combatised Tradesmen.—Upon the appearance before the recruiting officer of any person for appointment as a ranger or combatised tradesman the Security Guard, the recruiting officer shall read and explain to him, or cause to be read and explained to him in his presence, the conditions of service of the post to which he is to be appointed ; and shall put to him the questions contained in the form of appointment as may be prescribed by the Director-General and shall, after having cautioned

him that if he makes a false answer to any such question he shall be liable to punishment under the Act, record or cause to be recorded his answer to each such question.

(2) If, after complying with the provisions of sub-rule (1) and such other directions as may be issued in this behalf by the Director-General from time to time, the recruiting officer is satisfied that the person desirous of being appointed, fully understands the questions put to him and consent to the conditions of service, and if the said officer is satisfied that there is no impediment, he shall sign and shall also cause such person to sign the appointment paper, and such person shall thereupon be deemed to be appointed.

(3) (a) Every person appointed as a member of the Security Guard under sub-rule (2) shall be administered an oath or affirmation, as may be prescribed by the Director-General.

(b) The oath or affirmation shall as far as possible be administered by the Commander of the person to be attested or in the unavoidable absence of the Commander by the person authorised in writing by the Commander in this behalf.

(c) The oath or affirmation shall be administered when the person to be attested has completed his training.

CHAPTER III ORGANISATION

13. Constitution and Control of the Security Guard.—(1) In exercising command and supervision of the Security Guard, the Director-General shall be assisted by the Additional Directors-General, Inspectors-General, Deputy Inspectors-General, Group Commanders and other officers.

(2) The responsibility for the command, discipline, morale and administration shall,—

- (a) in the case of Additional Director-General, extend to all groups, units, headquarters, establishments and Security Guard personnel placed under him and within the area that may be assigned to him ;
- (b) in the case of Inspector-General, extend to all groups, units, headquarters, establishments and Security Guard personnel placed under him and within the area that may be assigned to him ;
- (c) in the case of Deputy Inspector-General, extend to all the groups, other personnel and units placed under him and within the area that may be assigned to him ; and
- (d) in the case of a Commander, extend to the group or unit placed under him and within the area assigned to him.

(3) The command, discipline, administration and training of groups, units and establishments not placed under a Deputy Inspector-General or an Inspector-General shall be carried out by such officers and in such manner as may from time to time be laid down by the Director-General.

(4) Any member of the Security Guard shall be liable to perform any duties in connection with the operations against terrorists, the administration, discipline and welfare of the Security Guard and such other duties as he may be called upon to perform in accordance with any law for the time being in force and any order given in this behalf by a superior officer shall be a lawful command for the purposes of the Act.

14. Command.—(1) An officer appointed to command shall have the power of command over all officers and men, irrespective of seniority, placed under his command.

(2) (a) In the contingency of an officer being unable to exercise the command, to which he has been appointed, due to any reason, the command shall devolve on the second-in-command, if one has been so appointed.

(b) If no second-in-command has been appointed, it shall devolve on the officer who may be appointed to officiate by the immediate superior of the officer unable to exercise command.

(c) If no such officer has been so appointed, command shall devolve on the senior most officer present.

(d) The inability of an officer to exercise command and its assumption by any other officer in accordance with this sub-rule shall be immediately reported to the next higher authority by the officer who has assumed such command.

(3) If persons belonging to different units are working together :—

(i) in regard to the specific task on which they are engaged, the officer appointed to command or in his absence the senior most officer present shall exercise command over all such persons.

(ii) in all other matters the senior officer belonging to each unit shall exercise command over persons belonging to his unit.

(4) Disciplinary powers over a person subject to the Act shall be exercised by the Commander of the unit to which such a person belongs or the officer on whom command has devolved in accordance with sub-rule (2).

(5) Where such a person is doing detachment duty, including attendance at a course of instruction, the Commander of the unit, centre or establishment with which he is doing such duty shall also have all the disciplinary powers of a Commander.

(6) The Director-General, the Inspector-General and the Deputy Inspector-General may specify one or more officers of the staff who shall exercise the disciplinary powers of a Commander in respect of persons belonging to or doing detachment duty at their respective Headquarters.

(7) The Director-General may also specify Officers who shall exercise the disciplinary powers of an Inspector-General and Deputy Inspector-General respectively in respect of persons belonging to or doing detachment duty at his Head Quarters.

(8) An Inspector-General may specify an officer who shall exercise the disciplinary powers of a Deputy Inspector-General in respect of persons belonging to or doing detachment duty at his Head Quarters.

Explanation.—In sub-rules (1) and (3) the word “officer” shall include Assistant Commanders and Rangers Grade I.

CHAPTER IV

TERMINATION OF SERVICE

15. Termination of service of officers by the Central Government on account of mis-conduct.—(1) When it is proposed to terminate the service of an officer under section 9 on account of mis-conduct, he shall be given an opportunity to show cause in the manner specified in sub-rule (2) against such action.

Provided that this sub-rule shall not apply :—

(a) Where the service is terminated on the ground of conduct which has led to his conviction by a criminal court or a Security Guard Court ; or

(b) where the Central Government is satisfied that for reasons, to be recorded in writing, it is not expedient or reasonably practicable to give to the officer an opportunity of showing cause.

(2) When after considering the reports on an Officer's mis-conduct, the Central Government or the Director-General is satisfied that the trial of the Officer by a Security Guard Court is inexpedient or impracticable, but is of the opinion, that the further retention of the said Officer in the service is undesirable, the Director-General shall so inform the officer together with particulars of allegations and report of investigation (including the statement of witnesses, if any, recorded and copies of documents, if any, intended to be used against him) in cases where allegations have been investigated and he shall be called upon to submit, in writing, his explanation and defence :

Provided that the Director-General may withhold disclosure of such report or portion thereof if, in his opinion, its disclosure is not in the interest of the Security of the State.

(3) In the event of the explanation of the Officer being considered unsatisfactory by the Director-General, or when so directed by the Central Government, the case shall be submitted to the Central Government with the Officer's defence and the recommendation of the Director-General as to the termination of the officer's service in the manner specified in sub-rule (4).

(4) When submitting a case to the Central Government under the provisions of sub-rule (2) or sub-rule (3), the Director-General shall make his recommendation whether the officer's service should be terminated, and if so, whether the officer should be :—

- (a) dismissed from the service ; or
- (b) removed from the service ; or
- (c) retired from the service ; or
- (d) called upon to resign.

(5) The Central Government, after considering the reports and the officer's defence, if any, or the judgement of the criminal court, as the case may be, and the recommendation of the Director-General, may remove or dismiss the officer with or without pension or retire or get his resignation from service, and on his refusing to do so, the officer may be compulsorily retired or removed from the service with pension or gratuity, if any, admissible to him.

16. Termination of Service of officers by the Central Government on grounds other than mis-conduct.—

(1) When the Director-General is satisfied that an officer is unsuitable to be retained in service, the officer—

- (a) shall be so informed ;
- (b) shall be furnished with the particulars of all matters adverse to him ; and
- (c) shall be called upon to urge any reasons he may wish to put forward in favour of his retention in the service :

Provided that clauses (a), (b) and (c) shall not apply, if the Central Government is satisfied that for reasons, to be recorded by it in writing, it is not expedient or reasonably practicable to comply with the provisions thereof :

Provided further that the Director-General may not furnish to the officer any matter adverse to him, if in his opinion, it is not in the interest of the security of the State to do so.

(2) In the event of the explanation being considered by the Director-General unsatisfactory, the matter shall be submitted to the Central Government for orders, together with the officer's explanation and the recommendation of the Director-General.

(3) The Central Government after considering the reports, the explanation, if any, of the officer and the recommendation of the Director-General, may call upon the officer to retire or resign and on his refusing to do so, the officer may be compulsorily retired from the service with pension or gratuity, if any, admissible to him.

17. Dismissal or removal of persons other than Officers on account of mis-conduct.—(1) When it is proposed to terminate the service of a person subject to the Act other than an officer, he shall be given an opportunity by the authority competent to dismiss or remove him to show cause in the manner specified in sub-rule (2) against such action :

Provided that this sub-rule shall not apply :—

- (a) where the service is terminated on the ground of conduct which has led to his conviction by a criminal court or a Security Guard Court ; or
- (b) where the competent authority is satisfied that, for reasons to be recorded in writing, it is not expedient or reasonably practicable to give the person concerned an opportunity of showing cause.

(2) When after considering the reports on the misconduct of the person concerned, the competent authority is satisfied that the trial of such a person is inexpedient or impracticable, but is of the opinion, that his further retention in the service is undesirable, it shall so inform him together with all reports adverse to him and he shall be called upon to submit, in writing, in his explanation and defence :

Provided that the competent authority may withhold from disclosure any such report or portion thereof, if, in his opinion, its disclosure is not in the public interest.

(3) The competent authority after considering his explanation and defence, if any, or the judgement of the criminal court, as the case may be, may dismiss or remove him from the service with or without pension.

(4) All cases of dismissal or removal under this Rule, shall be reported to the Director-General

18. Retirement of officers on grounds of physical unfitness.—(1) Where an officer not below the rank of a Deputy Inspector-General considers that an officer of the Security Guard is unfit to perform his duties because of his physical condition, the officer shall be brought before a medical board.

(2) The medical board shall consist of such officers and shall be constituted in such manner as may, from time to time, be laid down by the Director-General.

(3) Where the medical board considers the officer to be unfit for service, the Central Government shall if it agrees with the finding of the Medical Board, communicate to the said officer the findings of the medical board and thereupon, within a period of fifteen days of such communication, the officer may make a representation against it to the Central Government.

(4) The Central Government may, on receiving the representation from the officer, refer the case to be reviewed by a fresh medical board constituted for the purpose and order the retirement of the said officer if the decision of the fresh medical board is adverse to him.

19. Retirement of Assistant Commanders on grounds of unsuitability.—Where a Commander not below the rank of Group Commander is satisfied that an Assistant Commander is unsuitable to be retained in the Security Guard, he may recommend to the competent authority for the retirement of such a Assistant Commander.

Thereupon, the Inspector-General, in the case of Assistant Commander Grade I and the Deputy Inspector-General in the case of Assistant Commander Grade II and Grade III may, after giving such an Assistant Commander, an opportunity of showing cause (except when he considers it to be impracticable to give such opportunity), retire the said Assistant Commander from the Security Guard.

20. Retirement of Rangers and Combatised Tradesmen, on grounds of unsuitability.—Where a Commander not below the rank of Group Commander is satisfied that a Ranger or a Combatised Tradesman is unsuitable to be retained in the Security Guard, the Commander may, after giving such Ranger or a Combatised Tradesman an opportunity of showing cause (except where he considers it to be impracticable to give such opportunity), retire the said Ranger or a Combatised Tradesman from the Security Guard.

21. Retirement of Assistant Commanders, Rangers and Combatised Tradesmen on grounds of physical unfitness.—(1) Where a Commander not below the rank of Group Commander is satisfied that an Assistant Commander, a Ranger or a Combatised Tradesman is unable to perform his duties by reason of any physical disability, he may direct that the said Assistant Commander, the Ranger or the Combatised Tradesman, as the case may be, be brought before a Medical Board.

(2) The Medical Board shall be constituted in such manner as may be determined by the Director-General.

(3) Where the said Assistant Commander, Ranger or Combatised Tradesman is found by the Medical Board to be unfit for further service in the Security Guard, the Commander shall forward the proceedings of the Medical Board to the Inspector-General in the case of Assistant Commander Grade I and the Deputy Inspector-General in the case of Assistant Commander Grade II and Grade III. The Inspector-General or the Deputy Inspector-General, or as the case may be, the Commander in the case of Ranger or Combatised Tradesman, shall if he agrees with the finding of the Medical Board, inform the person concerned about it, to enable him to represent against the decision of the Medical Board within a period of fifteen days from the date of receipt of such communication.

(4) Where the person declared to be unfit for further service makes a representation under sub-rule (3), the same shall be forwarded to the next superior officer, who shall have the case referred to be reviewed by a fresh medical board, which will be constituted in such manner as may be determined by the Director-General.

The superior officer may, having regard to the finding of the fresh medical board, pass such order as he may deem fit.

(5) Where no representation is made against the decision of the medical board under sub-rule (3), the Inspector-General or the Deputy Inspector-General or as the case may be, the Commander, may (if he agrees with the finding of the Medical Board), order the retirement of the Assistant Commander Grade I or the Assistant Commander Grade II and III, or as the case may be, the Ranger or Combatised Tradesman, respectively.

22. Resignation.—(1) The Central Government may, having regard to the special circumstances of any case, permit any officer of the Security Guard to resign from the Security Guard before the attainment of the age of the retirement or before putting in such number of years of service as may be necessary under the rules to be eligible for retirement :

Provided that while granting such permission the Central Government may :

- (i) require the officer to refund to the Government such amount as would constitute the cost of training given to that officer; or
- (ii) in case the officer is eligible for pensionary benefits under the pension rules, order such reduction in the pension or other pensionary benefits of the officer as the Government may consider to be just and proper in the circumstances.

(2) The Central Government may accept the resignation under sub-rule (1) with effect from such date as it may consider expedient :

Provided that it shall not be later than three months from the date of receipt of such resignation.

(3) The Central Government may refuse to permit an officer to resign,

- (a) if an emergency has been declared in the country either due to internal disturbances or external aggression; or
- (b) if it considers it to be inexpedient so to do in the interest of the discipline of the Security Guard; or
- (c) if the officer has specifically undertaken to serve for a specified period and such period has not expired.

(4) The provisions of this rule shall apply to and in relation to Assistant Commanders, Rangers and Combatised Tradesmen as they apply to and in relation to any officer of the Security Guard and the powers vested in the Central Government under sub-rules (1) and (2) shall be exercised in the case of an Assistant Commander Grade I, by an Inspector-General, in the case of Assistant Commanders Grades II and III by a Deputy Inspector-General and in the case of Ranger Grade I, Ranger or a Combatised Tradesman, by a Group Commander.

23. Powers to be exercised by a Superior Officer or authority.—Any power conferred by the provisions of this Chapter on an officer may also be exercised by an officer or authority superior in command to the first mentioned officer.

24. Appeal against orders of dismissal, removal or retirement.—(1) A person subject to the Act other than an officer who has been dismissed, removed or prematurely retired from service, shall have the right to put in an appeal against the termination of his service to any of the authority, higher than the one who has passed the termination order within ninety days of the termination of service.

(2) In case of officers, appeal shall lie to the Central Government and such appeal shall be filed within ninety days of the termination of service.

(3) Where the appellate authority sets aside the order of dismissal removal or retirement under this rule, such authority shall pass such orders as may be necessary in respect of the period of absence from duty of the person whose dismissal, removal or retirement has been set aside.

25. Date of dismissal, removal, discharge, retirement.—(1) The effective date of dismissal, removal, resignation or retirement shall be :—

- (a) the date mentioned in the order of dismissal or removal or discharge or order sanctioning of accepting resignation or retirement or,
- (b) if no such date is mentioned, the date on which the order was signed or the date on which the person concerned is relieved from duties, whichever is later.

(2) The dismissal, removal, discharge, resignation or retirement of a person subject to the Act shall not be retrospective.

CHAPTER V

ARREST AND INVESTIGATION

26. Forms of arrest.—(1) Arrest may be either open or close arrest.

(2) An arrest, unless otherwise specified, shall mean an open arrest.

(3) An order imposing arrest may be communicated to the person to be arrested either orally or in writing.

27. Authority to order arrest.—(1) No person subject to this Act shall be arrested on a charge under the Act except under and in accordance with the orders of a superior officer having power of command over him.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) any person subject to the Act may be placed under arrest by any superior officer :—

- (a) if he commits an offence against such superior officer, or
- (b) if he commits an offence in the view of such superior officer, or
- (c) if he is behaving in a disorderly manner and the said superior officer considers it necessary to place such a person under arrest with a view to stop such disorderly behaviour.

(3) A superior officer effecting arrest under sub-rule (2) shall, as soon as possible, and in any case within twenty four hours of such arrest send a report to the Commander of the group or unit of which the person arrested is a member and in case of the arrest of an officer of and above the rank of Group Commander to his immediate superior officer.

28. Arrest how imposed.—(A) Close arrest.—(1) (a) Close arrest, in the case of a Ranger Grade II and a combatised Tradesman, shall be imposed by informing the person to be arrested and ordering him to be marched to the place of confinement under an escort of persons of similar or superior rank.

(b) Where no such escort is available the person arrested shall be ordered to report himself immediately to the quarter guard or other place of confinement.

(2)(a) Close arrest in the case of officers, Assistant Commanders and Rangers Grade I shall be imposed by placing such officer, Assistant Commander, Ranger Grade I under the custody of another person of similar or superior rank and wherever considered necessary such officer, Assistant Commander or Ranger Grade I may be confined under charge of a guard.

(b) The person under arrest shall not leave the place of his confinement without permission of a superior officer designated by the Commander in this behalf.

(B) Open Arrest.—(3)(a) Open arrest shall be imposed by informing the person to be arrested that he is under open arrest and that he shall confine himself within such limits as may be specified in this behalf by the concerned superior officer effecting such arrest.

(b) The Commander may, from time to time, vary the limits referred to in clause (a) above.

29. Release from arrest during investigation.—(1) Any person arrested under rule 27 may be released from arrest under the order of an officer :

Provided that in case of a person placed under arrest by an officer, such person shall be released from arrest under the order of an officer superior to the officer ordering arrest.

(2) Subject to the provisions of rule 30, no person except on the basis of any fresh evidence against him be re-arrested.

30. Release without prejudice to re-arrest.—Pending the completion of the investigation or convening of a Court, any person, who has been placed under arrest, may without prejudice to re-arrest be released by his Commander or by any officer superior to his such Commander.

31. Arrest when to be imposed.—(1) Any person charged with :

- (i) an offence under section 15 or clause (a) or clause (b) of section 16 or section 17 or section 20 or sub-section (1) of section 21.
- (ii) a civil offence punishable with death or imprisonment for life.

(iii) any other offence under the Act :—

- (a) if the interest of discipline so require, or
- (b) if the person concerned deliberately undermines discipline, or
- (c) if the person concerned is of violent disposition, or,
- (d) if the person concerned is likely to absent himself with a view to avoid trial, or
- (e) if the person concerned is likely to interfere with witnesses or tamper with evidence,

shall be placed under arrest.

(2) Where any person arrested shows symptoms of sickness, medical assistance shall be provided for such persons.

32. Special provision in case of arrest of a drunken person.—(1) Where a drunken person has been arrested, he shall, as far as possible, be confined separately and shall be visited by duty officer, duty Assistant Commander or duty Ranger in charge of the guard, once every two hours.

(2) A drunken person shall not be taken before a superior officer for investigation of his case until he has become sober.

33. Arrest in case of persons whose trial has been ordered.—(1) Unless the convening officer has otherwise directed, on the commencement of the trial of a person by the Court, the said person shall be placed under arrest by his Commander and shall remain under arrest during the trial.

(2) Where a sentence lower than that of imprisonment is passed by a Court, the arrested person may be released by his Commander pending confirmation of the finding and sentence :

Provided that the convening authority may rescind, vary or modify the order passed by a Commander under sub-rule (1) or sub-rule (2) and where no such order is passed by a Commander, the convening authority may pass such order as it may deem proper :

Provided further that a person who has been sentenced to be dismissed shall not, except while on active duty, be put on any duty.

34. Delay Report.—(1)(a) The report on reason for delay as required under section 57 shall be in the form set out in Appendix I and it shall be sent by the Commander to the Deputy Inspector-General under whom the accused may be serving.

(b) A copy of the eighth delay report and every succeeding report thereof shall also be sent to the Inspector-General under whom the accused may be serving.

(2) Where the accused is kept under arrest for a period exceeding three months without being brought to trial, a special report regarding the action taken and the reasons for the delay shall be sent by the

Commander to the Director-General with a copy each to the Deputy Inspector-General and the Inspector-General concerned.

35. Rights of a person under arrest.—(1) (a) Any person placed under arrest shall, at the time of being placed under arrest, be given in writing by the officer effecting the arrest of the particulars of the charges against him.

(b) Notwithstanding anything contained in clause (a), where during the investigation other offences committed by the accused are discovered, it shall be lawful to charge such person with those offences.

(2)(a) The duty officer or duty Assistant Commander shall every day make a visit to the person under arrest and take the orders of the Commander on any request or representation made by the person under arrest.

(b) The request or representation made by the person under arrest shall be entered in the form set out in Appendix II.

CHAPTER VI

CHOICE OF JURISDICTION BETWEEN SECURITY GUARD COURT AND CRIMINAL COURT

36. Trial of cases either by Security Guard Court or Criminal Court.—(1) Where an offence is triable both by a criminal court and a Security Guard Court, an officer referred to in section 77 may,—

- (i) (a) Where the offence is committed by the accused in the course of the performance of his duty as a member of the Security Guard, or
- (b) where the offence is committed in relation to property belonging to the Government or the Security Guard or a person subject to the Act, or
- (c) where the offence is committed against a person subject to the Act,

direct that any person subject to the Act, who is alleged to have committed such an offence, be tried by a Security Guard Court; and

- (ii) in any other case, decide whether or not it would be necessary in the interest of discipline to claim for trial by a Court any person subject to the Act who is alleged to have committed such an offence.

(2) In taking a decision to claim an offender for trial by a Security Guard Court, an officer referred to in section 77 may take into account all or any of the following factors, namely :

- (a) the offender is on active duty or has been warned for active duty and it is felt that he is trying to avoid such duty;
- (b) the offender is a young person undergoing training and the offence is not a serious one and the trial of the offender by a criminal court would materially affect his training;

- (c) the offender can, in view of the nature of the case, be dealt with summarily under the Act.

37. Cases which may not be tried by Security Guard Court.—Without prejudice to the provisions of sub-rule (1) of rule 36, an offender may not normally be claimed for trial by a Security Guard Court: —

- (a) where the offence is committed by him alongwith any other person not subject to the Act whose identity is known or
- (b) where the offence is committed by him while on leave or during absence without leave.

CHAPTER VII

INVESTIGATION AND SUMMARY DISPOSAL

38. Statement of allegations.—Where it is alleged that a person subject to the Act has committed an offence punishable thereunder, the allegation shall be reduced to writing in the form set out in Appendix III in the case of persons of and below the rank of Ranger Grade I and in the form set out in Appendix IV in the case of Officers and Assistant Commanders.

39. Hearing by the Team Commander and Squadron Commander.—(1) (a) In the case of a person, subject to the Act, other than an Officer and an Assistant Commander, the case may, in the first instance, be heard by his Team Commander or by his Squadron Commander.

- (b) the witnesses shall be heard in the presence of the accused who shall have the right to cross-examine them.
- (c) the accused shall have the right to call witnesses in defence and to make a statement.

(2) After hearing the accused under sub-rule (1), the Team Commander or the Squadron Commander, as the case may be, may award any punishment which he is empowered to award, or dismiss the charge when the charge is not proved, or refer the case for disposal by the Commander :

Provided that he shall not dispose of the case which has been reserved by the Commander for disposal by himself or if the accused is under close arrest.

40. Hearing by the Commander.—(1) The Commander of and above the rank of Group Commander may hear the charge against all ranks in accordance with the provisions of sub-rule (1) of rule 39 and may:

- (i) award any punishment which he is empowered to award in respect of persons of and below the rank of a Ranger Grade I, or
- (ii) dismiss the charge, or

- (iii) remand the case for preparing a record of evidence or an abstract of evidence against the accused, or

- (iv) in the case of an accused of and below the rank of Ranger Grade I, remand the accused for trial by Summary Security Guard Court:

Provided that,

- (a) in the case of an Officer, the evidence of witnesses shall be reduced to writing if he so demands.
- (b) the Commander shall dismiss the charge, if in his opinion, the charge is not proved or may dismiss it if he considers that because of the previous character of the accused and the nature of the charge against him, it is not advisable to proceed further with it. In case of an Officer, he shall record reasons for dismissing the charge.
- (c) where a case in respect of an Officer has been referred to the Commander by a superior authority for initiation of disciplinary action, the Commander shall not dismiss the charge without reference to such authority.
- (d) in case of all offences punishable with death, a record of evidence shall be prepared.

(2) Where the Commander is of the opinion that the charge against an officer or an Assistant Commander is of a serious nature, he may, without hearing the charge in accordance with the provisions of sub-rule (1), straightaway order a record of evidence or an abstract of evidence to be prepared in the case.

(3) Where the Commander is of the opinion that the charge against an Officer or an Assistant Commander does not deserve to be dismissed, and the charge is also not so serious as may warrant trial by a Security Guard Court, he may, in the case of an Assistant Commander, either dispose of the case himself or refer it to the appropriate authority for disposal under the provisions of section 54. In the case of an Officer, he may refer the case to the appropriate authority for summary disposal under the provisions of section 53.

(4) Where disciplinary action is intended to be taken against an Officer in command of a Group, or a Unit, or a Headquarters, such Officer shall be removed from the command of the Group, the Unit, or the Headquarters, as the case may be, and for the purpose, shall be attached to or posted to a Group Unit, or a Headquarters under the Command of an Officer senior to the Officer to be so attached or posted.

41. Procedure for summary disposal of charges against Officers.—(1) Where an Officer is remanded for the summary disposal of a charge against him, he

shall be provided substance of evidence available against him or a copy of the record or abstract of evidence, if prepared, along with a copy of the charge-sheet as soon as practicable and in any case not less than 24 hours before the commencement of the proceedings.

(2) The Officer dealing with the case under section 53 shall, unless the accused has consented in writing to dispense with the attendance of witnesses, hear the evidence in the presence of the accused who shall have the right to cross-examine witnesses. The accused shall have the right to call any witness and make a statement in his defence.

(3) Proceedings shall be recorded as far as practicable in accordance with the form in Appendix XIV, and in every case in which the punishment is awarded, the proceedings along with substance of evidence or record or abstract of evidence, as the case may be, shall be forwarded to the next higher authority through the Judge Attorney-General or any Officer authorised by him who may if the punishment awarded appears to him to be illegal, unjust or excessive, vary or remit the punishment or set aside the proceedings, or make such other directions as may be appropriate in the circumstances of the case.

(4) An Officer who considers himself aggrieved by any decision given under this rule, may submit one petition through his Commander, with one month of the disposal of the case to the Director-General who may pass such order or direction as may be appropriate in the circumstances of the case.

42. Summary disposal of charges against Assistant Commanders.—(1) Where an Assistant Commander is charged with an offence under the Act, he shall be dealt with by the authority empowered under section 54 in the same manner as nearly as circumstances admit, as provided in rule 41.

(2) Proceedings shall be recorded as soon as practicable in accordance with the form in Appendix XIV, and in every case in which the punishment is awarded, the proceedings along with substance of evidence or record or abstract of evidence, as the case may be, shall be forwarded to the next higher authority through the Judge Attorney-General or any officer authorised by him who may, if the punishment awarded appears to him to be illegal, unjust or excessive, vary or remit the punishment or set aside the proceedings, or make such other directions as may be appropriate in the circumstances of the case.

(3) An Assistant Commander who considers himself aggrieved by any decision given under this rule may submit one petition through his Commander within one month of the disposal of the case, to the authority superior to the one who awarded the punishment, and such authority may pass such order or direction as may be appropriate in the circumstances of the case.

43. Attachment to another unit.—The Commander shall not deal with any case.

- (i) where the offence with which the accused is charged is against the Commander himself, or

- (ii) where the Commander is himself a witness in the case against the accused, or

- (iii) where the Commander is otherwise personally interested in the case, the accused shall be attached to another Group or Unit or a headquarter for disposal of the case under the order of the competent authority.

Provided that a Commander shall not be disqualified from hearing a charge merely because the offence was committed against the property of a Security Guard Mess, band or institution of which the Commander is a member or trustee or because the offence is one of disobedience of such Commander's orders.

44. Charges not to be dealt with summarily.—A charge for an offence under section 15 or clauses (a) and (b) of section 16 or section 17 or clause (a) of section 18 or clause (a) of section 20 or clause (a) of section 23 or section 45 (other than that for simple hurt or theft) or a charge for abetment of or an attempt to commit any of these offences, shall not be dealt with summarily.

45. Record of evidence.—(1) The Commander may either prepare the record of evidence himself or detain another officer to do so.

(2) The witnesses shall give their evidence in the presence of the accused and the accused shall have right to cross-examine all witnesses who give evidence against him.

(3) After all the witnesses against the accused have been examined, he shall be cautioned in the following terms: "You may make a statement if you wish to do so, you are not bound to make one and whatever you state shall be taken down in writing and may be used in evidence". After having been cautioned in the aforesaid manner whatever the accused states shall be taken down in writing.

(4) The accused may call witnesses in defence and the officer recording the evidence may ask any question that may be necessary to clarify the evidence given by such witnesses.

(5) All witnesses shall give evidence on oath or affirmation:

Provided that, no oath or affirmation shall be given to the accused nor shall he be cross-examined.

(6) (a) The statements given by witnesses shall ordinarily be recorded in narrative form and the officer recording the evidence may, at the request of the accused, permit any portion of the evidence to be recorded in the form of question and answer.

(b) The witnesses shall sign their statements after the same have been read over and explained to them.

(7) The provisions of section 86 shall apply for procuring the attendance of witnesses before the officer preparing the record of evidence. Witnesses shall be summoned as per specimen given in Appendix XV.

(8) Where a witness cannot be compelled to attend or is not available or his attendance cannot be procured without an undue wastage of time or expenditure of money and after the officer recording the evidence has given a certificate in this behalf, a written statement signed by such witness may be read to the accused and included in the record of evidence.

(9) After the recording of evidence is completed, the officer recording the evidence shall give a certificate in the following form :—

“Certified that the record of evidence ordered by
Commander
was made in the presence and hearing of the accused and the provisions of rule 45 have been complied with”.

(10) No counsel or legal practitioner shall be permitted to appear before the Officer making the record of evidence.

46. Abstract of evidence.—(1) An abstract of evidence shall be prepared either by the Commander or an officer detailed by him.

(2) (a) The abstract of evidence, shall include,

(i) signed statements of witnesses wherever available or a precise thereof, and

(ii) copies of all documents intended to be produced at the trial.

(b) Where signed statements of any witnesses are not available, a precise of the evidence that the witnesses are likely to give shall be included.

(3) A copy of the abstract of evidence shall be given by the officer making the same to the accused and the accused shall be given an opportunity to make a statement if he so desires after he has been cautioned in the manner laid down in sub-rule (3) of rule 45 :

Provided that the accused shall be given such time as may be reasonable in the circumstances but in no case less than twenty-four hours after receiving the abstract of evidence to make his statement.

47. Investigation of cases by Police.—Where the Commander considers it necessary so to do, he may lodge a report with the Police for investigation of any case.

48. Disposal of case by Commander after record or abstract of evidence.—(1) Where an officer has been detailed to prepare the record of evidence or to make an abstract thereof he shall forward the same to the Commander.

(2) The Commander may, after going through the record or abstract of evidence prepared by him or by another officer,—

(i) remand the case for recording additional evidence, if required, or

(ii) dismiss the charge provided that where disciplinary action has been initiated against an officer on a reference from a superior authority, the charge shall not be dismissed without reference to such an authority, or

(iii) rehear the charge and award one of the summary punishments, or

(iv) try the accused summarily under section 51 or by a Summary Security Guard Court where he is empowered so to do, or

(v) remand the case for summary disposal by the competent authority in the case of an Officer or an Assistant Commander, or

(vi) apply to a competent officer or authority to convene a Court for the trial of the accused.

49. Application for a Court.—An application for a Court shall, as far as possible, be made by the Commander in the form set out in Appendix V and shall be accompanied by five copies of the record or abstract of evidence and charge-sheet and such other documents as are mentioned in that application form.

CHAPTER VIII

ON CHARGES AND MATTERS ANTECEDENT TO TRIAL

50. Charge-Sheet.—(1) A charge sheet shall contain the whole of the issue or issues to be tried at one time and may contain more than one charge, if the charges are founded on the same facts or form part of a series of offences of same or similar character;

Provided that a charge under sections 18, 19, 28 and 31 may be included in any charge sheet, notwithstanding that other charges in that charge sheet are not founded on the same facts or do not form part of a series of offences of the same or similar character.

(2) Every charge sheet shall, as far as possible be prepared as per the specimen set out in Appendix IV.

51. Charges.—(1) There shall be a separate charge for each offence.

(2) (a) If a single act or series of acts is of such a nature that it is doubtful which of several offences the facts which can be proved will constitute, the accused may be charged with having committed all or any of such offences, and any number of such charges may be tried at once or he may be charged in the alternative with having committed some one of the said offences.

(b) The charge for the more serious offence shall precede the one for the less serious offence.

(3) Each charge shall consist of two parts, namely :—

(a) statement of the offence, and

(b) particulars of the offence.

(4) The offence shall be stated, if not a civil offence, as nearly as practicable, in the words of the Act, and if a civil offence, in such words as would sufficiently describe that offence.

(5)(a) The particulars shall state the time and place of the alleged offence and the person (if any) against whom, or the thing (if any) in respect of which it was committed and these should be sufficient to give the accused notice of the matter with which he is so charged.

(b) In case such particulars are not sufficient to give the accused notice of the matter with which he is charged, the charge shall also contain sub particulars of the manner in which the offence was committed as will be sufficient for that purpose.

52. Joint Charges.—(1) Any number of accused may be charged jointly and tried together for an offence averred to have been committed jointly by them.

(2) Any number of accused though not charged jointly may also be tried together for an offence averred to have been committed by one or more of them and abetted by other or others.

(3) Where the accused are so charged under sub-rule (1) or sub-rule (2), any one or more of them may be charged with, and tried for, any other offence with which they could have been charged under such-rule (1) of rule 50.

53. Validity of charge sheet.—A charge sheet shall not be invalid merely by reasons of the fact that, it contains any mistake in the name or description of the accused, and in the construction of a charge sheet there shall be presumed in favour of supporting it every proposition which may reasonably be presumed to be impliedly included, though not expressed therein, and the statement of the offence and the particulars of the offence shall be read and construed together.

54. Amendment of the charge by the Security Guard Court.—(1) At any time during a trial, if it appears to the Court that there is in the charge sheet;

- (a) a mistake in the name or description of the accused, or
- (b) a mistake which is attributable to a clerical error or omission,

the Court may amend the charge sheet so as to correct the mistake.

(2) If at any time during a trial, at which there is a Judge Attorney, it appears to the Court, before it closes to deliberate on its findings, that it is desirable in the interest of justice to make any addition to, omission from or alteration in, a charge which cannot be made under sub-rule (1), it may, if such addition, omission, or alteration can be made without unfairness to the accused, and with the concurrence of the Judge Attorney, so amend the charge.

(3) If at any time during a trial, at which there is no Judge Attorney, it appears to the Court, before it closes to deliberate on its findings, that in the interest of justice, it is desirable to make any addition to, omission from or alteration in a charge, which cannot be made under sub-rule (1), it may adjourn and report its opinion to the convening officer, who may :—

- (a) amend the charge if permissible under rule 55 and direct the Court to try it as amended after due notice of the amendment has been given to the accused; or
- (b) direct the Court to proceed with the trial of the charge without amending it; or
- (c) convene a fresh Court to try the accused.

55. Amendment of Charge by Convening Officer.—When a Security Guard Court reports to the convening officer under either rule 54 or rule 70 he may amend the charge in respect of which the Court has reported to him, by making any addition to, omission from or alteration in the charge which, in his opinion, is desirable in the interest of justice and which he is satisfied, can be made without unfairness to the accused.

CONVENING OF GENERAL AND PETTY SECURITY GUARD COURTS

56. Action by a Superior Authority on receiving an application for convening a Court.—(1) As soon as a superior officer receives an application for convening a court, he shall scrutinise the charge and the evidence against the accused, where necessary in consultation with the Judge Attorney-General or an officer detailed for the purpose, by the Judge Attorney-General and he,

- (i) shall direct the Commander to dismiss the charge where the evidence against the accused is insufficient and further evidence is not likely to be available and may direct him to do so if he considers it inadvisable to proceed with the trial; or
- (ii) may return the case to the Commander for being tried by a Summary Security Guard Court or being dealt with summarily if he considers that the same can be adequately so tried or dealt with; or
- (iii) may dispose of the case administratively and if he is not competent to do so, may forward the case to higher authority with his recommendations; or
- (iv) may return the case for recording further evidence, if he considers the evidence recorded insufficient but considers that further evidence may be available.

(2) (a) In any other case he may either himself convene a Court or if he considers that a higher type of Court should be convened and he is not empowered to convene such a Court, forward the case to a higher authority with recommendation that such court may be convened.

(b) The higher authority on receiving the case may exercise any of the powers given in sub-rule (1) :

Provided that a superior officer or higher authority before convening a General Security Guard Court or a Petty Security Guard Court shall take the advice of the Judge Attorney-General or an officer detailed for the purpose by the Judge Attorney-General :

Provided further that the superior authority or higher authority while convening a Court may reframe the charge sheet on which the accused is to be tried.

57. Disqualification of officers for serving on General and Petty Security Guard Courts.—An officer shall be disqualified from serving on a Court, if he :

- (i) is an officer who convened the court ; or
- (ii) is the prosecutor or a witness for the prosecution ; or
- (iii) has taken any part in the investigation of the case, which would have necessitated applying his mind to any part of the evidence or to the facts of the case ; or
- (iv) is the Commander of the accused, or the Deputy Inspector-General under whose command the unit in which the accused was serving at the time the alleged offence was committed ; or
- (v) has a personal interest in the case.

58. Composition of General and Petty Security Guard Courts.—(1) A Court shall consist, as far as practicable, of officers of different units.

(2) The members of a Court for the trial of an officer shall be of a rank not lower than the rank of that officer, unless in the opinion of the convening officer, officers of such rank are not, having due regard to the exigencies of public service, available. Such opinion shall be recorded in the convening order.

59. Duties of convening officer when convening courts.—When an officer convenes a Court he shall :—

- (a) issue a convening order in the appropriate form set out in Appendix VI ;
- (b) direct upon what charges the accused is to be tried and ensure that the accused has been remanded for trial by a Court upon these charges, by his Commander ;
- (c) if he is of the opinion that charges shall be put in separate charge sheets, so direct and shall also direct the order in which they are to be tried ;
- (d) direct, if there is more than one accused whether the accused are to be tried jointly or separately ;
- (e) appoint members of the Court and any waiting members ;

(f) if convening :

a General Security Guard Court ; or a Petty Security Guard Court which he considers should be attended by a Judge Attorney, take the necessary steps to procure the appointment of a Judge Attorney by or on behalf of the Judge Attorney-General and may also appoint an officer to be under his instruction at the trial ;

(g) appoint an officer, subject to the Act or a counsel assisted by such an officer to prosecute ;

Provided that the convening officer may appoint more than one such officer or counsel to prosecute if he thinks fit ;

(h) appoint an interpreter wherever necessary ;

(i) send to the senior member the charge sheet, the convening order and a copy of the record or abstract of evidence from which any evidence, which in his opinion would be inadmissible at the trial has been expurgated ;

(j) forward to each member of the Court and to each waiting member a copy of charge sheet and the convening order ;

(k) forward to the prosecutor copies of the charge sheet and convening order and the original record or abstract of evidence together with an unexpurgated copy thereof showing the passages (if any) which have been expurgated in the copy sent to the senior member ;

(l) forward to the Judge Attorney (if any) copies of the charge sheet and convening order and an unexpurgated copy of the record or abstract of evidence showing the passages (if any) which have been expurgated in the copy sent to the senior member ;

(m) ensure that the Commander has summoned all the prosecution witnesses and such defence witnesses as the accused may have requested to be summoned under rule 61.

60. Preparation of defence by the accused.—(1) An accused, who has been remanded for trial, shall be afforded proper opportunity for preparing his defence and shall be allowed proper communication with his defending officer or counsel and with his witnesses.

(2) A defending officer, as far as possible of the choice of the accused, shall be appointed to defend an accused who has been remanded for trial unless the accused states in writing that he does not wish such an appointment to be made.

(3) If the prosecution is to be undertaken by a legally qualified officer or by a counsel the accused shall be notified of this fact in sufficient time to enable him, if he so desires to make arrangements for a legally qualified officer or counsel to defend him.

(4) As soon as practicable after a decision has been taken to place the accused on trial and in any case not less than four days before his trial he shall be given ;

- (a) a copy of the charge sheet ;
 - (b) an unexpurgated copy of the record or abstract of evidence showing the passages (if any) within, which have been expurgated in the copy sent to the senior member ;
 - (c) notice of any additional evidence which the prosecution intends to adduce ; and
 - (d) if the accused so requires, a list of the ranks, names, and units of the members who are to form the Court and of any waiting members.
- (5) When an accused is given a copy of the charge sheet and of the record or abstract of evidence in accordance with this rule, he shall :

- (a) have the charge explained to him ; and
 - (b) be informed that, upon his making a written request to his Commander not less than twenty four hours before his trial requiring the attendance at his trial of a witness (other than a witness for the prosecution) whom he desires to call in his defence (such witness to be named by him), reasonable steps will be taken in accordance with these rules to procure the attendance of any such witness at his trial.
- (6) The provisions of sub-rules (2) and (3) shall not apply in relation to a trial before a Summary Security Guard Court and in relation to such a trial the period of four days referred to in sub-rule (4) shall be construed as twenty four hours.

61. Summoning of Defence Witnesses.—(1) Subject to the provisions of sub-rules (2) and (3), the Commander shall, on a request made in this behalf by the accused, summon such witnesses as are specified by the accused.

(2) Where the Commander is satisfied that the evidence to be given by any witness is not likely to be of material assistance at the trial, he may refuse to summon such witness and while doing so he shall record in writing the reasons for not calling the witness.

(3) The Commander may, before summoning any witness, require the accused to defray or undertake to defray the cost of attendance of such witness and if the accused refuses to defray or undertake to defray the cost aforesaid, the Commander may refuse to procure the attendance of that witness.

(4) Where the Commander has refused to summon the witness under sub-rule (2) or sub-rule (3), the accused may make an application to the Court for the summoning of such witness and the Court may, if it considers it to be expedient in the interests of justice, order the summoning of such witness and, if

necessary, adjourn the proceedings for the attendance of such witness.

Explanation.—For summoning witnesses, summons as per specimen given in appendix XV shall be issued.

CHAPTER IX

PROCEDURE FOR GENERAL AND PETTY SECURITY GUARD COURTS

62. Assembly and swearing of Court.—(1) Upon a Security Guard Court assembling, the Court shall, before beginning the trial, satisfy itself in closed Court :—

- (a) that the Court has been convened in accordance with the Act and these rules ;
- (b) that the Court consists of not less than the minimum number of officers required by law ;
- (c) that the members are of the required rank ;
- (d) that the members have been duly appointed and are not disqualified under the Act ;
- (e) that if there is a Judge Attorney, he has been duly appointed ;
- (f) that the accused appears, from the charge-sheet, to be subject to the Act and to be subject to the jurisdiction of the Court ; and
- (g) that each charge is correct in law and framed in accordance with these rules.

(2) (a) Where a vacancy occurs through a member of the Court being disqualified under the Act, or being absent when the Court assembles, the presiding officer may appoint a duly qualified waiting member to fill that vacancy.

(b) The presiding officer may, if the interests of justice so require, substitute a duly qualified waiting member for a member appointed by the convening officer.

(3) If the Court is not satisfied on any of the matters mentioned in sub-rule (1) is not competent to rectify such matter itself under the Act or these rules, it shall before commencing the trial, report thereon to the convening officer.

(4) When the Court has complied with this rule and is ready to proceed with the trial, the presiding officer shall open the Court and the trial shall begin.

63. Commencement of Trial.—(1) The order convening the Court and the names of the officers appointed to try the accused shall be read in the hearing of the accused who shall be given an opportunity to object to any of those officers in accordance with section 81.

(2) When a Court is to try more than one accused whether separately or jointly, each accused shall be given an opportunity to object to any officer on the Court in accordance with the foregoing sub-rule and shall be asked separately whether he has any such objection.

(3) An accused shall state the names of all the officers to whom he objects before any objection is disposed of.

(4) If more than one officer is objected to, the objection to each officer shall be disposed of separately and the objection to the lowest in rank shall be disposed of first.

(5) An accused may make a statement and call any person to make a statement in support of his objection.

(6) An officer to whom the accused has objected may state in open Court any thing relevant to the objection of the accused whether in support or in rebuttal thereof.

(7) An objection to an officer shall be considered in closed Court by all the other officers on the Court and the officer objected to shall not be present at that time.

(8) When an objection to an officer is allowed under sub-section (3) of section 81 that officer shall forthwith retire and take no further part in the proceedings.

(9) When an officer objected to retire and there is duly qualified waiting member in attendance, the presiding officer shall immediately appoint him to take the place of the officer who has retired.

(10) The Court shall satisfy itself that a waiting member who takes the place of a member of the Court is of the required rank and not disqualified under the Act and shall give the accused an opportunity to object to him and shall deal with any such objection in accordance with the Act and these rules.

(11) If as the result of the allowing of an objection to a member there are insufficient officers available to form a Court in compliance with the Act, the Court shall report to the convening officer without proceeding further with the trial and the convening officer may either appoint an officer as a member to fill the vacancy or convene a fresh Court to try the accused.

64. Swearing or affirming of members.—As soon as the Court is constituted with the proper number of officers who are not objected to or objections in respect of whom have been overruled on oath or affirmation shall be administered to every member in presence of the accused in one of the following forms or in such other form to the same purport as the Court ascertains to be according to his religion or otherwise binding on his conscience.

FORM OF OATH

"I,.....swear by Almighty God, that I will, well and truly, try the accused (or accused persons), before the Court, according to the evidence, and that I will, duly administer justice, according to the National Security Guard Act, 1986, without partiality, favour or affection; and I do further swear that I will not, on any account, at any time, whatsoever, disclose or discover, the vote or opinion of any particular member of the Court unless required to give evidence thereof by a court of law".

FORM OF AFFIRMATION

"I,.....do solemnly, sincerely and truly, declare and affirm, that I will well and truly, try the accused (or accused persons), before the Court, according to the evidence, and that I will, duly administer justice according to the National Security Guard Act, 1986, without partiality, favour or affection; and I do further solemnly, sincerely and truly declare and affirm that I will not, on any account, at any time, whatsoever, disclose or discover, the vote or opinion of any particular member of this Court unless required to give evidence thereof by a Court of Law".

65. Swearing or affirmation of Judge Attorney and other officers.—After the members of the Court are all sworn or have made affirmation, an oath or affirmation shall be administered to the following persons or such of them as are present at the Court in such of the following forms as shall be appropriate, or in such other form to the same purport as the Court ascertains to be according to the religion or otherwise binding on the conscience of the person to be sworn or affirmed.

JUDGE ATTORNEY

FORM OF OATH

I,.....swear by Almighty God that I will, to the best of my ability, carry out the duties of Judge Attorney, in accordance with the National Security Guard Act, 1986, and the rules made thereunder without partiality, favour or affection, and I do further swear that I will not, on any account, at any time, whatsoever, disclose or discover the vote or opinion on any matter of any particular member of this Court, unless required to give evidence thereof by a Court of Law.

FORM OF AFFIRMATION

I,.....do hereby, solemnly, sincerely and truly declare and affirm that I will, to the best of my ability, carry out the duties of Judge Attorney in accordance with the National Security Guard Act, 1986, and the rules made thereunder without partiality, favour or affection, and I do further solemnly, sincerely and truly declare and affirm, that I will not, on any account, at any time, whatsoever, disclose or discover the vote or opinion, on any matter, of any particular member of this Court, unless, required to give evidence thereof by a Court of Law.

(B) OFFICER ATTENDING FOR THE PURPOSE OF INSTRUCTION**FORM OF OATH**

I,.....swear by Almighty God that I will not on any account; at any time, whatsoever, disclose or discover the vote or opinion of any particular member of this Court unless required to give evidence thereof by a Court of Law.

FORM OF AFFIRMATION

I,.....do solemnly, sincerely and truly, declare and affirm that I will not on any account, at any time, whatsoever, disclose or discover the vote or opinion of any particular member of this Court unless required to give evidence thereof by a Court of Law.

(C) SHORTHAND WRITER**FORM OF OATH**

I,.....swear by Almighty God that I will truly take down to the best of my power, the evidence to be given before this Court and such other matters as I may be required to take down and will, when required, deliver to the Court a true transcript of the same.

FORM OF AFFIRMATION

I,.....do solemnly, sincerely and truly, declare and affirm, that I will truly take down to the best of my power the evidence to be given before this Court and such other matters as I may be required to take down and will, when required, deliver to the Court a true transcript of the same.

(D) INTERPRETER**FORM OF OATH**

"I,.....swear by Almighty God that I will faithfully, interpret and translate, as I shall be required to do, touching the matter before this Court".

FORM OF AFFIRMATION

I,.....do solemnly, sincerely and truly declare and affirm that I will faithfully interpret and translate, as I shall be required to do, touching the matter before this Court.

66. Objection to Interpreter or Shorthand Writer.—A person shall not be sworn or affirmed as an interpreter or shorthand writer, if he is objected to by the accused unless the Court, after hearing the accused and the prosecutor, disallows such objections as being unreasonable.

67. Objection to Judge Attorney and Prosecutor.—The accused shall not be permitted to object to the Judge Attorney or the prosecutor.

68. Arraignment.—(1) When the Court and the Judge Attorney (if any) have been sworn, the charge will be read to the accused and shall be asked whether he pleads guilty or not guilty to the charge or charges.

(2) If there is more than one charge, against the accused he shall be required to plead separately to each charge.

(3) If there is more than one charge-sheet, against the accused, before the Court, the Court shall proceed with the charges in the first of such charge-sheets and shall announce its finding thereon and if the accused has pleaded guilty, comply with rule 75, before it arraigns him upon the charges in any subsequent charge-sheet.

69. Plea to Jurisdiction.—(1) The accused, before pleading to the charge, may offer a plea regarding the jurisdiction of the Court; and in such a case—

(a) the accused may adduce evidence in support of the plea and the prosecutor may adduce evidence in answer thereto; and

(b) the prosecutor may address the Court in answer to the plea and the accused may reply to the prosecutor's address.

(2) If the Court allows the plea it shall adjourn and report to the convening officer.

(3) When the Court reports to the convening officer under this rule, the convening officer shall :—

(a) if he approves the decision of the Court to allow the plea, dissolve the Court;

(b) if he disapproves the decision of the Court; either :—

(i) refer the matter back to the Court and direct them to proceed with the trial; or

(ii) convene a fresh Court to try the accused.

70. Objection to the charge.—(1) An accused before pleading to a charge may object to it on the grounds that it is not correct in law or is not framed in accordance with these rules and if he does so, the prosecutor may address the Court in answer to the objection and the accused may reply to the prosecutor's address.

(2) If the Court upholds the objection, it shall either amend the charge if permissible under rule 54 or adjourn and report to the convening officer :

Provided that if there is another charge or another charge-sheet before the Court, the Court may, before adjourning under this rule, proceed with the trial of such other charge or other charge-sheet.

(3) When the Court reports to the convening officer under this rule, the convening officer shall :—

(a) if he approves the decision of the Court to allow the objection :—

(i) dissolve the Court; or

(ii) where there is another charge or another charge-sheet before the Court which the Court has not tried, direct the Court to proceed with the trial of such other charge or charge-sheet only; or

(iii) amend the charge to which the objection relates, if permissible under rule 55, and direct the Court to try it as amended,

(b) If he disapproves the decision of the Court to allow the objection :—

- (i) direct the Court to try the charge ; or
- (ii) where there is another charge or another charge-sheet before the Court to which the objection does not relate and which the Court has not tried, direct the Court to proceed with the trial of such other charge or charge-sheet only ; or

(iii) convene a fresh Court to try the accused.

71. Plea in bar of trial.—(1) An accused before pleading to charge may offer a plea that the trial is barred under section 72 or section 73. If he does so :—

- (a) the accused may adduce evidence in support of the plea and the prosecutor may adduce evidence in answer thereto, and
- (b) the prosecutor may address the Court in answer to the plea and the accused may reply to the prosecutor's address.

(2) If the Court allows the plea it shall adjourn and report to the convening officer :

Provided that if there is another charge or another charge-sheet before the Court, the Court may, before adjourning under this rule, proceed with the trial of such other charge or other charge-sheet.

(3) When a Court reports to the convening officer under this rule, the convening officer shall :—

- (a) if he approves the decision of the Court to allow the plea,
 - (i) dissolve the Court ; or
 - (ii) where there is another charge or another charge-sheet before the Court, to which the plea does not relate and which the Court has not tried, direct the Court to proceed with the trial of such other charge or charge-sheet only.

(b) If he disapproves the decision of the Court to allow the plea :—

- (i) direct the Court to try the charge ; or
- (ii) where there is another charge or another charge-sheet before the Court, to which the plea does not relate and which the Court has not tried, direct the Court to proceed with the trial of such other charge or charge-sheet only ; or

(iii) convene a fresh Court to try the accused.

72. Application for separate trial.—(1) Where two or more accused are charged jointly, any one of the accused may, before pleading to the charge, apply to the Court to be tried separately on the ground that he would be prejudiced in his defence if he were not tried separately.

(2) Where the accused makes such an application, the prosecutor may address the Court in answer thereto and the accused may reply to the prosecutor's address.

(3) Where the Court is of the opinion that the interests of justice so require it shall allow the application and try separately the accused who made it.

73. Application for trial on separate charge-sheet.—(1) Where a charge-sheet contains more than one charge, the accused may, before pleading to the charges, apply to the Court to be tried separately on any charge in that charge-sheet on the ground that he would be prejudiced in his defence if he were not tried separately on that charge.

(2) Where the accused makes such an application, the prosecutor may address the Court in answer thereto and the accused may reply to the prosecutor's address.

(3) Where the Court is of the opinion that interests of justice so require, it shall allow the application and try the accused separately on the charge to which it relates as if that charge had been inserted in a separate charge-sheet.

74. Pleading to the charge.—(1) After any plea under rules 69 and 71, any objection under rule 70 and any applications under rules 72 and 73 have been dealt with, the accused shall be required subject to sub-rule (2) to plead either guilty or not guilty to each charge on which he is arraigned.

(2) Where a Court is empowered by section 90 to find an accused guilty of an offence other than that charged or guilty of committing the offence in circumstances involving a less degree of punishment or where it could after hearing the evidence, make a special finding of guilty subject to exceptions or variations in accordance with rule 95, the accused may plead guilty to such other offence or to the offence charged as having been committed in circumstances involving a less degree of punishment or to the offence charged subject to such exceptions and variations.

75. Acceptance of plea of guilty.—(1) Where an accused pleads guilty to a charge under either sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 74, the presiding officer or Judge Attorney shall, before the Court decides to accept the plea, explain to the accused the nature of the charge and the general effect of his plea and in particular to difference in procedure when an accused pleads guilty and when an accused pleads not guilty.

(2) The Court shall then cause the prosecutor to read the record or abstract of evidence to the Court or inform the Court of the facts contained therein :

Provided that if an expurgated copy of the record or abstract of evidence was sent to the presiding officer, the prosecutor shall not read to the Court those parts of the record or abstract of evidence

which have been expurgated or inform the Court of the facts contained in those parts, and shall not hand over the original record or abstract of evidence to the Court until the trial is concluded. Where there is no record or abstract of evidence, the Court shall record, in accordance with these rules, sufficient evidence to enable it to determine the sentence.

(3) A Court shall not accept a plea of guilty under sub-rule (1) of sub-rule (2) of rule 77, if,—

- (a) the Court is not satisfied that the accused understands the nature of the charge or the effect of his plea; or
 - (b) the presiding officer having regard to the evidence contained in the record of evidence or the abstract of evidence and all the circumstances, considers that the accused should plead not guilty; or
 - (c) the accused is liable, if convicted, to be sentenced to death.
- (4) (a) In the case of a plea of guilty under rule 76, a Court shall not accept the plea unless the convening officer concurs and it is satisfied of the justice of such course.

(b) The concurrence of the convening officer may be signified by the prosecutor.

(5) When a plea of guilty under sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 74 is not accepted by the Court or the accused either refuses to plead to the charge or does not plead to it intelligibly, the Court shall record a plea of not guilty.

(6) When a Court is satisfied that it can properly accept a plea of guilty under sub-rule (1) sub-rule (2) of rule 74, it shall record a finding of guilty in respect thereof.

(7) After the Court has recorded its findings, it shall give an opportunity to the accused to adduce evidence of character and to make a statement in mitigation of punishment.

(8) If from the evidence adduced by the accused and his statement made under sub-rule (7) the Court is satisfied that the accused did not understand the effect of the plea of guilty, it should alter the record and enter a plea of not guilty and proceed with the trial accordingly.

(9) After sub-rule (7) has been complied with and if Court has decided to accept the plea of guilty, the Court shall proceed as directed in rule 97.

76. Plea on alternative charge.—(1) When an accused pleads guilty to the first of two or more alternative charges, the Court, if it accepts the accused's plea of guilty, shall record a finding of guilty in respect of the first charge and the prosecutor shall withdraw any alternative charge before the accused is arraigned on it.

(2) When an accused pleads guilty to one of two or more charges which are laid in the alternative other than the first of such charges, the Court may—

(a) proceed as if the accused had pleaded not guilty to all the charges; or

(b) (i) With concurrence of the convening officer (which may be signified by the prosecutor) record a finding of guilty on the charge to which the accused has pleaded guilty and a finding of not guilty on any alternative charge which is placed before it in the charge-sheet.

(ii) Where the Court records such finding the prosecutor shall before the accused is arraigned on it withdraw any charge which is alternative to the charge of which the court has found the accused guilty and which is placed after it in the charge-sheet.

77. Order of trial where plea of guilty and not guilty.—(1) After the Court has recorded a finding of guilty, if there is no other charge in the same charge-sheet to which the accused has pleaded not guilty and no other accused who has pleaded not guilty to a charge in that charge-sheet, it shall proceed with the trial as directed by rule 75.

(2) Where there is another charge in the charge-sheet to which the accused has pleaded not guilty or there is another accused who has pleaded not guilty to a charge in that charge-sheet, the Court shall not comply with rule 75 until after it has dealt with such other charge or tried such other accused and has announced and recorded its finding in respect thereof.

78. Change of plea.—(1) An accused who has pleaded not guilty may at any time before the Court closes to deliberate on its finding withdraw his plea of not guilty and substitute a plea of guilty (including a plea of guilty under rule 76) and in such a case the Court shall, if it is satisfied that it can accept the accused's changed plea under these rules, record a finding in accordance with the accused's changed plea and so far as is necessary proceed as directed by rule 75.

(2) Where at any time during the trial it appears to the Court that an accused who has pleaded guilty does not understand the effect of his plea or the nature of the charge the Court shall enter a plea of not guilty and proceed with the trial accordingly.

(3) When the Court records a plea of not guilty in respect of any charge under sub-rule (2) it shall, if there was a charge laid in the alternative thereto which the prosecutor withdrew under rule 76 re-instate such alternative charge, arraign the accused thereof and proceed with the trial as if it had never been withdrawn.

79. Procedure on pleas of not guilty.—After a plea of not guilty to any charge has been recorded:—

(i) the Court shall ask the accused whether he wishes to apply for an adjournment on the ground that any, of these rules relating to procedure before trial have not been complied with and that he has been prejudiced thereby or on the ground that he has not had sufficient opportunity for preparing his defence;

(ii) Where the accused applies for an adjournment;

(a) the accused may adduce evidence in support of his application and the prosecutor may adduce evidence in answer thereto; and

(b) the prosecutor may address the Court in answer to the application and the accused may reply to the prosecutor's address;

(iii) the Court may grant an adjournment if it thinks the interests of justice so require.

80. Opening address.—(1) The prosecutor may, if he so desires, and shall, if required by the Court, make an opening address explaining the charge and the nature and general effect of the evidence which he proposes to adduce.

(2) The witnesses for the prosecution shall then be called and give their evidence.

81. Additional witness.—Where the prosecutor intends to adduce evidence which is not contained in any record or abstract of evidence given to the accused, notice of such intention together with the particulars of the evidence shall, when practicable, be given to the accused at a reasonable time before the evidence is adduced. If such evidence is adduced without such notice or particulars having been given, the Court may, if the accused so desires either adjourn after receiving the evidence of allow any cross-examination arising out of that evidence to be postponed, and the Court shall inform the accused of his right to apply for such an adjournment or postponement.

82. Dropping witnesses.—The prosecutor shall not be bound to call all the witnesses against the accused whose evidence is contained in the record or abstract of evidence, nor a witness when he has notified the accused that he intends to call under rule 81, but if the prosecutor does not intend to call such witness to give evidence, he shall give the accused reasonable notice that he does not intend to call the witness and that the accused will be allowed to communicate with him and to call him as a witness for the defence, if he so desires and if the witness is available.

83. Withdrawal of witnesses.—During a trial, a witness other than the prosecutor or accused shall not, except by leave of the Court, be in Court while not under examination, and if while he is under examination, a discussion arises as to whether a question is to be allowed or not with regard to his evidence the Court may direct the witness to withdraw during such discussion.

84. Examination of witnesses.—(1) A witness may be examined by the person calling him and may be cross-examined by the opposite party to the proceedings and on the conclusion of any such cross-examination may be re-examined by the person who

called him on matters arising out of the cross-examination.

(2) (a) The person examining a witness shall put his questions to the witness orally and unless an objection is made by the witness, the Court, the Judge Attorney, the prosecutor or by the accused, the witness shall reply forthwith.

(b) Where such an objection is made, the witness shall not reply until the objection has been disposed of.

(3) The Court may allow the cross-examination or re-examination of a witness to be postponed.

(4) Before the examination of a witness, he shall be administered an oath or affirmation in the following form or in such other form to the same purport as the Court ascertains to be in accordance with his religion or otherwise binding on his conscience.

FORM OF OATH

I,.....swear by Almighty God that whatever I shall state, shall, be the truth, the whole truth and nothing but the truth.

FORM OF AFFIRMATION

I,.....do solemnly, truly and sincerely declare and affirm that whatever I shall state, shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth.

85. Questioning by the Court.—(1) The presiding officer, the Judge Attorney and any member of the Court may put questions to a witness.

(2) Upon any such question being answered, the prosecutor and the accused may put to the witness such questions arising from the answer which he has given as seem proper to the Court.

86. Reading over of evidence.—(1) (a) The record which has been made of the evidence given by a witness shall be read back to him before he leaves the Court and when this is done he may ask for the record to be corrected or explain the evidence which he has given.

(b) Where any such correction is made or explanation given, the prosecutor and the accused may put such questions to the witness respecting the correction or explanation as seem proper to the Court.

(2) When a shorthand writer is employed it shall not be necessary to comply with sub-rule (1), if, in the opinion of the Court and the Judge Attorney (if any) it is unnecessary to do so ;

Provided that if any witness so demands, sub-rule (1) shall be complied with.

87. Calling or recalling witnesses by the Court.—(1)(a) The Court may at any time before it closes to deliberate on its finding or if there is a Judge Attorney before he begins to sum up, call a witness or

recall a witness, if in the opinion of the Court it is in the interest of justice to do so.

(b) Where the Court calls a witness or recalls a witness under this rule, the prosecutor and the accused may put such questions to the witness as seem proper to the Court.

(2) The prosecutor and the accused may, at any time before the Court closes to deliberate on its finding or if there is a Judge Attorney before he begins to sum up, recall a witness by leave of the Court and the prosecutor and the accused may put such questions to the witness as seem proper to the Court.

88. Submission of no case to answer and stopping of cases.—(1) (a) At the close of the case for the prosecution the accused may submit to the Court in respect of any charge that the prosecution has failed to establish a prima facie case for him to answer and that he should not be called upon to make his defence to that charge.

(b) Where the accused makes such submission the prosecutor may address the Court in answer thereto and the accused may reply to the prosecutor's address.

(2) The Court shall not allow the submission unless it is satisfied that—

(a) the prosecution has not established— a prima facie case on the charge as laid; and

(b) it is not open to it on the evidence to make a special finding under either section 90 or sub-rule (4) of rule 95.

(3) (a) Where the Court allows the submission, it, shall find the accused not guilty of the charge to which it relates and subject to confirmation the finding shall forthwith be announced in open Court.

(b) Where the Court disallows the submission it shall proceed with the trial of the offence as charged.

(4) the Court may, of its own motion, after the close of the hearing of the case for the prosecution, and after hearing the prosecutor find the accused not guilty of the charge and subject to confirmation the finding shall forthwith be announced in open Court.

89. Case for the defence.—(1) After the close of the case for the prosecution, the presiding officer or the Judge Attorney (if any) shall explain to the accused that :—

(a) if he wishes, he may give evidence on oath as a witness or make a statement without being sworn but that he is not obliged to do either.

(b) if he gives evidence on oath, he shall be liable to be cross-examined by the prosecutor and to be questioned by the Court.

(2) For the purpose of enabling the accused to explain any circumstances appearing in the evidence against him, the Court may, at any stage of the trial, without previously warning the accused, put such questions to him as the Court considers necessary, and shall for the purpose aforesaid, question him generally on the case after the witnesses for the prosecution have been examined and before he is called on for his defence.

(3) The accused shall not render himself liable to punishment by refusing to answer such questions, or by giving false answers to them.

(4) The answers given by the accused may be taken into consideration in such trial and put in evidence, for or against him in any other inquiry into or trial for, any other offence which such answers may tend to show he has committed.

(5) If the accused intends to call a witness to the facts of the case other than himself, he may make an opening address outlining the case for the defence before the evidence for the defence is given.

90. Witnesses for defence.—(1) After rule 89 has been complied with, the witnesses for the defence (if any) shall be called to give their evidence.

(2) The provisions of rules 84, 85 and 86 shall apply to the witnesses for the defence as they apply to the evidence of witnesses for the prosecution.

91. Witnesses in reply.—After the witnesses for the defence have given their evidence, the prosecutor may by leave of the Court, call a witness or recall a witness to give evidence on any matter raised by the accused in his defence which the prosecution could not properly have mentioned to the Court before the accused disclosed his defence or which the prosecution could not reasonably have foreseen.

92. Closing address.—(1) After all the evidence has been given the prosecutor and the accused may each make a closing address to the Court.

(2) The accused shall be entitled to make his closing address after the closing address by the prosecutor unless the accused has called a witness to facts other than himself, in which case the prosecutor shall be entitled, subject to sub-rules (3) and (4) to make his closing address after the accused has made the closing address.

(3) Where two or more accused are tried jointly, any one of them who has called no such witness shall be entitled to make his closing address after the prosecutor has made the closing address.

(4) (a) where two or more accused are represented by the same defending officer or counsel he may make one closing address only.

(b) Where any one of the accused for whom he appears has called no witness to facts other than himself such defending officer or counsel shall be entitled to make his closing address after the prosecutor has made the closing address.

93. Summing up by Judge Attorney.—After the closing addresses, if there is a Judge Attorney, he shall sum up the evidence and advise the Court on the law relating to the case in open Court.

94. Deliberation on finding.—(1) The Court shall deliberate on its finding in closed Court in the presence of the Judge Attorney.

(2) The opinion of each member of the Court as to the finding shall be given by word of mouth on each charge separately starting with the junior most in rank.

95. Record and announcement of finding.—(1) The finding on every charge upon which the accused is arraigned shall be recorded and except as provided in these rules, shall be recorded simply as a finding of "Guilty" or of "Not Guilty".

(2) Where the Court is of opinion as regards any charge that the facts proved do not disclose the offence charged or any offence of which he might under the Act legally be found guilty on the charge as laid, the Court shall acquit the accused of that charge.

(3) If the Court has doubts as regards any charge whether the facts proved, show the accused to be guilty on the charge as laid, it may, before recording a finding on that charge, refer to the confirming authority for an opinion, setting out the facts which it finds to be proved and may if necessary, adjourn for that purpose.

(4) Where the Court is of opinion as regards any charge that the facts which it finds to be proved in evidence differ materially from the facts alleged in the statement of particulars in the charge but are nevertheless sufficient to prove the offence stated in the charge, and that the difference is not so material as to have prejudiced the accused in his defence, it may, instead of a finding of "Not Guilty" record a special finding.

(5) The special finding may find the accused guilty on a charge subject to the statement of exceptions or variations specified therein.

(6) Where there are alternative charges, and the facts proved appear to the Court not to constitute the offence mentioned in any of those alternative charges, the Court shall record a finding of "Not Guilty" on that charge.

(7) The Court shall not find the accused guilty on more than one of two or more charges laid in the alternative, even if conviction upon one charge necessarily connotes guilty upon the alternative charge or charges.

(8) If the Court thinks that the facts proved constitute one of the offences stated in two or more of the alternative charges, but doubts which of those offences the facts do at law constitute, it may, before recording a finding on those charges, refer to the confirming authority for an opinion, setting out the

facts which it finds to be proved and stating that it doubts whether those facts constitute in law the offence stated in such one or other of the charges and may, if necessary, adjourn for that purpose.

(9) The finding on each charge shall be announced forthwith in open Court as subject to confirmation.

96. Procedure on acquittal.—If the finding on all the charges is "Not Guilty" the presiding officer shall affix his signature and date on the finding and such signature shall authenticate the whole of the proceedings, and the proceedings upon being signed by the Judge Attorney (if any) shall be at once transmitted for confirmation.

97. Procedure on conviction.—(1) If the finding on any charge is "Guilty", then, for the guidance of the Court in determining its sentence, and of the confirming authority in considering the sentence, the Court, before deliberating on the sentence, shall, whenever possible, take evidence of and record the general character, age, service, rank, any recognised acts of gallantry or distinguished conduct of the accused, any previous convictions of the accused either by Security Guard Court or a Criminal Court, any previous punishment awarded to him by an Officer exercising authority under sections 51, 53 or 54, as the case may be, the length of time he has been in arrest or in confinement on any previous sentence, and any decoration, or reward, of which he may be in possession or to which he is entitled.

(2) Evidence of the above matter may be given by a witness verifying a statement which contains a summary of the entries in the service books respecting the accused and identifying the accused as the person referred to in that summary.

(3) The accused may cross-examine any such witness and may call witnesses to rebut such evidence; and if the accused so requests, the service books or a duly certified copy of the material entries therein, shall be produced and if the accused alleges that the summary is in any respect not in accordance with the service books or such certified copy, as the case may be, the Court shall compare the summary with those books or copy and if it finds that it is not in accordance therewith, shall cause summary to be corrected or the objection of the accused to be recorded.

(4) When all the evidence on the above matter has been given, the accused may address the Court thereon and in mitigation of punishment.

98. Sentence.—The Court shall award a single sentence in respect of all the offences of which the accused is found guilty, and such sentence shall be deemed to be awarded in respect of which it can be legally given and not to be awarded in respect of which it cannot be legally given.

99. Recommendation for mercy.—(1) Where the Court makes a recommendation to mercy it shall give its reasons for such recommendation.

(2) The number of the members of the Court making recommendation to mercy mentioned in this rule, or any question relating thereto, may be entered in the proceedings.

100. Announcement of sentence and signing and transmission of proceedings.—(1) The sentence together with any recommendation to mercy and the reasons for any such recommendation shall be announced forthwith in open Court. The sentence will be announced as subject to confirmation.

(2) Upon the Court awarding the sentence, the presiding officer shall affix his signature and date to the sentence and such signatures shall authenticate the whole of the proceedings and the proceedings upon being signed by the Judge Attorney (if any), shall at once be transmitted for confirmation.

101. Revision.—(1) (a) Where the finding is sent back for revision under section 109, the Court shall re-assemble in open Court, the revision order shall be read and if the Court, is directed to take fresh evidence such evidence shall be taken in open Court.

(b) Where such fresh evidence is recorded otherwise than at the instance of the accused, the accused shall be given a further opportunity to lead evidence in respect of matters brought out in such fresh evidence.

(c) The prosecutor and the accused shall be given a further opportunity to address the Court in respect of the fresh evidence led.

(d) The Judge Attorney may also give a further summing up.

(2) Where the revision of finding does not involve taking of fresh evidence the accused shall be given an opportunity to address the Court in respect of matter raised in the revision order.

(3) (a) The Court shall then deliberate on its finding in closed Court and if the Court does not adhere to its former finding, it shall revoke the finding and sentence and record a new finding and if such new finding involves a sentence, pass the sentence, afresh.

(b) Where the original finding was one of "Not Guilty", the Court shall, before passing sentence comply with rules 97 and 98.

(4) (a) Where the sentence alone is sent back for revision, the revision order shall be read in open Court and the accused given an opportunity to address the Court in regard to matters referred to in the revision order.

(b) The Court shall then reconsider its sentence in closed Court and if it does not adhere to the sentence, revoke the sentence and pass the sentence afresh.

(5) Where the sentence alone is sent for revision the Court shall not revise the finding.

102. Confirmation and Promulgation :—(1) When a confirming authority receives the record of the proceedings of a Court, it shall record its decision thereon and on any sentence and any order which the Court may have made under section 102 on the record of the proceedings in the appropriate form set out in

Appendix VII and such record of his decision shall form part of the record of the proceedings.

(2) When a Court has accepted a plea of guilty made under rule 75 the confirming authority may confirm its finding notwithstanding that the Court has accepted the plea without the concurrence of the convening officer, if, in the opinion of the confirming authority it is in the interests of justice to do so.

(3) (a) When a Court has rejected a plea to the jurisdiction of the Court or a plea in bar of trial or has overruled an objection to a charge; it shall not be necessary for the confirming authority to approve specifically the decision of the Court, but its approval shall be implied from its confirming the finding on the charge to which the plea or objection relates.

(b) Where it disapproves the decision of the Court to reject the plea or to over-rule the objection it shall withhold confirmation of the finding on the charge to which the plea or objection relates.

(4) A confirming authority may state its reasons for withholding confirmation in any case, but if it withholds confirmation where a Court has rejected a plea to the jurisdiction or plea in bar of trial or has overruled an objection to the charges because it disapproves this decision of the Court, it shall when recording its decision under sub-rule (1) state that it has withheld confirmation for this reason.

(5) Where the sentence of a Court is improperly expressed, the confirming authority may in confirming the sentence vary the form thereof so that it shall be properly expressed.

(6) Whenever it appears that there is sufficient evidence on a plea of guilty under either sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 75 to justify the finding of the Court, such finding and any lawful sentence consequent thereon may be confirmed, and if confirmed, shall be valid, notwithstanding any deviation from these rules, if the accused has not been prejudiced by such deviation.

(7) While confirming the finding, the confirming authority may either unconditionally or subject to conditions which the accused accepts, reduce or remit a portion of the sentence or commute the punishment to one given lower in the scale of punishments in section 47.

(8) (a) When a confirming authority has confirmed a finding and a sentence of a Court or has withheld confirmation thereof, it shall send the record of the proceedings to the Commander of the accused for promulgation to the accused of the finding and sentence or the fact that confirmation has been withheld as the case may be.

(b) The fact of promulgation shall be recorded on the record of the proceedings in the form set out in Appendix VIII.

(c) Where confirmation has been withheld because the confirming authority disapproves the Court's decision to reject a plea to the jurisdiction of a plea in bar of trial or to over-rule an objection to the charge, the accused shall be so informed.

CHAPTER X

PROCEDURE OF SECURITY GUARD COURTS
AND INCIDENTAL MATTERS

103. Seating of members :—The members of a Court shall take their seats according to their rank.

104. Responsibility of Presiding Officer :—(1) The presiding officer is responsible for the trial being conducted in proper order, and in accordance with the Act, rules made thereunder and in a manner befitting a court of justice.

(2) It is the duty of the presiding officer to see that the accused has a fair trial, and that he does not suffer any disadvantage in consequence of his position as person under trial, or of his ignorance, or of his incapacity to examine or cross-examine witnesses, or otherwise.

105. Power of Court over address of prosecutor and accused :—(1) It is the duty of the prosecutor to assist the Court in the administration of justice, to behave impartially, to bring to the whole of the transaction before the Court and not to take any unfair advantage of, or suppress any evidence in favour of the accused.

(2) The prosecutor may not refer to any matter not relevant to the charge or charges, then before the Court, and it is the duty of the Court to stop him from so doing and also to restrain any undue violence of language or want of fairness or moderation on the part of the prosecutor.

(3) The Court shall give reasonable facilities to the accused in making his defence, the accused must abstain from any remarks contemptuous or disrespectful towards the Court, and from coarse and insulting language towards others, but he may for the purpose of his defence impeach the evidence and charge other persons with blame and even criminality, subject to, if he does so, any liability which he may thereby incur. The Court may caution the accused as to the irrelevance of his defence, but shall not, unless in special cases, stop his defence solely on ground of such irrelevance.

106. Sitting in closed Court :—(1) A Court shall, where it is so directed by these rules and may in other case on any deliberation amongst the members, sit in closed Court.

(2) No person shall be present in closed Court except the members of the Court, the Judge Attorney (if any) and any officer under instruction.

(3) For the purpose of giving effect to the foregoing provisions of this rule, a Court may either retire or cause the place where it sits to be cleared of all other persons not entitled to be present.

(4) Except as mentioned in sub-rules (1), (2) and (3) of this rule all proceedings, including the view of any place, shall be in open Court and in the presence of the accused subject to sub-rule (5).

(5) The Court shall have the power to exclude from the Court any witness who has yet to give evidence or any other person, other than the accused, who interferes with its proceedings.

107. Continuity of trial and adjournment of Court :—(1) When the Court is once assembled and the accused has been arraigned, the Court shall continue the trial from day to day in accordance with these rules unless it appears to the Court that an adjournment is necessary for the ends of justice or that such continuance is impracticable.

(2) (a) A Court may from time to time adjourn its proceedings and meet at such a place as may be convenient, and

(b) Wherever necessary, visit the scene of occurrence.

(3) The senior officer on the spot may also for exigencies of service adjourn or prolong the adjournment of the Court.

(4) A Court in the absence of a Judge Attorney (if one has been appointed for that Court) shall not proceed, and shall adjourn.

(5) If the time to which an adjournment is made is not specified, the adjournment shall be until further orders from the proper Security Guard Authority; and, if the place to which an adjournment is made is not specified, the adjournment shall be to the same place or to such other place as may be specified in further orders from the proper Security Guard authority.

108. Suspension of trial :—(1) where in consequence of anything arising while the Court is sitting, the Court is unable by reason of dissolution as specified in section 68 or otherwise, to continue the trial, the presiding officer or, in his absence the senior member present, shall immediately report the facts to the convening authority.

109. Proceedings on death or illness of accused :—In case of the death of the accused or of such illness of the accused as renders it impossible to continue the trial, the Court shall ascertain the fact of the death or illness by evidence and record the same and adjourn and transmit the proceedings to the convening authority.

110. Death, retirement or absence of presiding officer :—In the case of the death, retirement on challenge or unavoidable absence of the presiding officer, the next senior officer shall take the place of the presiding officer and the trial shall proceed if the Court is still composed of not less than the minimum number of officers of which it is required by law to consist.

111. Presence throughout of all members of Court :—(1) A member of a Court who has been absent while any part of the evidence on the trial of an accused person is taken, shall take no further part in the trial by that Court of that person, but the Court will not be affected unless it is reduced below the legal minimum.

(2) An officer shall not be added to a Court after the accused has been arraigned.

112. Taking of opinions of members of Court :—(1) Every member of a Court must give his opinion by word of mouth on every question which the Court has to decide, and must give his opinion as to the sentence notwithstanding that he has given his opinion in favour of acquittal.

(2) The opinions of the members of the Court shall be taken in succession, beginning with the member lowest in rank.

113. Procedure on incidental questions :—If any objection is raised on any matter of law, evidence, or procedure, by the prosecutor or by or on behalf of the accused during the trial, the prosecutor or the accused or counsel or the defending officer (as the case may be) shall have a right to answer the same and the person raising the objection shall have a right to reply.

114. Evidence when to be translated :—When any evidence is given in a language, which any of the officers composing the Court, the accused or the Judge Attorney does not understand, it shall be translated into a language which he understands.

115. Record in Proceedings of transactions of a Security Guard Court :—(1) At a Court, the Judge Attorney or, if there is none, the presiding officer shall record or cause to be recorded all transactions of the Court, and shall be responsible for the accuracy of the record (in these rules referred to as the proceedings); and if the Judge Attorney is called as a witness by the accused, the presiding officer shall be responsible for the accuracy of the record in the proceedings, of the evidence of the Judge Attorney.

(2) The evidence shall be taken down in a narrative form in as nearly as possible the words used, but in any case where the prosecutor, the accused, the Judge Attorney or the Court considers it material, the question and answer shall be taken down verbatim.

(3) Where an objection has been taken to any question or to the admission of any evidence or to the procedure of the Court, such objection shall if the prosecutor or accused so requests or the Court thinks fit, be entered upon the proceedings together with the grounds of the objection and the decision of the Court thereon.

(4) Where any address by, or on behalf of the prosecutor or the accused, is not in writing, it shall not be necessary to record the same in the proceedings further or otherwise than the Court thinks proper, except that;

(a) the Court shall in every case make such record of the defence, made by the accused as will enable the confirming officer to judge of the reply made by, or on behalf of, the accused to each charge against him, and

(b) the Court shall also record any particular matters in the address by or on behalf of, the prosecutor or the accused, as the case may be, may require.

(5) The Court shall not enter in the proceedings any comment or anything not before the Court, or any report of any fact not forming part of the trial, but if any such comment or report seems to the Court necessary, the Court may forward it to the proper authority in a separate document, signed by the presiding officer.

116. Custody and inspection of proceedings.—The proceedings shall be deemed to be in the custody of the Judge Attorney (if any), or, if there is none, of the presiding officer but may, with proper precaution for their safety, be inspected by the members of the Court, the prosecutor and accused, at all reasonable times before the Court is closed to consider the findings.

117. Review of General/Petty Security Guard Court proceedings.—The proceedings of a General and Petty Security Guard Court shall be sent by the person having the custody thereof the Judge Attorney-General for review, who shall then forward the same to the confirming authority.

118. Defending Officer, friend of accused and counsel.—(1) At any General or Petty Security Guard Court an accused person may be represented by a counsel or by any officer subject to the Act who shall be called "the defending officer" or assisted by any person whose services he may be able to procure and who shall be called "the friend of the accused".

(2) The defending officer shall have the same rights and duties as appertain to a counsel under these rules and shall be under the like obligations.

(3) The friend of the accused may advise the accused on all points and suggest the question to be put to the witnesses, but he shall not examine or cross-examine the witnesses, address the Court.

119. Requirement for appearance of counsel.—An accused person intending to be represented by a counsel shall give to his Commander or to the convening officer the earliest practicable notice of such intention, and, if no sufficient notice has been given the Court may, if it thinks fit, on the application of the prosecutor, adjourn to enable him to obtain a counsel on behalf of the prosecutor at the trial.

(2) Where the convening officer so directs, counsel may appear along with the prosecutor, but in that case, unless the notice referred to in sub-rule (1) has been given by the accused, notice of the direction for counsel to appear shall be given to the accused at such time (not in any case less than seven days) before the trial as would, in the opinion of the Court have enabled the accused to obtain counsel to assist him at the trial.

(3) The counsel, who appears before a Court on behalf of the prosecutor or accused, shall have the same rights as the prosecutor or accused for whom he appears to call, and orally examine, cross-examine, and re-examine witnesses, to put in any plea, and to inspect the proceedings and shall have the right otherwise to act in the course of the trial in place of the person on whose behalf he appears, and he shall comply with these rules as if he were that person and in such a case that person shall have no right himself to do any of the aforesaid matters except as regards the statement allowed by sub-rule (2) of rule 90 and sub-rule (4) of rule 97 or except so far as the Court permits him so to do.

(4) When counsel appears on behalf of the prosecutor, the prosecutor if called as witness, may be examined as any other witness.

120. Disqualification of Judge Attorney.—An officer who is disqualified for sitting on a Court, shall be disqualified for acting as a Judge Attorney at that Court.

121. Substitution on death, illness or absence of Judge Attorney.—If the Judge Attorney dies, or from illness or from any cause whatever is unable to attend, the Court shall adjourn, and the presiding officer shall report the circumstances to the Convening Officer; and a fit person may be appointed by that officer who shall be sworn or affirmed, and act as Judge Attorney for the residue of the trial, or until the Judge Attorney returns.

122. Power and duties of Judge Attorney.—Where a Judge Attorney has been named to act on the Court, he shall,—

- (a) give his opinion on any question of law relating to the charge or trial whenever so required by the Court, prosecutor or the accused;
- (b) inform the Court of any irregularity or other infirmity in the proceedings ;
- (c) inform the convening officer and the Court of any infirmity or defect in the charge or in the constitution of the Court ;
- (d) sum up the evidence and give his opinion on any question of law, before the Court proceeds to deliberate upon its findings.

(2) It shall be the duty of the Judge Attorney to ensure that the accused does not suffer any disadvantage in consequence of his position as such, or because of ignorance or incapacity to examine or cross-examine witnesses and for this purpose the Judge Attorney may, with the permission of the Court, call witness and put questions to them which appear to him to be necessary or desirable.

(3) In the discharge of his duties, the Judge Attorney shall maintain an attitude of strict impartiality.

(4) Where any opinion has been given by the Judge Attorney to the Court on any matter before it, it may be entered in the proceedings, if the Judge Attorney or the Court desires it to be entered.

(5) The Judge Attorney shall represent the Judge Attorney-General at a Security Guard Court.

123. Finding of insanity.—Where the Court finds either that the accused, by reason of unsoundness of mind, is incapable of making his defence, or that he committed the act alleged but was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing the nature of the act or that it was wrong or contrary to law, the presiding officer or in the case of Summary Security Guard Court, the officer holding the trial, shall affix his signature and the date on the finding which shall also be signed by the Judge Attorney and thereupon the proceedings shall, at once, be transmitted to the confirming authority or in the case of Summary Security Guard Court to the Deputy Inspector-General empowered to countersign them.

124. Preservation of proceedings.—The proceedings of every Court shall, after promulgation, be forwarded to the office of the Judge Attorney-General and be preserved there for not less than three years, or until the sentence awarded by the Court has expired whichever is later.

125. Right of person tried to copies of proceedings.—Every person tried by a Security Guard Court shall be entitled to obtain on demand, at any time after the confirmation of the finding and sentence, when such confirmation is required and before the proceedings are destroyed, from the Judge Attorney-General a copy thereof, including the proceedings upon revision, if any.

126. Copy of proceedings not to be given in certain cases.—Notwithstanding anything contained in rule 125, if the Central Government is satisfied for reasons to be recorded that it is against the interests of the Security of the State or friendly relations with foreign states to supply a copy of the proceedings or any part thereof under the said rule, he shall not be furnished with such a copy :

Provided that if the Central Government is satisfied that the person demanding the copy is desirous of submitting a petition in accordance with the Act or instituting any action in a court of law in relation to the finding or sentence, it shall permit inspection of the proceedings by such a person, or his legal advisor, if any, on the following conditions, namely :—

- (a) the inspection shall be made at such times and such places as the Central Government or any authority authorised by it may direct; and
- (b) the person allowed to inspect the proceedings shall, before such inspection, furnish,—
 - (i) an undertaking, in writing, that he shall not make copies of the proceedings or any part thereof and that the information or documents contained in such proceedings shall not be used by him, for any purpose whatsoever, other than for the purpose of submitting a petition in accordance with the Act or instituting an action in a court of law in relation to the said finding or sentence ; and
 - (ii) a certificate that he is aware that he may render himself liable to prosecution under sections 3 and 5 of the Indian Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) if he commits any act specified in the said sections in relation to the documents or information contained in the said proceedings.

127. Loss of proceedings.—(1) If, before confirmation, the original proceedings of a Court which require confirmation or any part thereof, are lost, a copy thereof, if any, certified by the presiding officer or the Judge Attorney at the Court may be accepted in lieu of the original.

(2) If there is no such copy, and sufficient evidence of the charge, finding, sentence, and transactions of the Court can be procured, that evidence may, with the assent of the accused, be accepted in lieu of the original proceedings, or part which have been lost.

(3) In any case mentioned in sub-rules (1) and (2) of this rule the finding and sentence may be confirmed, and shall be valid as if the original proceedings or part thereof had not been lost.

(4) If the accused refuses the assent referred to in sub-rule (2), he may be tried again, and the finding and sentence of the previous Court of which the proceeding have been lost shall be void.

(5) If, after confirmation or in any case where confirmation is not required, the original proceedings or any part thereof are lost, and there is sufficient evidence of the charge, finding, sentence, and transactions of the Court and of the confirmation (if required) of the finding and sentence, that evidence shall be a valid and sufficient record of the trial for all purposes.

128. Offences by witnesses and others.—When a Court is of opinion that there is ground for inquiring into any offence specified in sections 36 and 37 and committed before it or brought to its notice in the course of its proceedings, which would if done by a person subject to the Act, have constituted such an offence, such Court may proceed as follows, that is to say :—

- (a) If the person who appears to have committed the offence is subject to the Act, the Court may bring his conduct to the notice of his commander.
- (b) if the person who appears to have done the act is amenable to a Law relating to any Armed Force, the Court may bring his conduct to the notice of the proper Force authority, as the case may be ;
- (c) in other cases the officer who summoned the witness to appear or the presiding officer or officer holding the Court, as the case may be, may forward a written complaint to the nearest Magistrate of the first class having jurisdiction, and in the case of acts which would, if done by a person subject to this Act have constituted an offence under clause (e) of section 36 or section 37, the Court, after making any preliminary inquiry that may be necessary may send the case to the nearest Magistrate of the first class having jurisdiction for inquiry or trial in accordance with section 340 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

CHAPTER XI

SUMMARY SECURITY GUARD COURTS

129. Proceedings.—(1) The officer holding the trial (hereinafter in this chapter called the Court) shall record, or cause to be recorded the transactions of every Summary Security Guard Court.

(2) The Court may appoint a shorthand writer to record the proceedings of the Court. Such shorthand writer shall be duly sworn or affirmed as per the form given in rule 65.

130. Evidence when to be translated.—(1) When any evidence is given in a language which the Court or the accused does not understand, that evidence shall be translated to the Court or accused as the case may be in a language which it or he does understand.

(2) The Court shall for this purpose either appoint an interpreter, or shall itself take the oath or affirmation prescribed for the interpreter at a Summary Security Guard Court.

(3) When documents are produced for the purpose of formal proof, it shall be in the discretion of the Court to cause as much to be interpreted as appears necessary.

131. Assembly.—When the Court, the interpreter (if any) and the officers and subordinate officers attending the trial are assembled, the accused shall be brought before the Court and the oath or affirmation prescribed in rule 132 shall be taken by the persons therein mentioned.

132. Swearing or affirming of court and interpreter.—The Court shall take oath or affirmation in any one of the following forms or in such other form to the same purport which would, according to the religion or otherwise be binding on the conscience of the officer constituting the Court.

FORM OF OATH

“I swear by Almighty God that I will duly administer justice, according to the National Security Guard Act, 1986 without partiality, favour or affection.”

FORM OF AFFIRMATION

“I do solemnly, sincerely and truly declare and affirm that I will duly administer justice, according to the provisions of National Security Guard Act, 1986 without partiality, favour or affection”.

- (2) The Court, or any other person empowered by it in this behalf shall administer to the interpreter (if any) an oath or affirmation in any of the following forms, or in such other form to the same purport as the Court ascertains to be according to the religion or otherwise binding on the conscience of the person who is to act as interpreter.

FORM OF OATH

“I swear by Almighty God that I will faithfully interpret and translate, as I shall be required to do touching the matter before this Court.”

FORM OF AFFIRMATION

"I..... do solemnly, sincerely and truly declare and affirm that I will faithfully interpret and translate, as I shall be required to do touching the matter before this Court."

- (3) The witnesses shall, after the administration of the oath and the affirmation, withdraw from the Court.

133. Swearing of Court to try several accused persons.—(1) A Summary Security Guard Court may be sworn or affirmed at the same time to try any number of accused persons then present before it whether those persons are to be tried collectively or separately.

(2) In the case of several accused persons to be tried separately, the Court, when sworn or affirmed shall proceed with one case postponing the other cases and taking them afterwards in succession.

(3) Where several accused persons are tried separately upon charges arising out of the transaction, the Court may, if it considers it to be desirable in the interests of justice, postpone consideration of any sentence to be awarded to any one or more such accused persons until the trials of all such accused persons have been completed.

134. Arraignment of accused.—(1) After the Court and interpreter (if any) are sworn or affirmed as above mentioned, the accused shall be arraigned on the charges against him.

(2) The charges on which the accused is arraigned shall be read and, if necessary, translated to him, and explained and he shall be required to plead separately to each charge.

135. Objection by accused to charge.—The accused, when required to plead to any charge, may object to the charge on the ground that it does not disclose an offence under the Act, or is not in accordance with these rules.

136. Amendment of charge.—(1) At any time during the trial if it appears to the Court that there is mistake in the name or description of the accused in the charge-sheet, it shall amend the charge sheet so as to correct that mistake.

(2) If on the trial of a charge it appears to the court at any time before it has begun to examine the witnesses, that in the interests of justice any addition to, omission from, or alteration in, the charge is required, it may amend such charge and may, after due notice to the accused, and with the sanction of the officer empowered to convene a Petty Security Guard Court for the trial of the accused if the amended charge requires such sanction, proceed with the trial on such amended charge.

137. Special pleas.—If a special plea to the general jurisdiction of the Court, or a plea in bar of trial is offered by the accused the procedure laid down in Chapter IX for disposing of such plea shall, so far as may be applicable be followed.

138. General plea of "Guilty" or "Not Guilty".—

(1) The accused person's plea of "Guilty" or "Not Guilty" (or if he refuses to plead or does not plead intelligibly either one or the other, a plea of "Not Guilty") shall be recorded on each charge.

(2) If an accused person pleads "Guilty", that plea shall be recorded as the finding of the Court; but before it is recorded, the Court shall ascertain that the accused understands the nature of the charge to which he has pleaded guilty and shall inform him of the general effect of that plea, and in particular of the meaning of the charge to which he has pleaded guilty, and of the difference in procedure which will be made by the plea of guilty and shall advise him to withdraw that plea if it appears from the record or abstract of evidence (if any) or otherwise that the accused ought to plead not guilty.

(3) Where an accused person pleads guilty to the first two or more charges laid in the alternative, the Court may after sub-rule (2) has been complied with and before the accused is arraigned on the alternative charge or charges, withdraw such alternative charge or charges as follow the charge to which the accused has pleaded guilty without requiring the accused to plead thereto, and a record to that effect shall be made in the proceedings of the Court.

139. Procedure after plea of "Guilty".—(1) Upon the record of the plea of "Guilty", if there are other charges in the same charge-sheet to which the plea is "Not Guilty", the trial shall first proceed with respect to those other charges, and, after the finding on those charges, shall proceed with the charges on which a plea of "Guilty" has been entered; but if there are alternative charges, the Court may either proceed with respect to all the charges as if the accused had not pleaded "Guilty" to any charge, or may, instead of trying him, record a finding of "Guilty" upon any one of the alternative charges to which he had pleaded "Guilty" and finding of "Not Guilty" upon all the other alternative charges which precede such charge.

(2) (a) After the record of the plea of "Guilty" on a charge (if the trial does not proceed on any other charges) the Court shall read the record or abstract of evidence and annex it to the proceedings, or if there is no such record, or abstract shall take and record sufficient evidence to enable it to determine the sentence, and the reviewing officer to know all the circumstances connected with the offence.

(b) The evidence shall be taken in like manner as is directed by these rules in the case of a plea of "Not Guilty".

(3) The accused may, after such evidence has been taken or as the case may be, the record or abstract of evidence has been read, address the Court with reference to the charge and in mitigation of punishment and may call witnesses as to his character.

(4) (a) If from the statement of the accused or from the record of evidence, or otherwise, it appears to the Court that the accused did not understand the effect of his plea of "Guilty", the Court shall alter the record and enter a plea of "Not Guilty", and proceed with the trial accordingly.

(b) Any alternative charges withdrawn under sub-rule (1) shall be reinstated in the charge sheet and the trial shall take place as if they had never been withdrawn.

(5) If a plea of "Guilty" is recorded on some charges and the trial proceeds with respect to other charges in the same charge-sheet, the proceedings under sub-rules (2) and (3) shall take place after the findings on the other charges in the same charge sheet are recorded.

(6) When the accused states anything in mitigation of punishment which in the opinion of the Court requires to be proved, and would, if proved, affect the amount of punishment, the Court may permit the accused to call witnesses to prove the same.

140. Withdrawal of plea of "Not Guilty".—The accused may, if he thinks fit at any time during the trial, withdraw his plea of "Not Guilty" and plead "Guilty" and in such case the Court shall at once, subject to compliance with sub-rule (2) of rule 138 record a plea and finding of "Guilty" and shall, so far as if necessary, proceed in manner directed by rule 139.

141. Procedure after plea of "Not Guilty".—(1) After the plea of "Not Guilty" to any charge, is recorded, the evidence for the prosecution will be taken.

(2) At the close of the evidence for the prosecution the accused shall be asked if he has anything to say in his defence, or may defer such address until he has called his witnesses.

(3) The accused may then call his witnesses, including also witnesses to character.

142. Witnesses in reply to defence. The Court may, if it thinks it necessary in the interests of Justice, call witnesses in reply to the defence.

143. Evidence of witnesses.—The provisions of rules 85, 86 and 87 shall so far as may be, apply to the evidence of witnesses at a Summary Security Guard Court, as they apply to the evidence of witnesses at a General or Petty Security Guard Court.

144. Record and announcement of finding.—(1) The Court shall after the evidence for prosecution and defence has been heard, record its findings.

(2) The finding on every charge upon which the accused is arraigned shall be recorded and except as mentioned in those rules shall be recorded simply as a finding of "Guilty" or of "Not Guilty".

(3) When the Court is of opinion as regards any charge that the facts proved do not disclose the offence charged or any offence of which he might

under the Act legally be found guilty on the charge as laid, the Court shall find the accused "Not Guilty" of that charge.

(4) When the Court is of opinion as regards any charge that the facts found to be proved in evidence differ materially from the facts alleged in the statement of particulars in the charge, but are nevertheless sufficient to prove the offence stated in the charge, and that the difference is not so material as to have prejudiced the accused in his defence, it may, instead of a finding of "Not Guilty" record a special finding.

(5) The special finding may find the accused guilty on a charge subject to the statement of exceptions or variations specified therein.

(6) The Court shall not find the accused guilty on more than one or two or more charges laid in the alternative, even if conviction upon one charge necessarily connotes guilt upon the alternative charge or charges.

145. Procedure on acquittal.—Where the finding on each of the charges in a charge-sheet is "Not Guilty", the Court shall affix its signature and date to the proceedings, the findings will be announced in open Court, and the accused will be released if under arrest, in respect of these charges.

146. Procedure on finding of "Guilty".—(1) Where the finding on any charge is "Guilty", the Court may record of its own knowledge, or take evidence of any record, the general character, age, service, rank, and any recognised acts of gallantry, or distinguished conduct of the accused, and previous convictions of the accused either by a Security Guard Court or a Criminal Court, any previous punishment awarded to him by an officer exercising authority under section 51, the length of time he has been in arrest or in confinement on any previous sentence, and any decoration, or reward, of which he may be in possession or to which he may be entitled.

(2) Where the Court does not record the matters mentioned in this rule of its own knowledge, evidence on these matters may be taken in the manner directed in rule 97 for similar evidence.

147. Sentence.—The Court shall award one sentence in respect of all the offences of which the accused is found guilty.

148. Signing of proceedings.—The Court shall affix its signature and the date to the sentence and such signature shall authenticate the whole of the proceedings.

149. Charges different charge sheets.—(1) When the charges at a trial by Summary Security Guard Court are contained in different charge sheets, the accused shall be tried on each charge sheet separately upto and including the stage of finding.

(2) The Court shall, thereafter, comply with rules 145 or 146 as the case may be.

150. Clearing the Court.—(1) The officer holding the trial may clear the Court to consider the evidence or to consult with the officers, and Assistant Commander attending the trial.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (1) all the proceedings including the view of any place, shall be in open Court, and in the presence of the accused.

151. Adjournment.—A Court may,—

- (a) from time to time adjourn its proceedings and meet at such place as may be convenient; and
- (b) wherever necessary visit the scene of occurrence.

152. Friend of the accused.—During a trial at a Summary Security Guard Court an accused may take the assistance of any person, including a legal practitioner as may consider necessary;

Provided that such person shall not examine or cross-examine witnesses or address the Court.

153. Memorandum to be attached to proceedings.—Where a Summary Security Guard Court tries an offence which shall not ordinarily be tried without reference to an authority mentioned in sub-section (2) of section 71, an explanatory memorandum shall be attached to the proceedings.

154. Promulgation.—The sentence of a Summary Security Guard Court shall be promulgated in the manner usual in the service, at the earliest opportunity after it has been pronounced and shall subject to the provisions of the Act as carried out without delay after promulgation.

155. Review of proceedings.—The proceedings of a Summary Security Guard Court shall, immediately on promulgation be forwarded through the Judge Attorney-General, or an officer nominated by him for the purpose to the Deputy Inspector-General under whom the accused may be serving.

156. Action by the Deputy Inspector-General.—(1) Where the Deputy Inspector-General to whom the proceedings of a Summary Security Guard Court have been forwarded under rule 155, is satisfied that injustice has been done to the accused by reason of any grave irregularity in the proceedings or otherwise, he may,—

- (a) set aside the proceedings of the Court ;

OR

- (b) reduce the sentence or commute the punishment awarded to one lower in the scale of punishment given in Section 17.

(2) Where no action under sub-rule (1) has been taken he shall countersign the proceedings and return it to the unit of the accused for promulgation.

(3) The proceedings shall, after its promulgation, be forwarded to the Judge Attorney-General for custody.

CHAPTER XII

EXECUTION OF SENTENCE

157. Direction about Sentence of imprisonment.—

(1) A confirming authority or in the case of a Summary Security Guard Court, the Court, shall direct that the sentence of imprisonment shall be undergone by confinement either in a civil prison or in Security Guard custody.

(2) Such direction may be varied by any superior officer.

158. Warrants.—Warrants for committing a person to a civil prison to undergo sentence of imprisonment or to get such person back into Security Guard Custody if so required or to order the release of such a person from civil prison or any variation done by any superior officer shall be in such form as may be appropriate to each case set out in Appendix IX.

(2) Such warrants shall be signed by the Commander of the accused or by a staff officer on behalf of a Deputy Inspector-General, Inspector-General or the Director-General.

159. Warrant in case of sentence of death.—(1) Where a person is sentenced to death by hanging, a warrant in the form set out in Appendix X shall be sent by the Director-General to the Superintendent of the Prison where facilities for carrying out such a sentence exist, after the sentence has been confirmed by the Central Government and the accused shall be committed to the same prison by his Commander on the appropriate warrant.

160. Changes in sentence.—Where any change is made in the sentence of a person already committed to a civil prison, such change shall be communicated to the Superintendent of the Prison to which such person has been committed by the Commander or such other person as is mentioned in rule 158 on the form set out in Appendix XI.

161. Sentence of dismissal.—(1) Sentence of dismissal shall take effect from the date of promulgation of such sentence or from any subsequent date as may be specified at the time of promulgation.

(2) A sentence of dismissal combined with imprisonment to be undergone in a civil prison shall not take effect until such person has been committed to a civil prison.

CHAPTER XIII

PETITIONS

162. Petitions against finding and sentence of Court.—(1) A person subject to the Act who has been tried by a Court shall be allowed to put in one petition before confirmation, to the confirming authority and one petition after confirmation to any officer mentioned in section 113.

(2) In the case of a Summary Security Guard Court he shall be allowed to put in one petition only to any of the officers mentioned in section 113.

163. Period of Limitation.—(1) A petition, before confirmation, shall be submitted, within two weeks of the conclusion of trial.

(2) A petition after confirmation shall be submitted within 3 months of the date on which the sentence was promulgated:

Provided that the time taken by such person to obtain a copy of the proceedings shall be excluded in computing this period of 3 months.

164. Mode of submitting petitions.—(1) (a) A petition by a person who is still a member of the Security Guard shall be submitted through his Commander,

(b) A petition by a person who has ceased to be a member of the Security Guard may be submitted to the Commander of the Unit in which the trial was held.

(2) An officer to whom a petition is submitted or to whom a petition has been forwarded shall forward it to the next superior within a period of one week:

Provided that an officer may not forward a petition if he is competent to give the redress asked for and decides to do so.

(3) An officer receiving a petition shall send it to the Judge Attorney-General or to the officer approved by him for advice.

CHAPTER XIV COURTS OF INQUIRY

165. Composition.—(1) A Court of Inquiry may consist of one or more members. If only one member is appointed he shall be an officer. If more than one members are appointed, at least one of them should be an officer. Persons not subject to the Act, may also be appointed as additional members when the Court is to investigate matters of such a specialised nature as may require the assistance of specialised persons for proper investigation.

(2) The member or members of a Court of Inquiry ordered to be held into the conduct of an officer shall not be of a lower rank than the rank of such an officer. In case it is not possible to appoint all the members of the same or the higher rank, at least the presiding officer of such a Court of Inquiry shall be of a higher rank than the officer whose conduct is under inquiry.

166. Assembly.—A Court of Inquiry may be assembled by order of a Commander not below the rank of Group Commander or any officer or authority superior to him.

167. Assembly order.—The order assembling the Court of Inquiry shall state the composition of the Court, the time and place for its assembly and clearly state the matters which the Court will investigate. It will also provide for the administrative requirements of the Court.

168. Procedure of Courts of Inquiry.—(1) The proceedings of a Court of Inquiry shall not be open to the public. Only such persons may attend the proceedings as are permitted by the Court to do so.

(2) The evidence of all witnesses shall be taken on oath or affirmation and signed by them after the same has been read over and explained to them.

(3) Evidence given by witnesses shall be recorded in narrative form unless the Court considers that any questions and answers may be recorded as such.

(4) The Court may take in to consideration any documents even though they are not formally proved.

(5) The Court may ask witnesses any questions, in any form, that they consider necessary to elicit the truth and may take into consideration any evidence, whether the same is admissible under the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) or not.

(6) No counsel, or legal practitioner shall be permitted to appear before a Court of Inquiry.

(7) Provisions of section 86 shall apply for procuring the attendance of witnesses before the Court of inquiry. Witnesses shall be summoned as per specimen given in Appendix XV.

(8) (i) Where the subject matter of inquiry is the conduct or character of a particular person, such person may be associated throughout with the inquiry and be given full opportunity of making any statement, or giving any evidence, he may wish to make or give, and of cross-examining any witness whose evidence, in his opinion, affects his character or reputation.

(ii) In other cases, before giving opinion against any person subject to the Act, the Court shall afford that person an opportunity to know all that has been

stated against him, cross-examine any witnesses who have given evidence against him, and make a statement and call witnesses in his defence.

(9) The answers given by a witness to any question asked before the Court shall not be admissible against such a witness on any charge at any subsequent occasion except a charge of giving false evidence before such court.

(10) Where the proceedings of an inquiry are submitted to a higher authority for orders under Rule 170 such authority before disagreeing with the opinion of the Court, shall record reasons for doing so. In such a case, provisions of clause (ii) of sub-rule (8) may not be complied with.

(11) The Court may be reassembled as often as the officer who assembled the Court may direct, for the purpose of examining additional witnesses, or further examining any witness, or recording further information. In such a case the Court may record fresh opinion if considered necessary after complying with the provisions of clause (ii) of sub-rule (8).

169. Courts of Inquiry when to be held.—(1) A Court of Inquiry may be held to investigate into any disciplinary matter or any other matter of importance.

(2) In addition to a Court of Inquiry required to be held under section 60, a Court of Inquiry shall be held in the following cases :—

(a) (i) All unnatural deaths of persons subject to the Act or of other persons within the Security Guard lines, an immediate report shall be sent through the messenger to the Officer-in-charge of the Police Station within whose jurisdiction the place of such unnatural death is.

(ii) In cases when such report cannot, for any reasons, be delivered within a reasonable time, the Commander or the senior most officer of the unit present shall prepare a report on the proforma set out in Appendix XII.

(b) All injuries sustained by persons subject to the Act which are likely to cause full or partial disability. The Court shall in such case determine whether such injuries were attributable to service or not.

(c) All financial irregularities, losses, theft and misappropriation of public or Security Guard property, where it is necessary to obtain the order of a superior officer on such irregularities, loss, theft or misappropriation.

(d) All losses of secret documents and any other material of secret or above security classification. Such a court of inquiry shall be ordered by an officer or authority superior to the Unit Commander having the lost document or material on its charge.

(e) All damages to private persons or property in respect of which there is likely to be a claim against the Government or the Security Guard.

170. Action on the proceedings of a Court of Inquiry.—The proceedings of a Court of Inquiry shall be submitted by the presiding officer to the officer or authority who ordered the Court. Such officer or authority on receiving the proceedings may pass final orders thereon himself, if he is empowered to do so, or refer them to a superior authority.

171. Copies of Court of Inquiry Proceedings.—A person subject to the Act against whom the Court of Inquiry has given an opinion or who is being tried by a Security Guard Court on a charge relating to matters investigated by the Court of Inquiry, shall be entitled to copies of the proceedings of the Court of Inquiry unless the Director-General orders otherwise.

CHAPTER XV

MISCELLANEOUS

172. Prescribed Officer under section 10 (2).—Officer not below the rank of Group Commander may, under sub-section (2) of section 10, dismiss or remove from the service any person under his command other than an officer or an Assistant Commander.

173. Authority prescribed for the purpose of section 12(1).—The authority for the purpose of sub-section (1) of section 12 shall be :—

(i) Director-General in respect of all personnel subject to the Act other than officers.

(ii) Central Government in respect of officers.

174. Prescribed manner of administering oath or affirmation under sub-section (1) of section 60.—The Court shall administer an oath or affirmation to the witnesses as if the Court were a Security Guard Court.

175. Prescribed manner of custody and prescribed officers under section 96 or 97.—(1) The prescribed officer for the purpose of Section 97 shall be—

(a) in the case of trial by Summary Security Court, the Commander of the Unit to which the accused person belongs, or any authority superior to such Commander.

(b) in the case of trial by any other Court, the convening officer or any authority superior to him.

(2) When the officer who proposes to act as a prescribed officer under sub-rule (1) is under the command of the officer who has taken action in the case under sub-section (4) of Section 96, he shall ordinarily obtain the approval of such officer before he acts but if he is of opinion that service exigencies, or the necessities of discipline, render it impossible or inexpedient to obtain such approval, he may act without obtaining such approval, but shall report his action and the reasons therefor to such officer.

(3) For the purposes of sub-section (4) of section 96 the manner in which an accused person shall be kept in custody shall be as follows :—

The accused shall be confined in such manner as may, in the opinion of the proper Security Guard authority, be best calculated to keep him securely without unnecessary harshness, as he is not to be considered as a criminal but as a person labouring under a disease.

176. Authorised deduction.—The following deductions may be made from the pay and all other emoluments payable to a person subject to the Act, namely :—

(a) upon the general or special order of the Central Government, any sum required to meet any public claim, there may be against him;

(b) any sum required to meet compulsory contributions to any provident fund, welfare fund or any other fund approved by the Central Government or to meet any debt that may be due from him towards any Security Guard institutions such as messes, canteens and the like.

Explanation:—(i) "Public Claim" means any public debt or disallowance including over-issue, or a deficiency or irregular expenditure of public money or store of which, after due investigation, no explanation satisfactory to the Central Government, is given by the person who is responsible for the same.

(ii) The aforesaid deductions shall be in addition to those specified in the Act.

177. Repeal and Savings.—(1) All rules and orders relating to the matters covered by these rules shall stand repealed in so far as they are inconsistent with any of the provisions of these rules.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the rules or orders so repealed shall, in so far as such thing or action is not inconsistent with the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the provisions of these rules as if the said provisions were in force when such thing was done or such action was taken and shall continue in force accordingly until superseded by anything done or any action taken under these rules.

178. Transitory provisions.—Any rule or order applicable to the Security Guard on the date these rules come into force will, unless repugnant to these rules, continue to apply unless and until abrogated or modified by the Central Government or any other competent authority.

APPENDIX I

(See rule 34)

Form of Delay Report

Confidential

No.
 Unit Address.....
 Date

To

.....

Subject : 1st, (2nd), (3rd), (4th) etc. Eight day delay report Pursuant to the NSG Act, section 57 and Rule 34.

1. No.....Rank.....Name.....
2. Offence.....
3. Date of Offence
4. Date offence was discovered
5. Date of (open/closed) arrest
6. Date of release to open arrest/release without prejudice to re-arrest (if.....not leased, reason).....
7. Record of evidence made on (if not recorded, reasons)
8. Application for trial made on
9. Date due to be tried.....
10. Reasons for delay

(COMMANDER)

Copy to :

1. Inspector-General (In the case of the (3th) and subsequent reports]
2. Director-General (Special report in case the accused is under close arrest for more than 3 months without a trial).

APPENDIX II

[See Rule 35(2) (b)]

| S No. | Date | Name of the Accused | Name of the Officer or Asstt. Comdr to whom request or representation made | Particulars of the request or representation | Order of the Commander | Signature & date of the Officer or Asstt. Comdr. who con- veys the orders of the Comman- der to the accus- ed | Remarks |
|----------|------|------------------------|---|--|---------------------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

APPENDIX III

(Rule 38)

Form use at summary proceedings of Rangers and Combatised Tradesmen under sec 51 of the National Security Guard Act.

OFFENCE REPORT

Unit.....

| Charges against No..... | | Rank..... | Name..... | | | | | | |
|-------------------------|---------|-----------|--------------------|---------|--------------------|--|--------------------------------|---------|--|
| Place & date of offence | Offence | Plea | Names of witnesses | Finding | Punishment awarded | Signature and designation of officer by whom awarded and date of award | Date of entry in conduct sheet | Remarks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

Signature of Commander of the Unit

Instructions :

- Col. 1. In cases of absence without leave/desertion, the "date of offence" will be first day of absence.
 Col. 2. The section and sub-section of the NSG Act under which the charge is preferred will be inserted above the statement of offence.
 Col. 4. An officer cannot deal summarily with a case in which he is the sole prosecution witnesses.
 Col. 6. Must be completed strictly in accordance with the heading

APPENDIX IV

(Rule 50(2))

Charge-Sheet

The accused, No.....(if applicable) Rank.....Name.....Unit..... is charged with

DISOBEYING THE LAWFUL COMMAND OF HIS SUPERIOR OFFICER

NSG Act

Sec 21(2)

in that he,

at.....on....., disobeyed the lawful command of his superior officer. Rank.....Name of.....
the same Unit, to turn out for roll call by not turning out.

Place.....

Date.....

A.B.
Commander.....NSG

To be tried by a General/Petty Security Guard Court.

Place.....

Date.....

Sd/-

Inspector General/Deputy Ins-
pector General

"When the sanction is accorded for the trial of the grave offences by Summary Security Guard Court (NSG Act Sec. 72(2), a similar entry should be made on the charge sheet.

APPENDIX V

(Rule 49)

Form of Application for a Security Guard Court

Unit :

Station :

Date :

19

Application for Security Guard Court

Sir,

I have the honour to submit charge(s) against No. Rank Name of the Unit under my command, and request you to accord/obtain sanction, of , that a Security Guard Court may be assembled for his trial at

The case was investigated by (a)

A Court of Inquiry was held on (b) date at (Station)

Presiding Officer Rank, Name and Unit Members

The accused is now at His general character is (c) I enclose the following documents (d).

1. Charge sheet (..... copies) (e)
2. Record or abstract of evidence original (f) & 5 copies.
3. Original exhibits (g)
4. Correspondence (g)
5. Statement as to character and the conduct sheet of the accused (g).
6. List of witnesses for the prosecution and defence (with their present address (g)).
7. Statement by accused as to whether or not he desires to have an officer assigned by the convening officer to represent him at the trial (Rule 62) (g).

Signature of Commander

(a) Here insert name of

- (i) Officer who investigated the charges
- (ii) Officer who made preliminary hearing into the case (rule 39)
- (iii) Officer who made the record of evidence (rule 45)

(b) To be filled in if there has been a Court of Inquiry respecting any matters connected with the charges; otherwise to be struck out (rule 57 (iii)).

(c) To be filled in by the Commander.

(d) Any items not applicable to be struck out

(e) One copy each to Presiding Officer, Judge Attorney (if any), members, Prosecutor and the accused.

(f) Original Record or abstract of Evidence to be sent to the Prosecutor.

(g) 3, 4, 5 and 6 to be returned to the Commander of the Unit of the accused with the notice of trial.

(h) 7 to be sent to the Presiding Officer.

APPENDIX VI

(Rule 59)

Forms as to Security Guard Court

Forms for Assembly of Security Guard Court General and Petty

Form of order for the Assembly of a General (or Petty) Security Guard Court under the National Security Guard Act, 1986:

Orders by

(Place.....Date.....)

No.

Rank

Name.....

.....

.....

The senior officer to sit as Presiding Officer.

Members

.....

.....

.....

Waiting Members

.....

.....

.....

Judge Attorney

..... is appointed Judge Attorney

Interpreter

..... is appointed Interpreter

Prosecutor

..... is appointed Prosecutor

*The accused will be warned, and all witnesses required to attend.

The proceedings (of which only two copies are required) will be forwarded to

Signed this.....day of.....

Convening Officer

* Any opinion of the Convening Officer with respect to the composition of the Court (See rule 58) should be added here, thus:- "In the opinion of the convening officer it is not practicable to appoint officers of different units".

" In the opinion of the convening officer, officers of equal or superior rank to the accused are not available having due regard to public service".

* Add here any order regarding Counsel. (See rule 59(g)).

APPENDIX VII

(Rule 102)

In exercise of the powers conferred on me by section 102 of the National Security Guard Act, 1986, I.....hereby order that

.....be delivered/paid to.....(be confiscated/destroyed).

Signature

(Confirming authority)

Place.

Date

734 GI/87 -11

APPENDIX VIII

(Rule 102 (8))

The finding and sentence of the General/Petty Security Guard Court held at.....(Place).....from.....day to.....day for the trial of the accused.....were promulgated to the accused by me at.....(place) on.....day of.....19.....

Extracts for Unit records have been taken/*No record has been kept of the finding and sentences.

Signature
(Commander)

Place.....

Date.....

*To be used in case of acquittal on all charges.

APPENDIX IX

(Rule 158)

Warrants Under Section 117 and 121 of the National Security Guard Act, 1986

FORM 'A'

Warrant of commitment for use when a prisoner is sentenced to imprisonment for life. (Sec. 117).

To

The Superintendent
of the (a).....Prison.

Whereas at a General Security Guard Court, held at.....on the.....day of.....,19..... (No. Rank..... Name..... Unit.....) was convicted of (the offence to be briefly stated here, as "desertion on active duty.").

And whereas the said General Security Guard Court on the.....day of.....19....., passed the following sentence upon the said (Name.....) that is to say

(Sentence to be entered in full, but without signature)

And whereas the said sentence had been duly confirmed by (b) as required by law (c).

This is to require and authorise you to receive the said (Name.....) into your custody in the said prison as by law is required, together with this warrant, until he shall be delivered over by you with the said warrant to the proper authority and custody for the purpose of undergoing the aforesaid sentence of imprisonment. The aforesaid sentence has effected from the (d).

Given under my hand at.....this theday of.....19.....

Signature (e)

(a) Enter name of civil prison.

(b) Name and description of confirming authority.

(c) Add if necessary "with a remission of.....".

(d) Enter date on which the original sentence was signed.

(e) Signature of Commander of the prisoner or other prescribed officer.

APPENDIX IX

(Rule 158)

FORM 'B'

Warrant of commitment for use when a prisoner is sentenced to imprisonment which is to be undergone in a civil prison (NSG Act Section 117).

To

The Superintendent
of the (a).....Prison.

Whereas at a (b).....Security Guard Court held at.....on.....the

.....day of19 (No.Rank.Name.
.....Unit.....) was duly convicted of (the offence to be briefly stated here, as "desertion",
'theft', 'receiving stolen goods', 'fraud', 'disobedience of lawful command' or as the case may be).

And whereas the said (b).....Security Guard Court on the.....day of.....

19 passed the following sentence upon the said (Name..... that is to say.....

(Sentence to be entered in full, but without signature)

And whereas the said sentence

(c) has been duly confirmed by (d) as required by law (e) is by law valid without confirmation.

This is to require and authorise you to receive the said (Name.....) into your custody together with the warrant and there carry the aforesaid sentence of imprisonment into execution according to law. The sentence has effect from the (f).....

Given under my hand at.....this the.....day of.....19

Signature (g)

(a) Enter name of civil prison

(b) General, Petty or Summary

(c) Strike out inapplicable words

(d) Name and description of confirming authority,

(e) Add if necessary 'with a remission of.....'

(f) Enter date on which the original sentence was signed.

(g) Signature of Commander of prisoner or other prescribed officer.

APPENDIX IX

(Rule 158)

FORM 'C'

Warrant for use when a sentence of imprisonment for life is reduced by superior authority to one of a shorter period, (Sec. 121).

To

The Superintendent
of the (a).....Prison.

Whereas (No.RankName.....(date) of the unit confined
in the (a).....prison under a warrant issued by (b) in pursuance of a sentence (c).....passed
upon him by a (d).....Security Guard Court held at.....on..... And whereas
(e).....has, in, the exercise of the power conferred upon him by the National Security Guard Act, passed the
following order regarding the aforesaid sentence : that is to say :- (f).....

This is to require and authorise you to keep the said (Name).....in your custody together with this warrant, in the said prison as by law is required until he shall be delivered over by you with the said warrant to the proper authority and custody, for the purpose of his undergoing the punishment of imprisonment under the aforesaid order. And this is further to require and authorise you to return to me the original warrant of commitment in lieu where of this warrant is issued.

The period of such imprisonment will reckon from the (g).

Given under my hand at.....this the.....day of.....19

(Signature (h))

(a) Enter name of civil prison.

(b) Enter name or designation of officer who signed original warrant.

(c) Enter original sentence (if this was reduced by the confirming officer or other superior authority the sentence should be entered thus :- "I life (imprisonment reduced by confirming officer to 10 years").)

(d) General.

(e) Name and designation of authority varying the sentence

(f) Order to be set out in full.

(g) Enter date on which original sentence was signed.

(h) Signature of prescribed officer.

APPENDIX IX

(Rule 158)

FORM 'D'

Warrant for use when prisoner is to be delivered into Security Guard Custody.

To

The Superintendent
of the (a).....Prison.

Whereas (No.RankName) (late) of the
Unit is confined in the (a).....prison under a warrant issued by (b).....in
pursuance of sentence of (c).....passed upon him by a (d).....Security Guard Court held
at.....on....., and whereas (e).....has, in exercise of the powers conferred
upon him by the National Security Guard Act passed the following order regarding the aforesaid sentence; that is to say (f).....

This is to require and authorise you to deliver forthwith the said (name) in your custody to the officer or Assistant
Commander bringing this warrant.

Given under my hand at this the.....day of19

Signature (g)

- (a) Enter name of civil prison.
(b) Enter name of designation of officer who signed original warrant.
(c) Enter original sentence (if this was reduced by the confirming officer or other superior authority the sentence should
be entered thus :- "2 years rigorous imprisonment reduced by confirming officer to 1 year".
(d) General, Petty or Summary.
(e) Name and designation of authority issuing the order.
(f) Order to be set out in full.
(g) Signature of prescribed officer.

APPENDIX X

[Rule 159(I)]

FORM 'A'

Warrant committing to civil prison custody a person sentenced to death.

To

The Superintendent
of the (a).....Prison.

Whereas a (b).....Security Guard Court held at.....on the.....day of
.....19 , (No.RankName) of the
Unit was convicted of.....(offence to be briefly stated)

And whereas the said (b).....Security Guard Court on the.....day of.....
19 , passed sentence of death by being hanged, on the said (NAME);
and the said sentence of death has been confirmed by the Central Government.

This is to require and authorise you to receive the said (Name).....into your custody and to carry out the
sentence of death on.....

Given under my hand at.....this the.....day of.....19 ,

Signature (c)

- (a) Enter name of civil prison.
(b) General.
(c) Signature of the Director General.

APPENDIX X

[Rule 159(2)]

FORM 'B'

Warrant to obtain person sentenced to death from civil custody in order to carry out such sentence.

To

The Superintendent
of the (a).....Prison.

Whereas (No.....Rank.....Name.....) (late) of the.....
Unit having been sentenced to suffer death on the.....day of is held in the said prison under a warrant by (c).

And whereas the said sentences having been duly confirmed by (d).....as by Law required an order to
carry out the said sentence has been issued to me (e).....(Name and Rank).....

This is to require and authorise you to deliver forthwith the said (Name).....to the officer/Assistant
Commander/Ranger Grade-I bringing this warrant.

Given under my hand at.....this day of.....19

Signature (f)

- (a) Enter name of civil prison.
- (b) General.
- (c) Enter name or designation or officer who signed original warrant.
- (d) Name and description of confirming authority.
- (e) Name and designation of the officer to whom the order is issued.
- (f) Signature of the officer by whom the order is issued.

APPENDIX XI

(Rule 160)

FORM 'A'

Warrant for use when the sentence of a person under sentence of death and committed to custody in a civil prison is
commuted to a sentence of imprisonment for life.

To

The Superintendent
of the (a).....Prison.

Whereas (No.....Rank.....Name.....) (late) of the.....
Unit is held in the (a).....Prison under a warrant issued by (b).....in pursuance of a sentence of
death passed upon him by (c).....Security Guard Court held at.....on.....and
whereas (d).....has, in exercise of the powers conferred upon him by the National Security Board Act passed the
following order regarding the aforesaid sentence :—
that is to say (e)

This is to require and authorise you to keep the said (Name).....in your custody together with
this warrant in the said prison as by law is required until he shall be delivered over by you with the said warrant to the
authority and custody for the purpose of his undergoing the punishment of imprisonment for life, under the said order. And
this is further to require and authorise you to return to me the original warrant of commitment in lieu where of this warrant is
issued. This period of such imprisonment for life will reckon from the (f)

Given under my hand at.....this the.....day of.....19

(Signature (g))

- (a) Enter name of Civil prison.
- (b) Enter name or designation of the officer who signed original warrant.
- (c) General
- (d) Name and designation of authority commuting the sentence.
- (e) Order to be set out in full.
- (f) Enter date on which original sentence was signed.
- (g) Signature of Commander.

APPENDIX XI

(Rule 160)

FORM 'B'

Warrant for use when the sentence of a person under sentence of death and committed to custody in a civil prison is commuted to a sentence of imprisonment to be served in the same prison

To

The Superintendent
of the (a).....Prison.

Whereas (No. Rank Name) (late) of the
Unit is held in the (a) Prison under a warrant issued by (b) in pursuance of a sentence of death passed upon
him by a (c) Security Guard Court held at on and whereas (d)
..... has in exercise of the powers conferred upon him by the National Security Guard Act, passed the
following orders regarding the aforesaid sentence, that is to say :—(e).....

This is to require and authorise you to keep the said (Name) in your custody together with this
warrant, and there to carry into execution the punishment of imprisonment under the said order according to law.

And this is further to require and authorise you to return to me the original warrant of commitment in lieu where of this
warrant is issued. This period of such imprisonment will reckon from the (f).....

Given under my hand at this the day of 19

Signature (g)

- (a) Enter name of civil prison.
- (b) Enter name or designation of officer who signed original warrant
- (c) General
- (d) Name and designation of authority commuting the sentence.
- (e) Order to be set out in full.
- (f) Enter date on which original sentence signed.
- (g) Signature of Commander.

APPENDIX XI

(Rule 160)

FORM 'C'

Warrant for use when a person who, after having been sentenced to death has been committed to custody
in a civil prison is to be delivered into the Security Guard Custody for a purpose other than carrying out
the sentence of death

To

The Superintendent of the (a).....Prison

Whereas (No. Rank Name) (late)
of the Unit is held in the (a) Prison under a warrant issued by
(b) in pursuance of sentence of death passed upon him by a (c)
Security Guard Court held at on and whereas (d)
has in exercise of the powers conferred upon him by the National Security Guard Act passed the following order
regarding the aforesaid sentence: that is to say (e).....

This is to required and authorise you to forthwith deliver the said (name)
to the officer/Assistant Commander or Ranger Grade I bringing this warrant.

Given under my hand at this the day of 19

Signature (g)

- (a) Enter name of civil prison.
- (b) Enter name or designation of officer who signed original warrant.
- (c) General.
- (d) Name and designation of authority issuing order.
- (e) Order to be set out in full.
- (f) Signature of Commander.

APPENDIX XI

(Rule 160)

FORM 'D'

Warrant for use when a prisoner is pardoned or his trial set aside, or when the whole sentence or the unexpired portion thereof is remitted (Section 121)

To

The Superintendent

of the (a).....Prison.

Whereas (No.....Rank.....Name.....) of the.....
(Unit is confined in the (a).....Prison under a warrant issued by (b).....in
pursuance of a sentence of (c).....passed upon him by a (d).....Security
Guard Court held at.....on.....and whereas (e).....has, in
exercise of the powers conferred upon him by the National Security Guard Act, passed the following order regarding
the aforesaid sentence, that is to say (f).....

This is to require and authorise you to forthwith discharge the said (Name).....
from your custody unless he is liable to be detained for some other cause, and for your so discharging him, this shall
be your sufficient warrant.

Given under my hand at.....this the.....day of.....19.....

Signature (g)

- (a) Enter name of civil prison.
- (b) Enter name or designation of officer who signed original warrant.
- (c) Enter original sentence (if this was reduced by the confirming officer or other superior authority the sentence should be entered thus :—
(2 years rigorous imprisonment reduced by confirming authority to 1 year).
- (d) General, Petty and (or) Summary.
- (e) Name and designation of authority pardoning prisoner, mitigating sentence or setting aside trial
- (f) Order to be set aside in full.
- (g) Signature of prescribed officer.

APPENDIX XII

[Rule 169(2)(a)(ii)]

Report on unnatural death

1. Place of death, or the place where dead body was found (give details)
2. Date and time at which information of death was received.
3. Name and description of two or more persons who identify the dead body.
4. Name and particulars of the deceased and his status.
5. Condition of clothes worn by the deceased.

Note :—In case, examination by Doctor is awaited, above details should be collected without removing the clothes etc. of the deceased, the other details should be completed after the Doctor's examination.

6. Conditions of limbs, eyes and mouth.
7. Expression of face.

8. Marks of struggle on the dead body if any, injuries and abrasions, should be recorded showing their size and location.

Note :—Depth of injury should be recorded but injuries should not be touched. If examination by Doctor is awaited the above information should be recorded after his examination.

9. Whether blood is fluid or coagulated. The place from which it came out and its quantity.
 10. By which means, weapon or instrument, the injury or marks of struggle appear to have been caused.
 11. Was any rope tied around the neck, or is there any marks of it being tied by anything.
 12. Was the rope or any other thing used to strangle or hang dead body, was, it strong enough to sustain the weight and whether its other end was tied to anything.
 13. Was any external article like grass etc., sticking to hairs or held in his hand or sticking to any other part of the body.
 14. Is the dead body that of a strong and well built man or is it that of a weak or old man.
 15. Is the dead body strong or weak or is it in decomposed state.
 16. Length of the dead body from head to feet.
 17. Identification marks and location and appearance of the wounds.
 18. Apparent cause of death.
 19. Is there any rumour or other circumstances showing that it is a case of suicide. Details of its articles found on the dead body or lying near it.
 20. Those found on the dead body (A slip will be affixed on each articles which will be stamped.)
 21. Those found lying near the dead body (a slip duly stamped will be affixed on each article).
- Description of the seal.
22. Map of the place where the dead body was found
Brief history of the case.

Place,

Date,

Signature of two or more respectable witnesses of the locality in whose presence investigation was carried out.

Signature of the officer investigating the case.

Name

Rank

APPENDIX—XIII

(Rule 175)

PART I

FORM I

Form for use at summary trials of officers and Assistant Commanders (Under Sections 53 & 54 of the Act)

Accused.....
 Rank and Name.....
 Unit.....

When the authority dealing summarily with the case decides (with the written consent of the accused) to dispense with the attendance of witnesses :—

Question to accused :—

1. Have you received a copy of the charge sheet and record or abstract of evidence or substance of evidence ?

Answer :

2. Have you had sufficient time to prepare your defence ?

Answer :

3. The charge sheet is read. Are you guilty or not guilty of the charge/s against you which you have heard/read ?

Answer :

If the accused pleads 'Not guilty' to any charge, the Record of Evidence or Abstract of Evidence or Substance of evidence, as the case may be, shall be read within the hearing of the accused and the minute recorded to that effect

4. Do you wish to make a statement ?

Answer :

If the accused desires to make a statement he should do so now. If at the conclusion of the hearing the authority dealing summarily with the case considers that the charge should not be dismissed, he is to examine the accused's record of service or conduct sheet. If the authority dealing summarily with the case proposes to award a punishment other than a reprimand, severe reprimand or penal deductions, he shall put the following question to the accused.

5. Do you elect to be tried by Security Guard Court or will you accept my award ?

Answer :

Finding.....
 AWARD.....
 STATION.....
 DATE.....

Note :—Oral statement of the accused made in answer to question 4 will not be recorded. If the accused has submitted a written statement such statement is only to be forwarded with or attached to this form when a copy of the Record or Abstract of evidence or substance of evidence is also required to be so forwarded or attached. This form will be kept with the service record of the officer/Assistant Commander.

APPENDIX—XIV

(Rule 175)

PART I

FORM II

Form for use at summary trials of Officers and Assistant Commanders (under Sections 53 & 54 of the Act).

Accused.....

Rank & Name

Unit.....

When the authority dealing summarily with the case does not decide to dispense with the attendance of witnesses or when the accused requires their attendance.

Question to accused :—

1. Have you received a copy of the charge sheet and the record or abstract of evidence or substance of evidence ?

Answer :

2. Have you had sufficient time to prepare your defence ?

Answer :

3. Are you guilty or not guilty of the charge/s against you which you have heard/read ?

The witnesses give their evidence accused being permitted to cross-examine.

4. Do you wish to make a statement ?

Answer :

5. Do you desire to call any witness ?

Answer :

The accused makes a statement and his witnesses give evidence. If at the conclusion of the hearing, the authority dealing summarily with the case considers that the charge should not be dismissed with, he is to examine the accused's record of service or conduct sheet. If the authority dealing summarily with the case proposes to award a punishment other than a reprimand, severe reprimand or penal deductions, he shall put the following question to the accused :—

6. Do you elect to be tried by Security Guard Court or will you accept my award ?

Answer :

FINDING

AWARD

STATION

DATE

Note :—Oral statement of the accused made in answer to question 4 will not be recorded. If the accused has submitted a written statement, such statement is only to be forwarded with or attached to this form when a copy of the Record or Abstract of evidence or substance of evidence is also required to be so forwarded or attached. This form will be kept with the service record of the Officer/Assistant Commander.

APPENDIX—XV

(Rules 45, 61 & 168)

Forms of summons to witnesses

a) In the case of a Record of Evidence.

Whereas a charge of having committed an offence triable by Security Guard Court has been preferred before me against No.....Rank.....Name.....Unit.....) and whereas I have directed a record of the evidence to be taken in writing at place)..... on the..... day of.....19.....at.....hours.

I do hereby summon and require you name) to attend as a witness at the said place and hour (and bring with you the documents hereinafter mentioned, namely.....).

Whereof you fail at your peril.

Given under my hand at.....on the.....day of.....19.....

(Signature)

Commander of the accused.

(b) In the case of a Security Guard Court.

Whereas a Security Guard Court has been ordered to assemble at.....on.....the day of.....19.....for the trial of.....of the.....Unit I do hereby summon and require you A. B. to attend as a witness before the said Court at.....on the.....day of.....19.....at hours (and to bring with you the documents hereafter mentioned, namely.....), and so to attend from day to day until you shall be duly discharged, whereof you shall fail at your peril said.

Given under my hand at.....on the.....day of.....19.....

(Signature)

Convening Officer (or Judge Attorney
or presiding officer of the Court or
Commander of the accused.)

(c) In the case of a Court of Inquiry.

Whereas a Court of Inquiry has been ordered to assemble at.....on the day of.....19.....to inquire into the circumstances under which..... I do hereby summon and require you A. B. to attend as a witness before the said Court of Inquiry at.....on the.....day of.....19.....at hours (and to bring with you the documents hereafter mentioned namely.....), and so to attend from day to day until you shall be duly discharged, whereof you shall fail at your peril.

Given under my hand at.....on the.....day of.....19.....

(Signature)

Presiding Officer or
Commander of the Unit
[No. K. 16011/3/86-NSG]
V. K. JAIN, Jr. Secy.

